अयोध्या विवाद कभी महज हिंदुस्तान का मामला नहीं रहा। यही वजह रही कि शनिवार को जब इस पर जब फैसला आया, तो दुनियाभर में ट्विटर पर प्रमुख 10 में से तीन, और भारत में सभी के सभी प्रमुख ट्रेंडिंग टॉपिक अयोध्या मसले पर थे। ग्लोबल स्तर पर प्रमुख अखबारों और वेबसाइट ने इस विवाद और सुप्रीम कोर्ट के इस पर फैसले को प्रमुखता से स्थान दिया।

सुप्रीम फैसला

संघ ने महज 35 वर्षों में आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाया

अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में मुहिम चलाने वाले आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद समेत अनेक संस्थाओं-संगठनों ने अपने-अपने स्तर पर योगदान दिया। एक तरफ आरएसएस ने अयोध्या के लिए आंदोलनों के जरिये इसकी जीवंतता बरकरार रखी। दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद भी दुनियाभर में अपने स्तर से समर्थन जुटाती रही।

नीलू रंजन • नई दिल्ली

लगभग 500 साल पहले की ऐतिहासिक भूल सुधारने में यूं तो लंबा वक्त लगा, लेकिन सच्चाई यह है कि अयोध्या में राममंदिर निर्माण का आंदोलन महज 35 साल पुराना है। हकीकत यह है कि 1984 के पहले अयोध्या में राम मंदिर निर्माण भाजपा, विहिप समेत पूरे संघ परिवार के एजेंडे में नहीं था। कभी मुरादाबाद से कांग्रेस विधायक रहे दाऊ दयाल खन्ना ने पहली बार 1983 में काशी, मथुरा और अयोध्या को मुक्त करने की जरूरत बताई और संघ परिवार ने चंद साल के भीतर इसे लेकर देशव्यापी आंदोलन खड़ा कर दिया।

1925 में अपनी स्थापना के बाद से ही संघ हिंदू पुनर्जागरण के उद्देश्य की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन पूरे हिंदू समाज को झकझोरने वाला मुद्दा नहीं मिल पा रहा था। गोरक्षा आंदोलन, भारत माता यात्रा जैसे मुद्दों का सीमित प्रभाव था। ऐसे में मुरादाबाद के कांग्रेसी विधायक रहे दाऊ दयाल खन्ना ने संघ को संजीवनी दे दी। 1983 में मुजफ्फरपुर में आयोजित हिंदुओं के एक सम्मेलन में दाऊ दयाल खन्ना ने अयोध्या, काशी और मथुरा को मुक्त कराने की जरूरत बताई। संयोग से उस सम्मेलन में आरएसएस के तत्कालीन सहकार्यवाह रज्जू भैया भी मौजूद थे। रज्जू भैया को बात जंच गई और उन्होंने एक साल पहले ही (1982) संघ से विहिप में भेजे गए अशोक सिंघल को दाऊ दयाल खन्ना से संपर्क करने को कहा। इसके बाद संघ परिवार ने इस मुद्दे पर बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करनी शुरू कर दी।

विहिप को सौंपी गई थी कमान : बारीकी से तैयार अयोध्या आंदोलन की बागडोर विहिप के हाथों में सौंपी गई और अशोक सिंघल इसके शिल्पी बने। मार्च 1984 में देशभर से साधु संतों को दिल्ली के विज्ञान भवन में जुटाकर धर्मसंसद का आयोजन किया गया और राम मंदिर आंदोलन पर उनकी सहमति जुटाई गई। शुरू में आंदोलन को सिर्फ ताला खुलवाने तक सीमित रखा गया और उसी साल 7 अक्टूबर से एक रामजानकी रथयात्रा भी निकाली गई, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के कारण यात्रा स्थगित करनी पड़ी। लेकिन अगले साल अक्टूबर में पूरे उत्तर प्रदेश में छह रामजानकी रथयात्राएं निकाली गईं। संघ को जरा भी अंदाजा नहीं था कि रथयात्राएं निकाले जाने के चंद महीनों के भीतर जन्मभूमि का ताला खुल जाएगा। वकील उमेश चंद्र पांडेय ने ताला खुलवाने के लिए फैजाबाद (अब अयोध्या) की अदालत का द्वार खटखटाया और अदालत के आदेश से एक फरवरी, 1986 को ताला खुल भी गया।

1986 में ताला खुलने के बाद शुरू हुई मंदिर निर्माण की तैयारी : 1986 से ही विहिप से जुड़े महासचिव चंपत राय ने साफ किया कि उमेश चंद्र पांडेय का विहिप या संघ परिवार से कोई लेना-देना नहीं था। लेकिन इतनी जल्दी ताला खुलने से संघ परिवार और आंदोलन से जुड़े साधु-संतों के हौसले बुलंद हो गए।

अयोध्या के लिए विहिप ने जारी रखी समर्थन जुटाने की कोशिश

अयोध्या आंदोलन शुरू होने के बाद से विहिप के तेवर लगातार बरकरार रहे। विहिप ने धर्म संसद, अयोध्या की पंचकोसी व चौदह कोसी परिक्रमा का आयोजन कर राम मंदिर के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश जारी रखी। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ठीक पहले विहिप ने पंचकोसी परिक्रमा का आयोजन कर विहिप ने तत्कालीन अखिलेश सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश की थी। इसी साल जनवरी में कुंभ के दौरान धर्म संसद बुलाकर सरकार पर अध्यादेश के जरिये राम मंदिर बनाने के लिए दबाव बनाने की कोशिश की थी।

भागवत बोले – हमारा काम आंदोलन का नहीं, इंसान का निर्माण

अरविंद पांडेय • नई दिल्ली

करीब 35 साल पहले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ खड़े होकर जिस तरह इसे हिंदुत्व और राष्ट्र की प्रतिष्ठा से जोड़ दिया था, वह बोझ शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उसके सिर से उतर गया है। यही वजह है कि फैसला आने के कुछ ही घंटों में संघ प्रमुख मोहन भागवत सामने आए और फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वह पूरी तरह संतुष्ट हैं। काशी-मथुरा को लेकर ऐसे ही आंदोलन के सवाल को टालते हुए उन्होंने कहा, 'हमारा काम आंदोलन का निर्माण करना नहीं है, बल्कि मनुष्य निर्माण करना है।'

दिल्ली के झंडेवालान स्थित संघ कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा में भागवत ने यह भी साफ किया, 'राम जन्मभूमि आंदोलन से संघ किन्हीं कारणों से अपवाद स्वरूप जुड़ा था जो फैसला आने के बाद खत्म हो गया है।' उन्होंने कहा, 'फैसले को हार या जीत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि पूरे समाज की एकात्मता और बंधुता के परिपोषण करने वाले निर्णय के रूप में देखना चाहिए। संघ वैसे भी इस पूरे विवाद का खात्मा चाहता था जो हो गया है। मै इससे संतुष्ट हूं।' भागवत ने कहा कि अब फैसला आ गया है तो मंदिर निर्माण का काम भी शीघ्र शुरू हो जाएगा। उनका मानना है कि फैसले के बाद सरकार अब विवाद को खत्म करने की दिशा में तेजी से काम करेगी। साथ ही अतीत की सभी बातों को भुलाकर साथ मिलकर राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण करना है।

झंडेवालान में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बोलते सरसंघचालक मोहन भागवत • जागरण

1984 के बाद संघ के एजेंडे में आया अयोध्या का मामला

- तत्कालीन कांग्रेस विधायक दाऊ दयाल ने रज्जू भैया की मौजूदगी में उठाया था मुद्दा

पूजित चबूतरे पर ही होगा मंदिर के गर्भगृह का निर्माण

संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने इस दौरान मंदिर निर्माण को लेकर अनौपचारिक चर्चा में बताया कि फिलहाल शुभ मुहुर्त देखकर जल्द ही इसका निर्णय किया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि मंदिर का जो गर्भगृह होगा, वह मौजूदा समय में पूजित चबूतरा की होगा।

इससे पहले संघ प्रमुख ने फैसला सुनाने वाले सभी न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं का स्वागत करते हुए कहा कि उनके धैर्यपूर्वक मंथन से ही यह सत्य और न्याय सामने आया है। राम जन्मभूमि न्यास और तराशे गए पत्थरों के सवाल पर भागवत ने कहा कि जैसे-जैसे बात आगे बढ़ेगी, वैसे-वैसे सब तय होगा, सारे रास्ते बनेंगे। संघ प्रमुख से जब पूछा गया कि यह विवाद आपसी बातचीत से भी सुलझ सकता था, इस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल हो सकता था। इसके लिए कई कोशिशें भी गईं थीं, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई।

अयोध्या में मस्जिद निर्माण पर संघ सतर्क, कहा-सरकार को लेना है फैसला मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए पांच एकड़ जमीन देने के फैसले पर भागवत ने सधी हुई टिप्पणी करते हुए कहा कि वह फैसले का अध्ययन करेंगे। वैसे भी जमीन कोई उन्हें नहीं देनी है। सरकार को इस पर फैसला लेना है। हालांकि यह भी बताया गया कि अयोध्या का मतलब अयोध्या जिला भी हो सकता है।

1987 में तैयार हो गया था नक्शा, शुरू हुआ भव्य मंदिर के लिए पत्थर तराशने का काम

चंपत राय के अनुसार 1987 में ही मंदिर का नक्शा बनकर तैयार हो गया और सही पत्थर के चुनाव के लिए चार खदानों के पत्थरों के नमूने जांच के लिए रुड़की स्थित सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में भेजे गए। उसने अपनी रिपोर्ट में राजस्थान के भरतपुर जिले के वंशी पहाड़पुर के गुलाबी सैंड स्टोन को मंदिर के लिए उपयुक्त करार दिया। इसके बाद पत्थर मंगाकर उन्हें तराशने का काम शुरू कर दिया गया।

भाजपा को मिला राजनीतिक लाभ

राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के शिल्पकार भले ही अशोक सिंघल रहे हों, लेकिन उसे जनआंदोलन बनाने का काम भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने किया। अपनी रथयात्राओं के माध्यम से उन्होंने इसे पूरे देश में राजनीतिक मुद्दा बना दिया। जाहिर है भाजपा को इसका लाभ भी मिला। 1984 में लोकसभा में दो सांसदों की पार्टी 1989 में 89 और 1991 में 120 सीटें जीतने सफल रही।

मुस्लिम विरोधी कभी नहीं था राम मंदिर आंदोलन

1992 में विवादित ढांचा टूटने की साजिश की जांच सीबीआइ कर चुकी है और मामला अभी भी अदालत में लंबित है। लेकिन संघ इसे रामजन्मभूमि स्थान पर बने विवादित ढांचे के खिलाफ जनाक्रोश का परिणाम मानता है। आरएसएस के वरिष्ठ नेता मनमोहन वैद्य कहते हैं कि अयोध्या आंदोलन किसी भी रूप में मुस्लिम विरोधी आंदोलन नहीं था। कारसेवकों का गुस्सा सिर्फ विवादित ढांचे तक सीमित था। आक्रोशित भीड़ के बीच भी एक अनुशासन को साफ देखा जा सकता था। उस दिन लाखों कारसेवकों ने अयोध्या में विवादित ढांचे को छोड़कर किसी अन्य धार्मिक स्थल को हाथ नहीं लगाया।

मामला चलता रहा, कभी नहीं रुकी मंदिर निर्माण के लिए पत्थरों की आपूर्ति

विवादित ढांचे का गिरना भाजपा के लिए भले झटका साबित हुआ हो और उसे चार राज्य सरकारों को गंवाना पड़ा हो, लेकिन विहिप और आरएसएस आगे की रणनीति की तैयारी में जुट गए। 1993 में प्रमुख साधु-संतों के नेतृत्व में रामजन्मभूमि न्यास का गठन कर उसे मंदिर निर्माण की तैयारी की जिम्मेदारी सौंप दी और अदालती लड़ाई की तैयारी में जुट गए। संघ ने यह सुनिश्चित किया कि अदालत में मुकदमा कहीं भी कमजोर नहीं पड़ने पाए। राम मंदिर निर्माण के लिए पत्थर तराशने का काम चलता रहा। चंपत राय के अनुसार 1989 के बाद उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कई सरकारें आईं-गईं, लेकिन मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या आने वाले पत्थरों की सप्लाई नही रुकी। इस बीच गोलियां भी चलीं, कर्फ्यू भी लगे, लेकिन पत्थरों की सप्लाई में कोई रुकावट नहीं आई। 2006 तक आते-आते 60 फीसद पत्थर आ गए और उनकी नक्काशी कराकर रख दिया गया।

विहिप ने कहा – फिलहाल काशी-मथुरा और अन्य धार्मिक स्थलों पर विचार नहीं

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : अयोध्या में राम मंदिर का आंदोलन खड़ा करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाली विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। साथ ही, केंद्र सरकार से मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जल्द से जल्द मंदिर निर्माण के संबंध में कदम उठाए। सद्भाव बनाए रखने पर जोर देते हुए परिषद ने स्पष्ट किया कि मथुरा और काशी के मुद्दे पर अभी कोई विचार नहीं किया जा रहा। वह अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और समाज के सांस्कृतिक जागरण के काम पर केंद्रित है। विहिप के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने पत्रकार वार्ता में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने न्याय और सत्य को एक बार फिर पुख्ता किया। पूरा देश बीत 70 वर्षों के न्यायिक संघर्ष के बाद निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा था। आखिरकार वह प्रतीक्षा पूर्ण हुई। हम सभी सुप्रीम कोर्ट के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। एक सवाल पर वह बोले कि मंदिर निर्माण के लिए इस्तेमाल होने वाली 60 फीसद शिलाएं तैयार हैं। आलोक कुमार ने कहा कि पुरातत्व सर्वेक्षण और तकनीकी विशेषज्ञ विशेष तौर पर बधाई के पात्र हैं जिनके कारण सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इस महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंच सके।

ट्विटर पर ट्रेंड रहा अयोध्या मामला

नई दिल्ली, एएनआइ : अयोध्या विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आने के बाद शनिवार को सोशल मीडिया पर भी जबर्दस्त हलचल देखने को मिली। सर्वोच्च अदालत की पांच सदस्यीय पीठ ने जैसे ही फैसला सुनाया, भारत समेत दुनियाभर में 'अयोध्या वर्डिक्ट', 'हिंदू-मुस्लिम भाई-भाई', 'राम मंदिर', 'बाबरी मस्जिद', 'मंदिर वहीं बनेगा' जैसे हैशटैग ट्रेंड होने लगे। हैशटैग 'अयोध्या वर्डिक्ट' से सबसे अधिक करीब पांच लाख ट्वीट हुए। दुनियाभर में ट्रेंड कर रहे शीर्ष 10 में तीन और भारत में सभी 10 प्रमुख हैशटैग अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही जुड़े थे।

सोशल मीडिया पर फैसले को सर्वधर्म स्वीकृति : सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सोशल मीडिया यूजर्स ने स्वागत किया है। कई लोगों ने इस फैसले को भारत की जीत बताते हुए आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, 'कभी-कभी ही ऐसे अवसर आते हैं जब हम अपने देश के लिए गौरव से भर उठते हैं। यह उन्हीं अवसरों में से एक है। मंदिर भी, मस्जिद भी। यह किसी पक्ष नहीं बल्कि भारत की एकता की जीत है।'

एक अन्य सोशल मीडिया यूजर ने फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए लिखा कि अब देश को पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। कुछ ने सर्वोच्च न्यायलय के फैसले का सम्मान करने और किसी भी तरह की अफवाहों पर विश्वास नहीं करने की बात की।

फैसले से पहले ही ट्रेंड हुआ 'हिंदू-मुस्लिम भाई-भाई' हैशटैग : वर्षों से विवादित जमीन पर फैसला आने से पूर्व ही हजारों सोशल मीडिया यूजर्स ने देश की एकता अखंड रखने और धार्मिक सौहार्द बनाए रखने से जुड़े ट्वीट व पोस्ट साझा करने शुरू कर दिए थे। शुक्रवार की रात से ही 'हिंदू-मुस्लिम भाई-भाई' हैशटैग भी ट्रेंड होने लगा था।

एक समारोह के दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और रिटायर्ड आएएएस योगेंद्र नारायण • जागरण आर्काइव

...और आखिरी ईंट गिरते ही कल्याण सिंह ने लिख दिया इस्तीफा

अजय जायसवाल • लखनऊ

दिनांक : छह दिसंबर, 1992
स्थान : पांच, कालिदास मार्ग, मुख्यमंत्री आवास

दृश्य : तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अपने कक्ष में वरिष्ठ मंत्रियों लालजी टंडन और ओमप्रकाश सिंह के साथ लंच कर रहे थे और टीवी चालू था। सभी देख रहे थे कि कारसेवक विवादित ढांचे पर चढ़ चुके हैं। वे गुंबद गिराने को कुदालें चला रहे थे। कल्याण सिंह के चेहरे पर चिंता की लकीरें तो थीं, लेकिन वे अधीर कतई नहीं थे। तभी तत्कालीन पुलिस महानिदेशक एसएम त्रिपाठी लगभग भागते हुए मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। मुख्यमंत्री से तुरंत मिलने की इजाजत मांगी, लेकिन सिंह ने भोजन तक इंतजार करने को कहा। भोजन के बाद बुलाया तो डीजीपी बोले कि कारसेवक विवादित ढांचे को तोड़ रहे हैं। फायरिंग की अनुमति चाहिए। सिंह ने पूछा- फायरिंग में कितने लोग मरेंगे? डीजीपी बोले- कारसेवकों ने विवादित स्थल को घेर लिया है। फायरिंग हुई तो बहुत लोग मारे जाएंगे। यह सुनते ही सिंह ने कह दिया कि आंसू गैस या लाठीचार्ज जैसे उपाय कर सकते हैं। लेकिन मैं फायरिंग की अनुमति नहीं दूंगा। लाइये, यह बात मैं कागज पर भी लिखकर दे दूं कि आपने गोली चलाने की अनुमति मांगी लेकिन मैंने नहीं दी। यह सुनकर डीजीपी लौट गए और सिंह टीवी पर देखते रहे कि कारसेवक ढांचे को ढहाते जा रहे थे। ...और आखिरी ईंट गिरते ही उन्होंने अपना मुख्यमंत्री वाला राइटिंग पैड मंगाकर इस्तीफा लिख डाला।

यह ऐतिहासिक वाकया वयोवृद्ध पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अब शायद इस तरह न सुना पाएं। लेकिन इस घटना के चश्मदीद रहे सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी योगेंद्र नारायण के कानों में एक-एक शब्द आज भी गूंज रहे हैं। नारायण उन दिनों कल्याण सिंह के प्रमुख सचिव थे। केंद्रीय रक्षा सचिव के पद से 2002 में सेवानिवृत हुए नारायण सूबे के मुख्य सचिव भी रहे। वर्तमान में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विवि के चांसलर योगेंद्र नारायण ने फोन पर 'दैनिक जागरण' के साथ यह संस्मरण साझा किया। वह दावे के साथ कहते हैं कि कल्याण सिंह जान-बूझकर विवादित ढांचा गिरवाना नहीं चाहते थे। लेकिन उस दिन हालात ऐसे बने कि उन्होंने कारसेवकों का खून बहने के बजाय ढांचे का ढह जाना उचित समझा।

नरसिम्हा राव की बात सुन हैरान थे कल्याण : नवंबर, 1992 के अंत में कल्याण सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा से मिलने दिल्ली पहुंचे। उनसे मुलाकात के बाद बोले - 'आज तो अजीब ही बात सामने आई। नरसिम्हा जी ने बताया है कि विवादित ढांचे के नीचे मंदिर के अवशेष मिले हैं।' हालांकि, इसके पीछे कल्याण सिंह क्या सोच रहे थे, इसे कुछ स्पष्ट नहीं किया।

विदेशी मीडिया में भी छाया रहा फैसला

जेएनएन, नई दिल्ली : राम जन्मभूमि से जुड़े भूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला शनिवार को पूरी दुनिया में सुर्खियां बना। इस फैसले को विश्व के कई मुख्य अखबारों और न्यूज चैनलों ने वरीयता दी। कोर्ट के फैसले और विवाद की विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने फैसले पर अपना रुख भी स्पष्ट किया।

अमेरिका के प्रमुख अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने 'सुप्रीम कोर्ट ने भारत में सबसे विवादित भूमि पर मंदिर बनने का रास्ता किया साफ' हेडिंग से खबर दी। अखबार ने लिखा, 'भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए विवादित भूमि पर मंदिर बनने का रास्ता साफ कर दिया है। मुस्लिम पक्ष को अलग से पांच एकड़ भूमि देने का भी आदेश दिया गया है।' एक अन्य अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि भारतीय कोर्ट ने अयोध्या विवाद में हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया।

ब्रिटेन के प्रमुख अखबार द गार्जियन ने भी इस फैसले को विस्तृत कवरेज दी। 'अयोध्या फैसला : विवादित जमीन पर हिंदू पक्ष ने जीता केस' को सुर्खी बनाने के साथ अखबार ने अदालत द्वारा मुस्लिम पक्ष को पांच एकड़ जमीन दिए जाने की बात को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अखबार गल्फ न्यूज ने 'हिंदुओं को विवादित और मुस्लिमों को वैकल्पिक जमीन' से अपनी खबर की हेडिंग दी।

कतर स्थित न्यूज चैनल अल जजीरा ने भी अपनी वेबसाइट में कई खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद की विस्तृत जानकारी देते हुए अलग से भी एक खबर दी गई है। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन ने विवादित भूमि हिंदुओं और मुस्लिमों को वैकल्पिक भूमि देने वाली बात को अपनी सुर्खी बनाया। डॉन ने फैसले के उस बिंदु का भी जिक्र किया है, जिसमें पांच सदस्यीय पीठ ने विवादित ढांचा गिराए जाने की बात स्वीकारी थी। पाकिस्तान के कई अखबारों ने इस फैसले के खिलाफ खुलकर लिखा है।

बांग्लादेश में शांति, भारत में भी अमन की उम्मीद

ढाका, प्रेट्र : बांग्लादेश ने कहा है कि अयोध्या मामले पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक आदेश का वह अध्ययन करेगा। विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमिन ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि भारतीय कोर्ट के फैसले से उनके देश में तनाव पैदा नहीं होगा, कानून व्यवस्था के लिए कोई मुश्किल पैदा नहीं होगी। एक खेल प्रतियोगिता के उद्घाटन में आए मोमिन ने कहा, बांग्लादेश में अयोध्या के फैसले से कोई तनाव नहीं है। देश का भाईचारा और आपसी सद्भाव हमें शांति बनाए रखने में मदद करेगा। देश में मुस्लिम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध पूरे सौहार्द के साथ रह रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि भारत में भी शांति बनी रहेगी। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी मुस्लिम बहुल देश है। मोमिन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अध्ययन के बाद बांग्लादेश उस पर अलग से प्रतिक्रिया देगा।

पाक को लगी मिर्ची

इस्लामाबाद, प्रेट्र : अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पाकिस्तान को इससे मिर्ची लग गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अयोध्या पर फैसले के समय पर सवाल उठाते हुए कहा है कि करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर आए इस फैसले से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है। करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन खुशी का मौका था। लेकिन भारत ने इस पर पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

पाकिस्तान के अन्य नेताओं और सेना ने भी कमोबेश ऐसी ही प्रतिक्रिया व्यक्त की है। डॉन न्यूज टीवी को दी प्रतिक्रिया में कुरैशी ने कहा, 'इस फैसले के लिए क्या कुछ दिन और इंतजार नहीं किया जा सकता था। इसने खुशी के मौके को दुख वाला दिन बना दिया।' पाकिस्तान के विज्ञान एवं तकनीक मामलों के मंत्री फवाद चौधरी ने भारतीय कोर्ट के फैसले को अवैध और अनैतिक बताया है।

फिल्मी सितारों ने किया स्वागत, एकजुट होकर आगे बढ़ने का किया आह्वान

एंटरटेनमेंट ब्यूरो, मुंबई

फिल्मी हस्तियों ने अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। मधुर भंडारकर, तापसी पन्नू, विवेक आनंद ओबेराय समेत कई सितारों ने फैसले का स्वागत करते हुए शांति, एकता और सौहार्द बनाएं रखने की अपील की है।

फिल्म निर्माता फरहान अख्तर ने ट्वीट में लिखा, 'आप सबसे निवेदन है कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आदर करें। अब हम लोगों को एक होकर आगे बढ़ने की जरूरत है। जय हिंद।' हुमा कुरैशी ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'प्रिय भारतवासियों, अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करें। हम सभी को एक साथ मिलकर एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने की जरूरत है।' विवेक आनंद ओबराय ने महात्मा गांधी की तस्वीर उनके कथन के साथ पोस्ट करते हुए सभी से यह अपील की कि देश में शांति व्यवस्था बनाएं रखें और आपस में एकता बनाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सीख का सम्मान करें।

> सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हमें दिखा दिया कि हम सब किस तरह शांतिपूर्वक एक साथ रह सकते हैं। यही हमारे महान देश की खूबसूरती है। मैं सभी से अनुरोध करती हूं कि हमारे अनेकता में एकता की मिसाल कायम रखे।
>
> – टीम कंगना रनोट

> वक्त लगता है पर हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने रामजन्म भूमि पर फैसला सुनाया है। फैसले का सम्मान करें। फैसले को स्वीकार करें और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का राजनीतिक फायदा या टीआरपी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने वाले लोगों को नजरंदाज करें। यह वास्तव में आगे बढ़ने का समय है।
>
> – हंसल मेहता

धारावाहिकों की शूटिंग पर नहीं पड़ा असर : फैसले के मद्देनजर टीवी शो की शूटिंग के बाबत सिने और टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (सिंटा) के संयुक्त महासचिव अमित बहल ने बताया कि शुक्रवार की रात को ही पता चल गया था कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे। फैसला सुबह 10.30 बजे आने वाला था। कलाकार उससे पहले सेट पर पहुंच जाते हैं। ज्यादातर स्टूडियो में सुरक्षा वैसे भी सख्त होती है। फिल्म सिटी से लेकर दूसरे किसी भी स्टूडियो में कोई अलग से सिक्योरिटी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। डबिंग स्टूडियो का काम भी सुचारू रूप से जारी रहा। डेली सोप 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के निर्माता राजन शाही ने बताया,' हमारे शो के सेट पर काम नियमित दिनों की तरह हुआ। हमारी इंडस्ट्री की खासियत ही यही है कि यहां एकता और समानता है। यहां पर हर धर्म की इज्जत की जाती है। सब साथ में काम और मेहनत करते हैं। काम और इंसान की इज्जत की जाती है। यह गर्व की बात है कि टीवी इंडस्ट्री पर धर्म या राजनीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

भाखरवड़ी शो के निर्माता जेडी मजीठिया ने कहा, 'हमारे सेट पर शांतिपूर्ण तरीके से काम जारी रहा।

राम की ननिहाल छत्तीसगढ़ में खुशी का माहौल

नईदुनिया, रायपुर

- सरकार भी फैसले को लेकर थी निश्चिंत, बच्चों को इतिहास का गवाह बनने की छुट्टी

छत्तीसगढ़ भगवान राम की ननिहाल के रूप में पहचान रखता है। अयोध्या मामले में कोर्ट का फैसला आने के बाद छत्तीसगढ़ में खुशी का माहौल देखने को मिला। सभी वर्गों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए सौहार्द का रस घोला। राजनीतिक दल के नेता हो, या फिर सामाजिक कार्यकर्ता, सभी कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नजर आए। सरकार भी कोर्ट के फैसले को लेकर निश्चिंत नजर आ रही थी। जब अन्य राज्यों में स्कूलों और कालेज को सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर बंद किया गया, तो छत्तीसगढ़ में सरकार ने बच्चों को इतिहास का गवाह बनते देखने के लिए स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की।

हर वर्ग की नजर सुबह साढ़े दस बजे से टीवी की स्क्रीन पर टिक गई थी। सड़कों पर सन्नाटा था और लोगों में कोर्ट के फैसले को लेकर उत्सुकता थी। पुलिस ने भी प्रदेशभर में पूरी तैयारी की थी। कलेक्टर से लेकर एसपी ने सोशल मीडिया को लेकर अलर्ट जारी किया। सभी ने एकजुटता दिखाते हुए सोशल मीडिया के ग्रुप को एडमिन पोस्ट मोड में कर दिया। प्रदेश में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि किसी भी मुद्दे पर हर वर्ग एकराय होकर सहमति जता रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में श्रीरामजन्मभूमि पर भगवान रामलला को विराजमान कर मंदिर बनाने के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय के सर्वसम्मत फैसले का स्वागत किया है। पार्टी ने इसे सर्व धर्म समभाव की भावना से अनुप्राणित राष्ट्र-जीवन की विजय बताया है। कांग्रेस ने भी अपने दिल्ली कूच के कार्यक्रम को रद करने की घोषणा की। कांग्रेस, भाजपा और जकांछ ने अपने कार्यकर्ताओं से एक दिन पहले ही अपील की थी कि कोर्ट का जो भी फैसला हो, उसे स्वीकार करना है। आला नेताओं की निर्देश पर पार्टी के कार्यकर्ता भी सधे अंदाज में बयान देते नजर आए।

रायपुर के चंदखुरी में है माता कौशल्या का मंदिर : राजधानी रायपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर चंदखुरी में माता कौशल्या का मंदिर है। आम मान्यता है कि कौशल्या माता का यह मायका है। राम के ननिहाल होने के कारण राजधानी में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कहा था कि भगवान राम के ननिहाल में मंदिर का निर्माण हो गया है, तो अब अयोध्या में भी मंदिर बनने से कोई रोक नहीं सकता है।

ड्यूटी से लापता रहने पर पांच मजिस्ट्रेट को प्रतिकूल प्रविष्टि

जासं, रामपुर : अयोध्या मामले में फैसले के बाद जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह ने जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती करते हुए क्षेत्रवार भ्रमण किया था। इस संबंध में आयोजित बैठक के दौरान स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बावजूद एक जोनल मजिस्ट्रेट एवं चार सेक्टर मजिस्ट्रेटों की लापरवाही सामने आई है।

जिलाधिकारी ने बताया कि एआइजी स्टांप अशोक कुमार, सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में जिम्मेदार सब-रजिस्ट्रार भरत कुमार जमुनानी, एफएसओ अशोक कुमार मिश्र, सब रजिस्टार करुणेश वर्मा तथा जेई पीडब्ल्यूडी सूरजभान अपनी ड्यूटीस्थल से गैरहाजिर रहे।

फैसले में पुरातत्ववेत्ता की गवाही शिलालेख भी

संदीप तिवारी, रायपुर

- भगवान श्रीराम के ननिहाल छत्तीसगढ़ निवासी पद्श्री डॉ. अण शर्मा रहे हैं गवाह
- एएसआइ टीम का हिस्सा रहे हैं डॉ. शर्मा

अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दौरान जो तथ्य सबसे मजबूत आधार बने,उसमें छत्तीसगढ़ की अहम भूमिका रही है। भगवान श्रीराम का ननिहाल कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रहने वाले पुरातत्ववेत्ता और खुदाई दल के सदस्य पद्श्री डॉ.अण कुमार शर्मा इस प्रकरण में मुख्य गवाह रहे। अयोध्या में भगवान राम की ही जन्मभूमि है इसके लिए डॉ. अण शर्मा ने कोर्ट में चार प्रमाण दिए थे। पहला खोदाई में मिला शिलालेख से पता चलता है कि गहरवाल राजा ने राम मंदिर का निर्माण करवाया था। दूसरा मंदिर तोड़ा गया और मस्जिद बनाने के लिए मंदिर की ही नींव को उपयोग में लाया गया था। तीसरा मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, लेकिन मस्जिद के चार कोनों में चार मीनारें होना आवश्यक है, वह नहीं थी। बजू टैंक भी नहीं पाया गया और चौथा बाबर कभी अयोध्या नहीं आया, उसका सेनापति आया था। जिस मस्जिद की बात कही जा रही है, उसकी दीवारों पर मूर्तियां जड़ी हुई हैं। इसमें 84 पिलर पाए गए हैं।

मिला था सात सौ साल पुराना शिलालेख : उन्होंने बताया कि मैंने टीम के साथ कहा था कि 'राम जन्मभूमि में खुदाई करके भी देखा जा सकता है। कोर्ट ने खुदाई के लिए इजा

दैनिक जागरण
धैर्य का फल सदैव सुखद एवं मधुर होता है

सर्वोच्च निर्णय

स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे बहुप्रतीक्षित, महत्वपूर्ण और निर्णायक सिद्ध होने वाला निर्णय आखिरकार आ गया। जो निर्णय आया उसकी प्रतीक्षा दशकों से नहीं, सदियों से की जा रही थी। यह निर्णय करोड़ों-करोड़ लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप ही है। अयोध्या के विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण को प्रशस्त करने वाले इस सर्वोच्च निर्णय की अपेक्षा केवल इसलिए नहीं की जा रही थी कि भारतीय समाज के एक बहुत बड़े वर्ग की यह मान्यता थी कि अयोध्या का विवादित स्थल राम की जन्मभूमि है, बल्कि इसलिए भी की जा रही थी कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक महत्व के प्रमाण इसी ओर संकेत कर रहे थे कि राम मंदिर के स्थान पर मस्जिद का निर्माण किया गया। यह मस्जिद को दिए गए नाम बाबरी से ही नहीं, विवादित ढांचे के आसपास बने अनेक मंदिरों से भी स्पष्ट होता था। हिंदू समाज मंदिर की जगह मस्जिद के निर्माण के बाद से ही इस पवित्र स्थल पर न केवल अपना दावा कर रहा था, बल्कि उस पर अपना अधिकार पाने के लिए हर संभव तरीके से प्रयत्न भी कर रहा था। इसके दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध हैं कि ये प्रयत्न लगभग पांच सौ साल से हो रहे थे। विवादित ढांचे के ध्वंस के बाद ऐसे कुछ और साक्ष्य सामने आए जिन्होंने मंदिर के स्थान पर मस्जिद के निर्माण को पुष्ट किया, लेकिन संकीर्ण राजनीतिक कारणों से उनकी अनदेखी की गई। ऐसा इस तथ्य से भली तरह अवगत होने के बाद भी किया गया कि राम इस देश में रचे-बसे हैं और अयोध्या की तो पहचान ही राम की नगरी के रूप में है। राम केवल हिंदू समाज के आराध्य ही नहीं, राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना के प्रेरणा पुरुष भी हैं। यदि समय रहते यह समझा जाता कि राम के बिना भारतीय मानस की कल्पना ही नहीं की जा सकती और अयोध्या के विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण को सहर्ष सहमति दी जाती तो उससे परस्पर सद्भावना का ऐसा संचार होता जिसकी अनुभूति पूरा देश करता। ऐसी स्थिति में एक मिसाल कायम होती जो देश ही नहीं, दुनिया को भी प्रेरणा देने का काम करती। दुर्भाग्य से एक महान अवसर गंवा दिया गया। इस पर अफसोस जताने के साथ ही यह समझा जाना चाहिए कि ऐसा किन कारणों से हुआ ताकि भविष्य के लिए सबक सीखा जा सके। यह अच्छा-बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ कि आक्रमणकारी बाबर को राम के बराबर खड़ा करने की कोशिश की गई और इस क्रम में यहां तक पूछा गया कि इसके क्या प्रमाण हैं कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ था?

अब उचित यही है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की अभिलाषा राष्ट्रीय आकांक्षा का रूप ले और उसमें सभी की सहमति शामिल हो

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सबको स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि इससे ही उस सद्भाव की पूर्ति होगी जिसकी देश को आवश्यकता है। इससे इन्कार नहीं कि इस फैसले से कुछ लोगों को मायूसी होगी, लेकिन कोई भी समाज हो वह नियम-कानूनों से ही चलता है और ऐसा कोई फैसला नहीं हो सकता जो सबको समान रूप से संतुष्ट कर सके। चूंकि सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी कोई अदालत नहीं इसलिए उसके फैसले को स्वीकार करने के अलावा और कोई उपाय भी नहीं। अब उचित यही है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की अभिलाषा राष्ट्रीय आकांक्षा का रूप ले और उसमें सभी की सहमति शामिल हो। यह मंदिर एक ऐसी साझा सांस्कृतिक धरोहर बनना चाहिए जो उन मूल्यों और मर्यादाओं का प्रतिनिधित्व करे जिनके संदर्भ में रामराज्य का उल्लेख किया जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाने वाले राम किसी एक समुदाय या वर्ग तक सीमित नहीं किए जा सकते। इसका सबसे बड़ा प्रमाण रामराज्य की कल्पना साकार होने की कामना है। यह कामना और बलवती होनी चाहिए और इसमें सभी को भागीदार बनना चाहिए। इससे ही अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर की भव्यता और महत्ता स्थापित होगी। राम मंदिर के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने के साथ ही अयोध्या में मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण के लिए जो पांच एकड़ जमीन दी गई उसके प्रति भी सभी की सहमति होनी चाहिए। यह सहमति व्यक्त करने के साथ-साथ यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के आधार पर निर्णय नहीं दिया, लेकिन उसने आस्था की अनदेखी भी नहीं की। शायद इसीलिए उसने यदि रामलला को विवादित स्थल सौंपा तो मस्जिद के लिए भी भूमि उपलब्ध कराने का आदेश दिया। स्पष्ट है कि न्याय केवल हुआ ही नहीं, बल्कि होते हुए दिखा भी है। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही एक अभिलाषा पूरी हुई, लेकिन अभिलाषाएं और भी हैं और वे सब तब पूरी होंगी जब राष्ट्रीय एकजुटता और समरसता को राम का काज समझा जाएगा। यह समय हर्ष-विषाद का नहीं, बल्कि संतोष भाव के साथ राम मंदिर के साथ-साथ राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य को पूरा करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का है। ऐसा करते हुए यहध्यान रखना ही होगा कि सबका कल्याण ही रामराज्य की संकल्पना है।

नया इतिहास लिखने वाला फैसला

संजय गुप्त

उच्चतम न्यायालय के फैसले के साथ ही अयोध्या विवाद को लेकर हो रही राजनीति का पटाक्षेप तो होना ही चाहिए, हिंदू-मुस्लिम समाज के बीच की दूरियों को भी खत्म किया जाना चाहिए

जिस फैसले की प्रतीक्षा पूरा देश दशकों से नहीं, बल्कि सदियों से कर रहा था वह आखिरकार उच्चतम न्यायालय की ओर से सुना दिया गया। यह सचमुच एक नए इतिहास का निर्माण करने वाला फैसला है। यह नया इतिहास लिखने की जिम्मेदारी भारत के सभी लोगों की है। इस जिम्मेदारी का निर्वाह न्याय के प्रति सम्मान भाव प्रकट करने से ही हो सकेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने अयोध्या मामले का पटाक्षेप कर एक नया अध्याय लिखने का काम किया है। इसीलिए उसका फैसला मील का पत्थर है। इस फैसले के लिए संविधान पीठ को भी बधाई दी जानी चाहिए। अपने इस ऐतिहासिक निर्णय में देश की शीर्ष अदालत ने विवादित स्थल पर मंदिर निर्माण के पक्ष में आदेश दिया। इसके साथ ही उसने मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या में ही किसी स्थान पर पांच एकड़ जमीन आवंटित करने का भी निर्देश दिया। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को इसका जिम्मा सौंपा है कि वह तीन महीनों में एक ट्रस्ट बनाकर मंदिर निर्माण के लिए उचित कार्ययोजना तैयार करे। इस निर्णय ने हिंदू समाज की आशा पूरी कर उसे उत्साहित किया है, लेकिन उसे उत्साह के स्थान पर संतोष भाव प्रदर्शित करना चाहिए। उसे सामाजिक सद्भाव की न केवल चिंता करनी होगी, बल्कि उसे हर हाल में बनाए रखना होगा। उत्साह या असहमति के चलते ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जिससे देश का माहौल बिगड़े। वास्तव में यह सभी का दायित्व है कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि देश का सामाजिक तानाबाना सुरक्षित रहे। यह इसलिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए, क्योंकि राम सबके हैं और सबका कल्याण ही उनके जीवन का ध्येय था। इसी के लिए वह जाने जाते थे और इसीलिए सबके मन में बसे थे।

स्वतंत्रता के पहले की तरह स्वतंत्रता के बाद भी अयोध्या विवाद को सुलझाने की कोशिश हुई, लेकिन वह सफल नहीं हुई। सदियों पुराना अयोध्या विवाद समय के साथ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विवाद के रूप में तब्दील हो गया और उससे सामाजिक सद्भाव को क्षति पहुंची। यह क्षति इसलिए पहुंची कि अयोध्या में मंदिर-मस्जिद के कुछ पैरोकारों ने इस विवाद को वोट बैंक आधारित राजनीति का प्रश्न बना दिया। विडंबना यह रही कि उन्होंने इस विवाद को आपसी बातचीत और सहमति से सुलझाने की कोशिश ईमानदारी से नहीं की। वास्तव में इसीलिए यह विवाद लंबे समय तक उलझा रहा। 1992 में विवादित ढांचे के ध्वंस के बाद इस विवाद को नए सिरे से सुलझाने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन वह भी सही तरह से आगे नहीं बढ़ सकी। निःसंदेह अयोध्या के विवादित ढांचे को जिस तरह गिराया गया वह ठीक नहीं था। इस ध्वंस से मुसलमान आक्रोशित हुए।

अवधेश राजपूत

यह आक्रोश इसलिए उपजा, क्योंकि मुस्लिम समाज को यह बताकर गुमराह किया गया कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर की जगह नहीं बनाई गई थी। इसीलिए यह जिद सही नहीं थी कि जहां पर ढांचा था वहीं पर मस्जिद बने। इस जिद का इसलिए भी कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि इस्लामी मान्यताएं यही कहती हैं कि झगड़े की जमीन पर बनी मस्जिद पर नमाज मंजूर नहीं होती।

2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जब इस विवाद पर अपना फैसला सुनाया तो उसे किसी पक्ष ने स्वीकार नहीं किया। वास्तव में इस फैसले से किसी का भी भला नहीं हो रहा था। विवादित जमीन को तीन हिस्सों में बांटकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किसी पक्ष को संतुष्टि नहीं प्रदान की थी, लेकिन इस फैसले ने विवाद सुलझाने की आधारशिला रखी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआइ ने विवादित स्थल का उत्खनन कर जो साक्ष्य जुटाए उन्होंने यह साबित किया कि मस्जिद का निर्माण खाली जमीन पर नहीं किया गया और वहां मंदिर के अवशेष मिले। ये साक्ष्य इस मान्यता के अनुरूप थे कि विवादित स्थल पर राम मंदिर था, जिसके स्थान पर बाबर के सेनापति ने जबरन मस्जिद का निर्माण कराया। एएसआइ के उत्खनन अभियान का हिस्सा रहे केके मुहम्मद ने बार-बार यह कहा कि विवादित स्थल पर प्राचीन मंदिर होने के प्रमाण मिले थे, लेकिन उनकी अनदेखी की गई। इतना ही नहीं एएसआइ की रपट को खारिज करने की भी कोशिश की गई। ऐसा नहीं किया जाता तो शायद विवाद पहले ही सुलझ जाता।

इसमें किसी को कोई संदेह नहीं हो सकता कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ। चूंकि अयोध्या राम के नाम से ही दुनिया भर में अपनी पहचान रखती है इसलिए ऐसे तर्क उकसाने वाले ही थे कि इसके क्या प्रमाण कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ? अफसोस यह रहा कि देश के तमाम इतिहासकार और राजनेता एक लंबे अर्से तक यह दावा करते रहे कि अयोध्या में राम मंदिर पर हिंदू समाज का कोई दावा नहीं बनता। इस दावे को खारिज करने के लिए तमाम मनगढंत बातें कही गईं। उच्चतम न्यायालय में 40 दिन की सुनवाई के दौरान भी कुछ पैरोकार राम मंदिर के विरोध में थोथी दलीलें देते रहे। वे जोर दे रहे थे कि यहां मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था। चूंकि उनके तर्क बेतुके और हास्यास्पद थे इसीलिए उच्चतम न्यायालय ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। अब जब उच्चतम न्यायालय ने आस्था नहीं, बल्कि साक्ष्यों के आधार पर यह पाया कि अयोध्या के विवादित स्थल पर हिंदू पक्ष का दावा सही साबित होता है तब फिर सभी को उसके फैसले को स्वीकार करना चाहिए। यह ठीक नहीं कि जब करीब-करीब सभी राजनीतिक दल और यहां तक कि सुन्नी वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार कर रहा है तब फिर ओवैसी जैसे नेताओं को कोई बखेड़ा करने से बचना चाहिए। यह स्वागतयोग्य है कि चंद लोगों और वह भी ओवैसी जैसे सांप्रदायिक राजनीति करने वाले नेताओं को छोड़कर आम मुस्लिम समाज इस फैसले को स्वीकार करता दिख रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि हिंदुओं की ओर से भी इस फैसले को जीत के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। यही सही तरीका है।

यह समय आगे बढ़ने का और सद्भाव को पुष्ट करने का है। अब कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के साथ अयोध्या विवाद को लेकर हो रही राजनीति का भी पटाक्षेप हो। केवल इतना ही नहीं, हिंदू-मुस्लिम समाज के बीच जो भी दूरियां हैं उन्हें कम करने की कोशिश हो। यह कोशिश दोनों ही पक्षों की ओर से होनी चाहिए। ऐसा करते हुए एक-दूसरे की भावनाओं का आदर किया जाना चाहिए, क्योंकि यही भारतीय परंपरा है और इससे ही देश आगे बढ़ेगा।

response@jagran.com

अयोध्या से आगे की राह

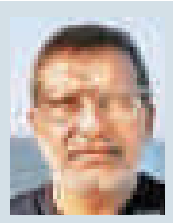

शंकर शरण

विविध मतावलंबियों के संबंध सभी पक्षों द्वारा किन्हीं समान सिद्धांतों का सम्मान करके ही सद्भावपूर्ण बनाए जा सकते हैं

भारत में मंदिर सदैव सद्भाव और सामंजस्य बनाने की कड़ी रहे हैं। यह भी स्मरण रहे कि यहां मस्जिदों और गिरिजाघरों को बनाने का कभी विरोध नहीं हुआ तो अब मंदिर के लिए भी नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी द्वारा खुले दिल से स्वागत करके एक नए युग का आरंभ करना चाहिए। आखिर, सदियों की प्रतीक्षा, आश्वासनों और संघर्ष के बाद अयोध्या में रामजन्मभूमि पर पुनः मंदिर बनने का मार्ग बना। इसके लिए हिंदुओं ने जो धैर्य दिखाया वह विश्व इतिहास में अभूतपूर्व है। किसी अन्य धर्मावलंबी समुदाय ने कभी कहीं इतना संयम दिखाया हो, ऐसा उदाहरण दुनिया में नहीं मिलता। अयोध्या एक अति-विशिष्ट स्थान है। इसका उल्लेख वेदों में भारत के सात सबसे पवित्र स्थानों में है। इक्ष्वाकु वंश की राजधानी के रूप में अयोध्या का सम्मान केवल हिंदू ही नहीं, बौद्ध, जैन और सिख परंपराओं में भी रहा है। स्वयं गौतम बुद्ध ने खुद को राम का वंशज कहा था। विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में सरयू नदी का वर्णन तीन सबसे पावन नदियों में से एक के रूप में रहा है। अयोध्या श्रीराम के पहले से ही सूर्यवंश के महान शासकों की राजधानी रही थी। दो हजार वर्ष पहले कोरिया की रानी सूरीरत्ना (सूर्यरत्ना) को भी मूलतः अयोध्या की ही राजकुमारी माना जाता है। इस परंपरा से आज भी कोरिया के लोग जुड़े हैं। थाइलैंड, इंडोनेशिया और कंबोडिया आदि कई देशों में रामायण के जीवंत प्रसंग मिलते हैं। अयोध्या, राम और रामायण केवल भारत ही नहीं, विश्व के कई देशों में आदर पाते हैं।

पिछले कुछ दशकों से यह गलत धारणा फैलाई गई कि अयोध्या में रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद एक महत्वपूर्ण स्थल के लिए दो समुदायों के बीच का झगड़ा था, जैसा यरुशलम के लिए यहूदियों और मुसलमानों के बीच रहा है। यह सच नहीं है। मुस्लिमों के लिए अयोध्या का कभी कोई महत्व नहीं था। न धार्मिक, न ऐतिहासिक। फिर भी इसके लिए हिंदुओं को लंबा संघर्ष करना पड़ा। इसके पीछे एक सभ्यतागत चेतना है। समूचे उत्तर भारत में राम मंदिरों का लगभग अभाव है जबकि रामायण, राम कथा से जुड़े स्थल और राम की पूजा व्यापक रूप से होती है। तब क्या उत्तर भारत में राम के मंदिर नहीं बने थे? यदि बने थे तो उनका क्या हुआ? स्पष्टतः सदियों के आक्रमणों में उन सभी को सचेत रूप से मिटाया गया, क्योंकि राम केवल ईश्वर अवतार ही नहीं, मर्यादा

पुरुषोत्तम शासक भी थे। जिनका रामराज्य आदर्श रूप में भी जन-गण के मन में स्थापित था। इसीलिए राम मंदिरों को मिटाना एक मजहबी मतवादी ही नहीं, एक रणनीतिक उद्देश्य भी रखता था। क्या वही मनोवृत्ति इस आखिरी चरण में भी नहीं देखी गई?

अयोध्या मामले में आरंभ से ही तथ्यों पर कोई विवाद नहीं था। मंदिर पर अतिक्रमण के बाद भी हिंदू वहां पर पूजा करते रहे और उस स्थान पर पुनः अधिकार के लिए लड़ते रहे। अंग्रेज शासकों ने भी माना था कि बाबरी मस्जिद से पहले मंदिर था, लेकिन उन्होंने इसे यूं ही रहने दिया। 1947 में आजादी मिलने के बाद हिंदुओं को लगा कि अब तो उन्हें रामजन्मभूमि मिल जानी चाहिए, मगर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन वामपंथी विचारों और आंदोलनों को बढ़ावा दिया जिनके लिए राम और रामायण अरुचिकर थे। नेहरूजी के बाद कांग्रेसी शासकों ने भी यही रवैया जारी रखा। इतने महत्वपूर्ण स्थल के लिए स्वतंत्र भारत में केंद्र और राज्य सरकारों ने जैसी उपेक्षा दिखाई वह भी हैरत की बात रही। कई देशों में स्वतंत्रता मिलने के बाद विदेशी साम्राज्यवादी प्रतीकों, इमारतों को हटाकर राष्ट्रीय स्वाभिमान की पुनर्स्थापना की गई। ग्रीस, बुल्गारिया, सर्बिया, पोलैंड और रूस में ऐसे तमाम उदाहरण हैं। अतः भारत जैसी महान सभ्यता को भी बाहरियों द्वारा खड़े किए गए अपमानजनक प्रतीकों को हटाकर अपनी धर्म परंपरा पुनर्स्थापित करने का अधिकार था। कम से कम महत्वपूर्ण हिंदू श्रद्धा स्थलों पर तो यह होना चाहिए था।

विवादित ढांचा विध्वंस से पहले तक ऐसे अनेक मुस्लिम थे जो वहां मस्जिद के नीचे मंदिर रहे होने का प्रमाण मिल जाने पर स्थान हिंदुओं को दे देने के पक्ष में थे, लेकिन सेक्युलर-वामपंथियों ने उन्हें बरगला कर रोका। इस पृष्ठभूमि में मुसलमानों को पूरे मामले पर आत्मचिंतन करना चाहिए। न केवल पिछले दशकों की उठापटक, बल्कि सदियों का भारतीय इतिहास और दूसरे देशों, समुदायों, धर्म-परंपराओं और राजनीतिक व्यवहारों के मद्देनजर उन्हें न्याय और सत्य की तलाश करनी चाहिए। यह कोई भी देख सकता है कि इस्लाम को आदर के नाम पर दुनिया भर में जो अपेक्षा रहती है, उसका दसांश भी हिंदू धर्म-परंपरा के लिए नहीं दिखाया जाता। रामजन्मभूमि पर पिछले तीस वर्षों की राजनीतिक, वैचारिक प्रक्रियाएं भी इसका प्रमाण हैं। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, मार्क्सवादी इतिहासकार और अनेक दलों ने बार-बार अपने रुख बदले। पहले बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर रहे होने का प्रमाण मांगा गया। जब अनेक पुरातात्विक प्रमाण मिलने लगे तो हाईकोर्ट का फैसला मानने की बात की गई। मगर फैसला आने पर, उसे मानने के बदले सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। फिर, जब सुप्रीम कोर्ट में बहस गंभीर दौर में पहुंची तब विचित्र दलील आई कि 16वीं सदी के शासक बाबर द्वारा किए गए कामों पर मौजूदा न्यायालय को विचार करने का अधिकार ही नहीं। एक तरह से हर हाल में हिंदुओं को वंचित रखने की जिद रही। क्या ऐसे रुख से सामाजिक सद्भाव बन सकता है? भारतीय मुस्लिमों को इस पर नए सिरे से विचार करना चाहिए। विविध मत वाले समुदायों के संबंध केवल समानता और सभी पक्षों द्वारा किन्हीं समान सिद्धांतों का सम्मान करके ही सद्भावपूर्ण बनाए जा सकते हैं। विशेषाधिकार या एकतरफा आधार पर नहीं। अयोध्या विवाद के समाधान के बाद एक समान कसौटी बनाने के लिए खुलकर विचार करना आवश्यक है। इसी में सामाजिक संबंधों की सहजता और सद्भाव बनने की कुंजी है। इस दिशा में मुस्लिम समुदाय के विवेकशील लोगों को पहल करनी चाहिए।

(लेखक राजनीतिशास्त्र के प्राध्यापक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

प्रसन्नता का मंत्र

विश्वप्रसिद्ध उपन्यासकार और कवि थॉमस हार्डी का जीवन संघर्षों में बीता था। उन्होंने मानव जीवन की परेशानियों को बड़े नजदीक से देखा और बहुत संजीदगी से महसूस किया था। मानव के प्रसन्न रहने की लालसा के संबंध में उनका यह कथन अति प्रेरणादायी है, 'दर्द के सामान्य नाटक में खुशी कभी-कभार आने वाली घटना है।' किंतु दुर्भाग्यवश जीवन में खुशियों के बारे में इस कड़वी और कालातीत सच्चाई को हम जीवनपर्यंत समझ ही नहीं पाते हैं और खुशियां प्राप्त करने की राह महज एक मृगमरीचिका बनकर रह जाती है।

दुनिया में हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है। खुशी प्राप्त करने की मानव स्वभाव के इस लिहाज से यहां पर एक प्रश्न का उठना काफी लाजिमी हो जाता है कि आखिर एक इंसान क्या करे जो वह हमेशा खुश रहे और उदासी का साया कभी भी उसके जीवन में दुख का सौगात लेकर नहीं आ पाए। वैसे गौर से सोचें तो यह समझते देर नहीं लगती है कि हमारा खुश होना और दुखी होना हमारी मनोस्थिति पर निर्भर करता है। मन में उमंग हो और सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो हम खुद को खुशी से लबरेज महसूस करते हैं। किंतु जब मन विषाद से भरा हो, दर्द हो और कुछ भी आपकी सोच के अनुकूल नहीं हो रहा हो तो फिर मन उदासियों से भर जाता है। अर्थात इंसान का मन उसकी खुशियों की चाभी के रूप में काम करता है।

इसका आशय यह है कि खुश रहने के लिए हमें अपने मन को समझाना होगा। इसके लिए गौतम बुद्ध ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। उन्होंने कहा है कि प्रसन्न रहना एक कला है और इसके लिए बीते हुए कल पर सोचना बंद करने और दूसरों से खुद की तुलना पर रोक लगाने की जरूरत है। जब हम बीती हुई घटनाओं पर पश्चाताप करने लगते हैं और दूसरों के तथाकथित खूबसूरत शीशे में खुद का अक्स ढूंढने लगते हैं तो मन का भाव कसैला हो उठता है। वर्तमान में रहते हुए और खुद के जीवन को ईश्वर की सर्वोत्तम रचना समझकर जीवन जीने में ही प्रसन्न रहने का मूल मंत्र छुपा होता है।

श्रीप्रकाश शर्मा

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या नोटबंदी का फैसला अपने उद्देश्यों में सफल रहा?

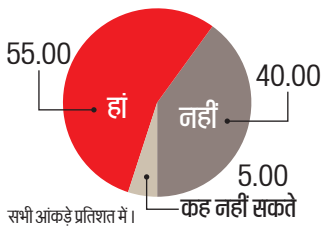

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश में सामाजिक तानाबाना मजबूत होगा?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

तोड़े संग-संग बैठकर सत्ता के सब ग्रास,
अब करवाने में जुटे अपना ही परिहास।
अपना ही परिहास भाजपा अरु शिवसेना,
कभी साथ थे आज न मिलते दिखते नैना।
विपक्षियों के साथ जा रहे रिश्ते जोड़े,
रिश्ते जिनके साथ जा रहे उनसे तोड़े।

- ओमप्रकाश तिवारी

भारतीय समाज में मंदिरों की महत्ता

अभिनव प्रकाश

हिंदू समाज के लिए मंदिर केवल पूजा-स्थल न होकर आर्थिक, सामाजिक, अध्ययन और कला के भी केंद्र रहे हैं

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने के साथ ही यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भारत में आदिकाल से ही मंदिर महत्वपूर्ण रहे हैं। हालांकि वैदिक पूजा पद्धति में मंदिर या मूर्ति की प्रमुखता नहीं थी। फिर भी विभिन्न देवी-देवताओं, यक्ष, पितर, ग्रह-नक्षत्र, ग्राम देवताओं इत्यादि की पूजा-अर्चना का चलन हमेशा से रहा है। प्रकृति और मातृ शक्ति के लिए पूजन स्थल स्थापित करने की परंपरा ही कालांतर में चलकर पौराणिक देवी-देवताओं के लिए भव्य मंदिरों के निर्माण में परिवर्तित हो गई। इसमें चौथी-पांचवीं शताब्दी से गांधार और मथुरा की बौद्ध मूर्तिकला का भी प्रभाव देखने को मिलता है। भक्ति काल में मंदिरों की महत्ता और भूमिका अपने आधुनिक रूप में विकसित हुई। मध्यकाल के दौरान हिंदू मंदिर सामाजिक जीवन और लोकप्रिय संस्कृति पर अपने प्रभाव के चरम पर थे। आरंभिक काल से ही मंदिर सामाजिक गतिविधियों के केंद्र रहे हैं। कुल और परिवार के मंदिर, ग्राम और नगर के मंदिर और सभी वर्गों में विख्यात प्रसिद्ध तीर्थ-स्थलों के मंदिर हिंदू समाज के न सिर्फ आध्यात्मिक, अपितु आर्थिक, सामाजिक, अध्ययन एवं कला के भी केंद्र रहे हैं। इसके साथ ही प्रमुख मंदिर अपने-अपने क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक इकाई भी होते थे। मंदिरों के नित्य कर्म पर हजारों लोगों का रोजगार जुड़ा होता था। जैसे कि शिल्पकार, राज मिस्त्री और बुनकर जैसे तमाम तबके इन पर आश्रित होते थे। मंदिर उपभोग का भी प्रमुख केंद्र हुआ करते थे जहां नारियल, चंदन, चावल, हल्दी, तेल, घी और अगरबत्ती के अलावा फल-फूल जैसे उत्पादों की बड़े पैमाने पर खपत होती थी। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को आवश्यक गति मिलती।

दक्षिण में तो मंदिर बैंक की भूमिका भी निभाते थे। दूसरे देशों के साथ भारतीय व्यापार को संचालित करने में मंदिर व्यापारियों को निधि उपलब्ध कराते। उस पर मिलने वाला प्रतिफल मंदिरों की समृद्धि का एक अहम कारक हुआ करता था। भारत के तटीय इलाकों में तमाम मंदिर इस परंपरा से जुड़े हैं। जैसे गुजरात का हरसिद्धि माता का मंदिर जो नाविकों और समुद्री व्यापारियों की संरक्षक मानी जाती हैं। व्यापार में मंदिरों के महत्व का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि पिछली सदी के आरंभ में हमलावरों द्वारा मंदिर विध्वंस का सीधा असर समुद्री व्यापार के कमजोर होने में दिखाई देता है।

मंदिर भारत में कला के अद्वितीय केंद्र रहे हैं। मंदिरों की स्थापत्य कला समाज की कलात्मक पराकाष्ठा की अभिव्यक्ति हुआ करती थी। मंदिर कल्पना, योजना, अभियांत्रिकी, मूर्तिकला और समाज की साधन-संपन्नता के भी प्रतीक हुआ करते थे। इसके साथ ही मंदिर गीत और नृत्य, नृत्यशाला और नाट्यकला के भी महत्वपूर्ण केंद्र होते थे। भारतीय शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य के विकास में मंदिरों की प्रमुख भूमिका रही। ज्ञान-अर्जन और अध्ययन के केंद्र के रूप में भी मंदिरों की महत्ता रही है। मंदिरों को दिए गए दान से और राज्य एवं बड़े व्यापारियों द्वारा दी गई संपत्ति से तमाम आश्रम संचालित होते थे। आज भी मंदिर सामाजिक हित में तमाम गतिविधियां भी चलाते हैं जिनमें स्कूल, अस्पताल और धर्मशालाएं जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

मंदिर सामाजिक जीवन का केंद्र हैं। इससे एकता और समरसता की भावना मजबूत होती है। मंदिरों की यह भूमिका खासतौर पर विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्हें यह न केवल अपने धर्म और संस्कृति से जोड़े रखती है, बल्कि उनके लिए समर्थन का आधार भी उपलब्ध कराती है। तमाम संतों ने अपने सामाजिक सुधारों के जरिये मंदिरों के माध्यम से सामाजिक भेदभाव को चुनौती दी है। मंदिरों को केवल पूजा-स्थल के रूप में ही नहीं देखा जा सकता, वे हिंदू समाज के आर्थिक, सामाजिक एवं कलात्मक अभिव्यक्ति के केंद्र रहे हैं।

यह शायद मंदिरों का ही महत्व था कि विदेशी आक्रांता भी उन्हें ही निशाना बनाया करते थे। मंदिरों का विध्वंस धार्मिक उत्पीड़न से अधिक सामाजिक मनोबल तोड़ने वाला हुआ करता था। इसी मकसद से भारत में हजारों मंदिरों को ध्वस्त किया गया। राम मंदिर इनमें से एक है। उत्तर भारत में शायद ही कोई मंदिर होगा जो दो सौ वर्ष से पुराना हो, क्योंकि वे ध्वस्त किए गए। इनमें से अधिकांश का पुनर्निर्माण मराठा साम्राज्य के शिखर काल में संभव हुआ। इनमें अहिल्याबाई होल्कर का शासनकाल खासा अहम रहा। असल में उन्हें यह भान था कि हिंदू समाज में वास्तविक एवं प्रतीकात्मक रूप से मंदिरों की क्या महत्ता रही और नष्ट कर दिए गए मंदिरों का पुनर्निर्माण क्यों इतना आवश्यक है?

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं)

response@jagran.com

ट्वीट-ट्वीट

यह केवल भारत जैसे स्वाभाविक रूप से धर्मनिरपेक्ष देश में ही संभव है कि देश की 80 प्रतिशत बहुसंख्यक आबादी अपनी आस्था के केंद्र पर निर्णय के लिए 70 वर्षों तक प्रतीक्षा कर सकती है। धार्मिक सहिष्णुता पर भारत को भाषण देने वाले पश्चिमी देशों को खुद अपने अतीत पर गौर करना चाहिए।

मिन्हाज मर्चेंट@MinhazMerchant

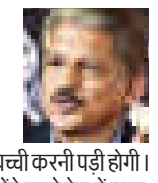

पांच लोग। एक फैसला जिसका 130 करोड़ लोग इंतजार कर रहे हों। इसका निर्णय करने वाली पीठ का हिस्सा होने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए और इसमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के कितनी माथापच्ची करनी पड़ी होगी। मैं उन लोगों को नमन करता हूं जिन्होंने हमारे देश में न्याय सुनिश्चित करने के अपने दायित्व का पूरे मनोयोग से निर्वहन किया।

आनंद महिंद्रा@anandmahindra

फैसले का विरोध कर रहे असदुद्दीन ओवैसी को शायद यह नहीं पता कि अयोध्या में और भी मस्जिदें हैं। उन्हें तो किसी ने हाथ नहीं लगाया और न ही लगाएंगे। यहां मसला केवल रामजन्मभूमि के ऊपर ढांचा खड़ा करने से जुड़ा था।

अद्वैता काला@AdvaitaKala

अयोध्या पर फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट बधाई का पात्र है। अब इसे मूर्त रूप देने के इंतजाम किए जाएं। इसके बाद हमें उन मुद्दों पर ध्यान देने में जुट जाना चाहिए जो हमारे देश को दुनिया में सबसे बेहतरीन जगह बना सकते हैं।

तापसी पन्नू@taapsee

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में

अयोध्या और जागरण

नरेन्द्र मोहन

भारतीय चेतना को भी न्याय दीजिए

राम जन्म स्थल पर बनने वाले मंदिर को लेकर जो विवाद उत्पन्न हो गया है, उस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने जैसी तत्परता अभी दिखाई है और अपने समक्ष प्रस्तुत विचारार्थ विषय को अधिकाधिक प्राथमिकता देकर जो निर्णय लिए हैं, वे भले ही विवादास्पद हों, पर समस्या की गंभीरता को देखते हुए उसने जो वरीयता उसे प्रदान की, यदि वैसी ही वरीयता इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इस विवाद को प्रदान कर दी गई होती तो संभवतः टकराव की वह स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाती, जो उत्पन्न हुई और अभी भी बनी हुई है। भारतीय न्यायपालिका कुल मिलाकर समय पर न्याय नहीं दे पा रही है और जो न्यायपालिका समय पर न्याय नहीं दे पाती, वह वास्तव में श्रेष्ठ कोटि का न्याय नहीं कर सकती और जब न्याय का स्तर श्रेष्ठ कोटि का न हो तो द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी के न्याय को न्याय कैसे कहा जाएगा, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। न्याय तो वही है जो समय पर दिया जाए। इस अवधारणा के प्रतिकूल जो कुछ भी है, उसे न्याय नहीं कहा जा सकेगा। मृत व्यक्ति को कोई न्याय नहीं देता, जो बीत गया है, जो नष्ट हो गया, जो इतिहास बन गया है-उस पर न्यायपालिका विचार नहीं करेगी। चंद अपवादों को छोड़कर सीमा अवधि बीत जाने के उपरांत न्यायपालिका किसी भी ऐसे वाद पर विचार नहीं कर सकती, जो देर से दायर किया गया हो, पर न्यायपालिका स्वयं अपने पर कोई अंकुश नहीं लगाना चाहती-ऐसा क्यों? न्यायपालिका भी तो उत्तरदायी है कि वह एक निश्चित सीमा अवधि में उन वादों का हल बताए, जो उसके समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किए गए हैं। राम जन्म स्थल को लेकर अनेक याचिकाएं विभिन्न न्यायालयों में दायर की गईं, पर आज तक उनका कोई हल नहीं निकल पाया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष 2.77 एकड़ भूखंड को लेकर जो मामला है, उस पर बहस भी हो गई, सुनवाई भी हो गई, पर उच्च न्यायालय ने तत्काल अपना निर्णय नहीं सुनाया। इस निर्णय को देने में देरी क्यों की गई, यह अपने आप में एक गंभीर प्रश्न बन चुका है। सच और झूठ क्या है, यह कोई नहीं जानता, लेकिन देश का एक बहुत बड़ा वर्ग स्पष्ट रूप से न्यायपालिका और भारत सरकार पर भी आरोप लगा रहा है कि यह देरी राजनीतिक स्वार्थों के तहत कराई गई है। काश, इस प्रकार के आरोप भारतीय न्यायपालिका पर ना लग पाते।

जातीयता को मान्यता

यह एक चिंताजनक बात है कि भारतीय न्यायालय इधर, बार-बार विवादों के घेरे में फंसती चली जा रही है। भारतीय न्यायपालिका का आचरण भले ही कितना ही श्रेष्ठ कोटि का क्यों न रहा हो, उसके अनेक निर्णय ऐसे भी हुए हैं, जिनसे राष्ट्र की समस्याएं बढ़ी हैं, कम नहीं हुईं। इसी परिप्रेक्ष्य में एक बुनियादी प्रश्न यहां उठता है कि क्या न्यायपालिका को राष्ट्र की समस्याओं की अनदेखी कर कोई निर्णय देना चाहिए और साथ ही एक प्रश्न यह भी कि राष्ट्रीय समस्याओं को किस परिप्रेक्ष्य में न्यायपालिका द्वारा देखा जाए? उदाहरण स्वरूप सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, वह भले ही तकनीकी रूप से सही हो, लेकिन कुल मिलाकर इस निर्णय ने समाज में व्याप्त जातिवाद को मान्यता ही प्रदान की है। भारत के पतन का मूल कारण, यह जातिवाद ही रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे न्यायाधीश इस सच्चाई से परिचित न हों। वे यह सच्चाई अच्छी तरह से जानते हैं कि इस जातिवाद को समाप्त करने के लिए कैसे-कैसे आंदोलन हमारे देश में हुए और संविधान निर्माताओं ने भी किस तरह से जातिवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया था। और तो और भारतीय संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर तक ने बड़ी स्पष्ट घोषणा की थी कि भारतीय संविधान किसी भी प्रकार से जातिवाद को मान्यता प्रदान नहीं करेगा। जातिवाद की अवधारणा पर प्रहार करने के लिए ही भारतीय संविधान में अनेक व्यवस्थाएं बनाई गईं, सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए, सभी नागरिकों को न्याय मिले-इसकी पूरी व्यवस्था बनाई गई। समाज में वास्तव में मातृभाव जाग्रत हो-इसकी स्पष्ट घोषणा की गई, पर ऐसा लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने समस्त घोषणाओं को केवल राजनीतिक घोषणा ही माना और संभवतः इसीलिए जातिवाद के जिस सिद्धांत को मंडल आयोग ने मान्यता दे दी थी, लगभग उसी सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने मान्यता प्रदान कर दी। जो राष्ट्र, जो समाज स्वयं अपनी योग्यता को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, जिस समाज में जानबूझकर अयोग्यता को मान्यता देकर उसे योग्यता के ऊपर बैठा दिया जाता है, वह समाज कैसे प्रगति करेगा-यदि इस पर थोड़ा भी विचार सर्वोच्च न्यायालय ने कर लिया होता तो संभवतः जैसे निर्णय आरक्षण के संदर्भ में उसके द्वारा किया गया है, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन आता।

यह अनदेखी क्यों?

एक बात जिसका उत्तर समझ में नहीं आ रहा है और वह यह है कि क्या न्यायालय केवल किताबी दृष्टि से ही न्याय करेगा और क्या न्यायपालिका को अधिकाधिक संकीर्ण होकर न्याय की व्यवस्था करनी चाहिए तथा राष्ट्र की जो समस्याएं हैं, उन पर गंभीरता से विचार करने का दायित्व उसका नहीं है, क्या न्यायपालिका को यह नहीं देखना है कि जातिवाद का जो विष भारतीय समाज में व्याप्त है, वह कैसे दूर किया जाए। समाज में जो कुरीतियां व्याप्त हैं, उन्हें दूर करने का दायित्व क्या न्यायपालिका पर नहीं है? धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता के नाम पर क्या किसी को भी इस बात का अधिकार मिल जाएगा कि वह राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करने के लिए स्वतंत्र हो जाए? क्या न्यायपालिका इस पर विचार नहीं करेगी कि राष्ट्र क्या है? राष्ट्रीयता क्या है, भारतीयता क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है, भारतीय आदर्श क्या हैं, कहां है उनका उद्गम, कहां से है उनका उद्भव, कैसे होगा उनका पोषण, कौन करेगा उनका पोषण एवं संवर्द्धन और कौन लड़ेगा कुरीतियों से, जातीयता की बुराइयों से। इसी प्रकार क्या न्यायपालिका को इस पर विचार नहीं करना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वाभिमान जागृत करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं और ये उपाय कौन करे। वे कौन से कृत्य हैं जिनसे राष्ट्र की अस्मिता प्रभावित होती है, राष्ट्रीय स्वाभिमान नष्ट होता है। वे कौन हैं, जो धर्म के नाम पर सत्य की पक्षधरता को नष्ट कर रहे हैं? क्या धर्म के नाम पर किसी को भी यह अधिकार है कि वह सत्य को नष्ट कर दे और राष्ट्र को खंडित हो जाने दे। क्या धर्म राष्ट्र की स्वतंत्रता से ऊपर है? न जाने कितने ऐसे प्रश्न हैं जो मेरे मन में उठते हैं और मेरी दृष्टि में सर्वोच्च न्यायालय को इनकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए, पर जहां तक मेरी जानकारी है, यदि सर्वोच्च न्यायालय इन प्रश्नों की अनदेखी नहीं कर रहा है तो कम से कम उन पर बहुत स्पष्ट रूप से विचार किया जा रहा हो-ऐसी स्थिति भी नहीं है।

विचार प्रवाह

न्यायपालिका का कर्तव्य

यदि वास्तव में भारत को एक अखंड और जीवंत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ना है और अपने को विश्व में स्थापित करना है तो उसे उन अनेक भ्रांतियों को दूर करना ही होगा जो भ्रांतियां कभी धर्म के नाम पर, कभी संस्कृति के नाम पर, कभी समाज के नाम पर, कभी अल्पसंख्यकवाद के नाम पर, कभी सामाजिक न्याय के नाम पर चारों ओर बिखरी हुई हैं। संसद इस कार्य को इसलिए नहीं कर सकेगी, क्योंकि संसद में जो लोग चुनकर आते हैं, वे सामान्यतः राजनीतिक संकीर्णता से ग्रस्त होते हैं। भारतीय राजनीतिज्ञों में नैतिक साहस का बहुत अधिक अभाव है और साथ ही वे सत्ता मोद से इतने अधिक पीड़ित हैं कि वे राष्ट्र की समस्याओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखने से इन्कार करते हैं। उनका प्रथम लक्ष्य यही रहता है कि किसी भी प्रकार से चुनाव जीता जाए और सत्ता की ऊंची से ऊंची कुर्सी तक पहुंचा जाए। देश को अंधकार से बाहर निकालने का कार्य न्यायपालिका को ही करना होगा, अंधकार से प्रकाश की ओर और असत्य से सत्य की ओर चलने का जो संकल्प कभी भारतीय मनीषियों ने लिया था, वह संकल्प राजनीतिज्ञों द्वारा पूरा नहीं किया जा सकेगा। वह संकल्प तो पूरा किया जा सकेगा या पूरा करवाया जा सकेगा-न्यायपालिका के माध्यम से ही। लेकिन अगर यही न्यायपालिका जातिवाद की वकालत करेगी या प्रश्न करेगी कि यह सुबूत लाओ कि राम का जन्म अयोध्या में ही हुआ था या इसे अनदेखा करेगी कि पिछले एक हजार वर्षों में देश के साथ आक्रमणकारियों ने क्या सलूक किया है और किस प्रकार से विदेशी संस्कृतियां भारतीय संस्कृति को पददलित और अपमानित करती चली आ रही हैं तो स्थिति बहुत जटिल हो जाएगी।

शासन और 'धर्म'

सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरह की शक्ति और तत्परता राम मंदिर के निर्माण के संदर्भ में दिखाई वह तकनीकी रूप से अनुचित नहीं है, लेकिन क्या राष्ट्र की समस्याओं को केवल कानूनी संकीर्णता से ही देखा जाएगा। निश्चित रूप से भारत एक संप्रदाय निरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भारत की अपनी कोई संस्कृति नहीं है, अपनी कोई मान्यता नहीं है और उसका अपना कोई इतिहास नहीं है। संप्रदाय निरपेक्ष होने का अर्थ केवल यह है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक को अपनी उपासना पद्धति चुनने का संवैधानिक अधिकार पूर्ण रूप से प्राप्त है और उसमें शासन या किसी अन्य द्वारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। क्योंकि शासन ने किसी भी उपासना पद्धति विशेष को कोई शासकीय मान्यता प्रदान नहीं की है। जिस उपासना पद्धति की बात यहां की जा रही है, उसे लोकाचार की भाषा में आज 'धर्म' के नाम से संबोधित किया जाता है, पर धर्म और उपासना पद्धति में भारी अंतर है, लेकिन तात्कालिक सुविधा और लोक मान्यता के सम्मान की दृष्टि से हम यहां उपासना पद्धति को धर्म का पर्यायवाची मान ले रहे हैं। शासन का कोई 'धर्म' नहीं होता और जिस शासन का 'धर्म' होता है, उसे संप्रदाय निरपेक्ष नहीं माना जा सकता। भारत संप्रदाय निरपेक्ष या 'धर्म निरपेक्ष' है, इसका अर्थ यही है कि यहां शासन का अपना कोई 'धर्म' नहीं है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं होता कि शासन अधर्मी या अनिश्वरवादी है। संविधान ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है कि शासन अधर्मी, विधर्मी या अनिश्वरवादी है अथवा ईश्वर को मान्यता नहीं देता। अतः न्यायपालिका को भी इस संदर्भ में उन तर्कों और संकीर्णताओं का परित्याग करना होगा, जो तर्क मात्र इसलिए दे दिए जाते हैं ताकि भारतीय संस्कृति को जो भी वर्ग पददलित करना चाहता है उसका वर्चस्व बना रहे।

इस्लाम और भारत

यह तो निर्विवाद रूप से सत्य है कि भारतीय संस्कृति को पददलित और अपमानित करने की सर्वाधिक चेष्टा मुगल शासनकाल में की गई, जब इस्लाम तलवार के बल पर भारत में आया और तलवार के बल पर ही उसने अपनी प्रभुता स्थापित की, उसके कारण देश में जो भारी उथल-पुथल हुई, उसके झटके आज भी लग रहे हैं। इस्लाम इस बात की मान्यता नहीं देता कि उसके समक्ष कोई दूसरी उपासना पद्धति बराबरी के स्तर पर ठहर सके। कट्टरतावादी इस्लाम की धारा तो इस बात की स्पष्ट घोषणा करती है कि जो इस्लाम के अनुयायी नहीं हैं, इस्लाम को कबूल नहीं करते हैं उनका कत्ल तक कर दिया जाना चाहिए। दूसरी उपासना पद्धतियों के प्रति जितनी अधिक असहिष्णुता कट्टरपंथी इस्लाम में है, वैसी असहिष्णुता भारत के लिए पूर्णरूप से विजातीय है। भारतीय मन यह कभी सोच नहीं सकता कि तलवार अर्थात शक्ति के बल पर किसी भी उपासना पद्धति को किसी दूसरे व्यक्ति या समाज पर थोपा जा सकता है, लेकिन इस सच्चाई को कहने का साहस न तो भारतीय संसद के पास है और न ही भारतीय न्यायपालिका के पास और जब भारतीय विधायिका और न्यायपालिका के पास यह साहस है ही नहीं, तब कार्यपालिका के पास यह साहस कहां से आ सकता है? राष्ट्र एक बौद्धिक पंगुता की स्थिति में पहुंचता चला जा रहा। इस बौद्धिक पंगुता या बौद्धिक क्लैव्यता अथवा बौद्धिक नपुंसकता ने राष्ट्र के समक्ष गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर दी है। राम जन्म स्थल पर मंदिर निर्माण की जो वर्तमान समस्या है, वह इसी बौद्धिक क्लैव्यता और बौद्धिक नपुंसकता की ही देन है।

इसमें अनुचित क्या है?

मैं अनेक बार यह बात लिख चुका हूं और पुनः इस बात को यहां दोहराना चाहूंगा कि न्याय पाने का अधिकार देश के बहुसंख्यकों को भी तो प्राप्त है। देश के बहुसंख्यकों के साथ भारतीय संस्कृति के साथ जो अन्याय अभी तक होता चला जा रहा है-क्या उसका कोई प्रतिकार नहीं खोजा जाएगा? मैं यह नहीं कहता कि देश के इतिहास को दोबारा लिखिए। इतिहास से बदला लेने की भी बात मैं नहीं कर रहा हूं। बात तो केवल यह है कि भारत के शरीर में जो भाले सैकड़ों वर्ष पहले चुभो दिए गए, उन भालों और बर्छियों को कोई बाहर खींचकर निकालेगा या नहीं? मुगल शासन काल में जब अत्याचार की बर्छियों से इस देश की संस्कृति को बुरी तरह से बेध डाला गया था तब वे बर्छियां इसलिए नहीं निकाली जा सकती थीं, क्योंकि हम गुलाम थे। मुगलों के बाद अंग्रेज आ गए, उन्होंने भी इन बर्छियों को निकालने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें भारतीय संस्कृति के आत्म सम्मान से कुछ भी लेना-देना नहीं था। आखिर मुगलों की तरह अंग्रेज भी आक्रमणकारी ही थे, अतः उन्होंने भी भारतीय संस्कृति के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया, पर जब हम आजाद हुए, तब उसके बाद भी क्या ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए था, जिससे कम से कम बर्छियां बाहर निकल सकतीं, जो इन आक्रमणकारियों ने हमारे शरीर में चुभो दी थीं। यदि इस संदर्भ में न्यायपालिका की सहायता मांगी जा रही है तो इसमें अनुचित क्या है? क्या भारतीय संस्कृति को न्यायपालिका के समक्ष जाकर न्याय मांगने और न्याय पाने का अधिकार नहीं है? आज भारतीय संस्कृति, भारतीय अस्मिता और भारतीय स्वाभिमान न्यायपालिका के समक्ष जाकर केवल न्याय की भीख ही तो मांग रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि न्याय भिक्षा के रूप में भी नहीं मिलने वाला और अगर वास्तव में यही स्थिति बनी रही तो फिर देश में भूचाल आएगा, अच्छा यह होगा कि भूचाल न आए और समय रहते न्यायपालिका अपने दायित्व को समझ ले। अगर भारतीय न्यायपालिका ने अपने आपको उस मानसिकता से मुक्त नहीं किया जो मानसिकता उसे ब्रिटिश शासकों से विरासत में मिली है और अगर न्यायपालिका ने खुद को भारतीय संस्कृति और उसके श्रेष्ठ मूल्यों से नहीं जोड़ा तो कुल मिलाकर वह भारतीय जनमानस के साथ वास्तव में बौद्धिक और मानसिक स्तर पर कोई न्याय नहीं कर सकती।

वास्तविक न्याय चाहिए

जहां तक भौतिक स्तर की बात है, उस स्तर पर तो न्याय गुलामी के दिनों में भी भारतीय नागरिकों को मिल जाया करता था, लेकिन मानसिक और बौद्धिक स्तर पर न्याय पाना अभी भी एक जटिल समस्या है। सर्वोच्च न्यायालय को आज केवल भौतिक स्तर पर ही न्याय नहीं देना है, उसे राष्ट्र को बौद्धिक, मानसिक, आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक स्तर पर भी न्याय देना होगा। यदि राष्ट्र चेतना के स्तर पर न्याय नहीं दिया गया तो भौतिक स्तर पर दिए जाने वाले न्याय का कोई मूल्य नहीं होगा। जिस राष्ट्र के पास अपनी कोई स्वयं की बौद्धिक चेतना नहीं होती, वह राष्ट्र केवल बौद्धिक आधार पर अपना विकास नहीं कर सकता और न विश्व को नेतृत्व दे सकता है और न ही मानवता का कोई कल्याण कर सकता है।

न्यायपालिका के समक्ष अपनी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। उसके समक्ष अनेक ऐसे अवरोध हो सकते हैं, जो गंभीर सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियों के कारण उत्पन्न होते हैं, पर इन अवरोधों को दूर करने का कार्य भी तो न्यायपालिका को ही करना होगा। लेकिन जातीयता की रक्षा करके कोई इन अवरोधों को कैसे दूर करेगा? राष्ट्र की जो बौद्धिक शक्ति है, जो प्रतिभा है उसको अपमानित और पददलित करके भी कोई कैसे इन अवरोधों को दूर करेगा? न्याय के तो अनेक पक्ष होते हैं। किताबी न्याय को न्याय नहीं कहा जा सकता। वास्तविक न्याय तो वह है जो राष्ट्रीय चेतना को जागृत कर सके और जो राष्ट्रीय स्वाभिमान को पुनर्स्थापित नहीं कर सकता-वह न्याय नहीं है।

(8 दिसंबर, 1992 को प्रकाशित विचार प्रवाह)

न्यायपालिका और राम मंदिर

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अयोध्या में विवादित 2.77 एकड़ भूमि के अधिग्रहण को लेकर जो फैसला दिया है, वह फैसला अगर समय पर दे दिया जाता तो देश को जिस दुर्दशा को देखना पड़ रहा है, हो सकता है कि वह सब कुछ नहीं देखना पड़ता। देर से दिया जाने वाला न्याय समाज के लिए कितना बड़ा अभिशाप सिद्ध को सकता है-कम से कम इस बात का एहसास अब तो भारतीय न्यायपालिका को हो ही जाना चाहिए। यह ठीक है कि हर मुकदमे का फैसला एक निश्चित सीमा अवधि के अंतर्गत और तात्कालिक रूप से नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ विवाद ऐसे होते हैं, जिनका संबंध राष्ट्र और समाज से तथा राष्ट्र की भावनाओं से होता है। और यदि इस तरह के विवादों के फैसले में देरी होगी तो मिलकर राष्ट्र गंभीर संकट में फंस जाएगा। न्यायपालिका का यह दायित्व है कि वह राष्ट्र को कम से कम गंभीर संकटों से तो अवश्य ही बचाए। जो विवाद देश की भावनाओं से संबंधित हैं और जिनका संबंध समाज की आस्था है, उन विवादों को यदि न्यायपालिका द्वारा महत्व देकर सक्रियता से निर्णीत नहीं किया जाएगा तो इसे देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा।

राम राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय स्वाभिमान, राष्ट्रीय आदर्शों और श्रेष्ठ मानव मूल्यों के प्रतीक हैं। उन पर समस्त राष्ट्र को गौरव होना चाहिए। जो राम को राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान का प्रतीक नहीं मानते, उन्हें सच्चा भारतीय नहीं कहा जा सकता-चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान, सिख हों या ईसाई, पारसी हों या यहूदी या कोई अन्य धर्मावलंबी। भारत में रहने वाले को अपने पूर्वजों पर गौरव होना चाहिए। भारतीय हो कर भी जो व्यक्ति अपने पूर्वजों पर गर्व नहीं कर सकता, वह सच्चा भारतीय नहीं है। राम, कृष्ण और इसी प्रकार की अनेक महान विभूतियां हमारी पूर्वज हैं, हम उनसे प्रेरणा लेते रहे हैं, लेते हैं और आगे भी लेंगे। आने वाली पीढ़ी यदि अपने श्रेष्ठतम पूर्वजों से प्रेरणा नहीं लेगी, उनका सम्मान करना नहीं जानेगी तो ऐसी पीढ़ी भारतीय होते हुए भी अभारतीय होगी। जो भारतीय है, वह कभी भी राम के प्रति अनादर का भाव रख ही नहीं सकता और न राम जन्म स्थल के प्रति अनादर का भाव प्रदर्शित कर सकता है।

राम केवल हिंदुओं के ही प्रतीक नहीं हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कुछ लोग विशेष रूप से इस्लाम के अनुयायी राम के प्रति उस प्रकार आदर भाव नहीं रखते जैसा कि हिंदू रखते हैं, लेकिन इससे भी कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। कोई सत्य को पहचानने से इन्कार कर दे, कोई सूर्य को पहचानने से इन्कार कर दे तो इससे न तो सत्य असत्य तो सकता है न सूर्य का प्रकाश कम हो सकता है। सच तो यह है कि इस राष्ट्र को राम के प्रति नमन करना ही होगा, तभी यह राष्ट्र भारत वर्ष कहलाएगा। आखिर जब मिस्र अपने पूर्वजों के प्रति, जो कि मुसलमान नहीं थे, नमन कर सकता है। टर्की अपने पूर्वजों के प्रति जो मुस्लिम नहीं थे, नमन कर सकता है। इराक अपने पूर्वजों के प्रति जो मुसलमान नहीं थे, नमन कर सकता है। इंडोनेशिया, जो मुस्लिम बहुल राष्ट्र है, राम का आदर और सम्मान कर सकता है, तब भारतीय एक स्वर से अपने पूर्वजों के प्रति नमन क्यों नहीं करना चाहते। इस संदर्भ में जो कुछ हो रहा है, उसे यह कहा जा रहा है कि भारतीय संस्कृति और भारतीयता के साथ न्याय किया जा रहा है। यह तो न्याय नहीं न्याय का उपहास है। जिस प्रकार व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार है, उसी प्रकार से राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र के स्वाभिमान और राष्ट्र की संस्कृति को भी न्याय पाने का अधिकार है। जब तक भारतीयता को, भारतीय संस्कृति को तथा भारतीय स्वाभिमान को न्याय देने के लिए न्यायपालिका आगे नहीं आएगी, वह भारतीय मानसिकता में आज जो विस्फोट हो रहा है, उसे रोक नहीं सकेगी। भारत सरकार अविलंब राम जन्म भूमि संबंधी विवाद का जो मुख्य कारण है, उसे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए भेज दे कि एक निश्चित अवधि के अंदर इस पर निर्णय दिया जाए कि वहां कभी बाबरी मस्जिद बनवाई गई थी, क्या वहां पहले कोई मंदिर था, जिसे गिराकर मीर बकी ने अपनी विजय ध्वजा के रूप में मस्जिद बनवाई?

(13 दिसंबर, 1992 को प्रकाशित संपादकीय)

साक्षी और सहयात्री

अयोध्या में राम जन्म स्थल पर राम मंदिर के लिए आग्रह का भाव प्रबल होने और उसके आंदोलन का रूप लेने के पहले से ही दैनिक जागरण का यह मत था कि हिंदू समाज की ओर से पावन समझे जाने वाले इस स्थल पर राम के नाम का मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि ऐसे मंदिर भारतीय जनमानस की सांस्कृतिक चेतना के केंद्र होते हैं और वे राष्ट्र को प्रेरणा प्रदान करने का भी काम करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की आवश्यकता को बल प्रदान करने के साथ ही जागरण ने सदैव इस बात को रेखांकित किया कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर बनने वाला भव्य मंदिर समस्त मर्यादाओं का पालन करते हुए ही निर्मित होना चाहिए। इसीलिए दिसंबर 1992 में जब अयोध्या स्थित विवादित ढांचे को ध्वंस हुआ तो जागरण ने इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना माना और स्पष्ट तौर पर ऐसा लिखा भी। विवादित स्थल में उग्र कारसेवकों के प्रवेश कर जाने और तोड़फोड़ शुरू कर देने के घटनाक्रम की सूचना प्रधानमंत्री नरसिंह राव को शायद सबसे पहले जागरण के तत्कालीन संपादक नरेंद्र मोहन ने कानपुर स्थित अपने कार्यालय से फोन के जरिये दी थी। उस दिन दोपहर करीब 12 बजे का समय था जब नरेंद्र मोहन जी को अयोध्या में तैनात अपने संवाददताओं के जरिये विवादित स्थल पर जमा कारसेवकों के बेकाबू होकर तोड़फोड़ करने की सूचना मिली। उन्होंने सूचना की पुष्टि करने के बाद तुरंत प्रधानमंत्री कार्यालय फोन लगाया। फोन प्रधानमंत्री के सचिव रामू दामोदरन ने उठाया। चंद क्षणों बाद नरेंद्र मोहन जी ने प्रधानमंत्री को अयोध्या की नाजुक स्थिति से अवगत कराया। इस प्रसंग का उल्लेख इसलिए, क्योंकि लोगों ने यह लिखा है कि जिस समय ढांचा टूट रहा था उस समय नरसिंह राव सो रहे थे। किसी ने यह भी लिखा है कि वह पूजा कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं था और इसकी पुष्टि रामू दामोदरन कर सकते हैं।

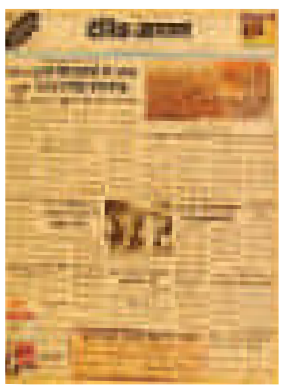

1990 के दशक का प्रारंभिक कालखंड वह समय था जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का आंदोलन एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले रहा था। अयोध्या इस आंदोलन के केंद्र में थी और उत्तर प्रदेश में उसका सबसे अधिक असर था। यह असर हर कहीं और समाज के हर वर्ग के बीच दिखता था। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक और तहसील स्तर तक फैले जागरण के संवाददाता इस असर की न केवल थाह ले रहे थे, बल्कि उसे व्यक्त भी कर रहे थे। निःसंदेह घटनाओं के केंद्र में अयोध्या और उसके आसपास का क्षेत्र ही था, लेकिन सच यह है कि उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में राम मंदिर की गूंज सुनाई दे रही थी। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा केवल अयोध्या आंदोलन से सक्रिय तौर पर जुड़े लोगों का नारा नहीं था, बल्कि वह आम जनता का साझा स्वर बन गया था। इन स्वरों को व्यक्त करने में जागरण ने तत्परता भी दिखाई और सतर्कता भी। आज उस दौर की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन उस दौरान राम मंदिर ने उत्तर प्रदेश को जिस तरह आंदोलित भी कर रखा था और उद्वेलित भी उसकी हाल के इतिहास में मिसाल नहीं मिलती। जागरण इस आंदोलन और उद्वेलन का साक्षी भी रहा और सहयात्री भी।

गलत बातें मत कीजिए

रामजन्म स्थल को लेकर इधर कुछ दिनों से केंद्रीय सत्तारूढ़ नेताओं द्वारा जिस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं, उससे निश्चित रूप से यह समस्या और अधिक उलझ जाएगी। यह दुर्भाग्य की बात है कि यह सुनने में आया है कि राष्ट्रपति तक ने कहा है कि उस स्थान पर पुनः मस्जिद बना दी जानी चाहिए। यदि देश को इसी तरह से चलाना है, तो इतनी बात भी निश्चित मान ली जानी चाहिए कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच वास्तविक सद्भाव की स्थिति कभी उत्पन्न होने वाली नहीं है। यह खाई और बढ़ेगी। रामजन्म स्थल पर मस्जिद बने और वह भी वर्तमान सरकार द्वारा बनावाई जाए इसका कोई औचित्य नहीं। अयोध्या में कौन सा स्थान रामजन्म स्थल है, यह बात न्यायपालिका नहीं तय कर सकती। यह हिंदुओं के लिए आस्था और विश्वास का प्रश्न है। हां, इस बात पर सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से निर्णय प्राप्त किया जा सकता है कि मीर बकी ने कभी किसी मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनवाई थी या नहीं? विश्व में हिंदू ही ऐसे अभागे हैं, जो यदि यह कह सकते हैं कि वे हिंदू हैं, तो लोग उन्हें सांप्रदायिक मानने लगते हैं। ऐसी हीन भावना अन्य किसी धर्मावलंबी में देखने को नहीं मिलती। इस हीन भावना से अब हिंदू धीरे-धीरे बाहर निकल रहा है और यह उचित भी है।

समझ नहीं आया कि भारत सरकार विश्व के समक्ष यह बात क्यों नहीं कह पाती कि अयोध्या में रामजन्म स्थल पर जो विवादित ढांचा था, वह पचास वर्षों से भी अधिक समय से मंदिर है और उस स्थल में सौ वर्षों से भी अधिक समय से पूजा अर्चना कीर्तन होता चला आया है और इसीलिए बहुत लंबे अरसे से वहां नमाज भी नहीं पढ़ी गई। जिस ढांचे को 'बाबरी मस्जिद' कहा जा रहा था, वह अगर बाबरी मस्जिद थी, तो वहां नियमित रूप से नमाज क्यों नहीं पढ़ी गई? मुसलमानों के लिए तो वह एक परित्यक्त स्थल था। हिंदुओं के लिए वह रामजन्म स्थल है, अतः मुसलमानों द्वार परित्यक्त होने के बाद भी हिंदुओं ने अपना धार्मिक अनुष्ठान जारी रखा, भजन कीर्तन करते रहे और बाद में लगभग पचास वर्ष पहले वहां रामलला की मूर्ति स्थापित कर दी गई। क्या जो स्थल पचास वर्षों से मंदिर के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, उस स्थान को लेकर यह कहना कि वहां 'मस्जिद' को ढहा दिया गया, अनुचित नहीं है। हां, एक ऐसे विवादित ढांचे को ढहाया गया, जिसके अंदर रामलला की मूर्ति थी। एक बात यह भी समझ लेने की आवश्यकता है कि इस समय विश्व की राजनीति और कूटनीति इस्लाम और गैर-इस्लाम के बीच विभाजित हो चुकी है।

अगर अयोध्या में रामजन्म स्थल पर कोई ढांचा बनवाने की बात आएगी भी तो भारत सरकार को उस ढांचे को विवादित ही कहना होगा और उस विवादित ढांचे के अंदर उसे रामलला की मूर्ति ही स्थापित करनी होंगी। यह नहीं हो सकता कि अब रामजन्म स्थल पर रामलला की मूर्ति स्थापित न हो। भारत सरकार उन्हें हटवा नहीं सकती। यदि ऐसी कोई चेष्टा की जाती है, तो वह कांग्रेस के लिए अभिशाप सिद्ध होगी और कम से कम बहुसंख्यक समाज की दृष्टि में तो कांग्रेस का अंत ही हो जाएगा। इतना बड़ा राजनीतिक खतरा कांग्रेस उठाए, इसकी कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। खाड़ी के देश क्या सोचते हैं, क्या नहीं- यह एक अलग प्रश्न है। मुख्य बात यह है कि इस देश का बहुसंख्यक समाज क्या सोच रहा है। यह तो अपने आपको धोखा देने की बात है कि बहुसंख्यक समाज इस बात का पक्षधर है कि रामजन्म स्थल पर पुनः मस्जिद बना दी जाए। रामजन्म स्थल पर पुनः मस्जिद बना देने से किसी प्रकार की कोई भी समस्या हल नहीं होगी, बल्कि समस्या जितनी उलझी हुई है उससे कहीं अधिक उलझ जाएगी और फिर एक बात और है कि अगर मस्जिद बना भी दी गई तो क्या उसे भारत सरकार बाबरी मस्जिद कहेगी? क्या भारत सरकार को हर वह काम करना होगा, जो बाबर ने किए थे और इसीलिए करने होंगे, क्योंकि ऐसा करने से पाकिस्तान खुश हो जाएगा या अन्य मुस्लिम देश खुश हो जाएंगे।

(14 दिसंबर, 1992 को प्रकाशित संपादकीय)

5 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है हज यात्रा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि। हज कमेटी ऑफ इंडिया के सदस्य डॉ. इफ्तिखार अहमद जावेद ने बताया कि पासपोर्ट जारी होने की तारीख को भी बढ़ा कर पांच दिसंबर कर दिया गया है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
रविवार 10 नवंबर 2019

एम्स बनेगा विश्वस्तरीय, डॉक्टरों के सुझाव होंगे अहम

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

एम्स को विश्वस्तरीय मेडिकल विश्वविद्यालय बनाने की योजना में यहां कार्यरत डॉक्टर खासतौर पर भागीदार होंगे। इस प्रयास में संस्थान के डॉक्टरों व एम्स फैकल्टी एसोसिएशन, आरडीए (रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन) जैसे संगठनों के सुझाव अहम होंगे। यही वजह है कि एम्स प्रशासन ने संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं व भविष्य की जरूरतों पर सर्वे शुरू किया है। इसके लिए डॉक्टरों से सुझाव मांगे गए हैं। डॉक्टरों से कुछ अहम सुझाव मिलने पर उन्हें एम्स मास्टर प्लान में शामिल किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि केंद्र सकरार ने 10 हजार 345 करोड़ की लागत से एम्स के मास्टर प्लान की योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ एम्स को मेडिकल शिक्षा में सुधार के लिए विश्वस्तरीय मेडिकल विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया जाना है। साथ ही डॉक्टरों के लिए करीब चार हजार आवासीय फ्लैट बनाए जाने हैं। इस योजना पर जल्द अमल शुरू करने के लिए जोर-शोर से तैयारी चल रही है। यही वजह है कि एम्स विभागीय स्तर पर सर्वे कर रहा है। इसके तहत सभी विभागों के डॉक्टरों से ओपीडी के लिए उपलब्ध कमरे, डे-केयर की सुविधा, लैब, विभिन्न विभागों के लिए अस्पताल में उपलब्ध बेड, आइसीयू बेड, ऑपरेशन थियेटर (ओटी), मेडिकल के छात्रों के लिए प्रयोगशाला, रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए कमरे, सभागार, उपलब्ध डॉक्टरों व कर्मचारियों की संख्या इत्यादि की जानकारी मांगी गई है।

एम्स प्रशासन के अनुसार, संस्थान को अगले 30 साल की जरूरतों के अनुसार विकसित किया जाना है। इसलिए डॉक्टरों से यह भी पूछा गया है कि बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए किस तरह की क्या-क्या सुविधाएं शामिल की जाएं। बताया जा रहा है कि ज्यादातर विभागों ने अपने सुझाव एम्स प्रशासन को भेज दिए हैं। इसकी रिपोर्ट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजी जाएगी।

यह है योजना : मौजूदा समय में एम्स में कुल 2478 बेड हैं। एम्स मास्टर प्लान के अनुसार, इसमें 3000 अतिरिक्त बेड बढ़ जाएंगे। इसके लिए पुराने ब्लॉकों की जगह नए बहुमंजिला भवन बनाए जाएंगे। मेडिकल शिक्षा व शोध में सुधार के लिए अत्याधुनिक सुविधा से संपन्न शैक्षणिक व शोध ब्लॉक बनेगा। इसमें रोबोटिक सिम्युलेशन लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, सुपर स्पेशियलिटी रिसर्च लैब, व्याख्यान हॉल, हाईटेक क्लास रूम, सभागार व इवेंट सेंटर इत्यादि की सुविधा होगी। इसका निर्माण अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा। इसके अलावा संस्थान में पैदल चलने वालों व वाहनों के लिए अलग कॉरिडोर की सुविधा होगी। जिससे एम्स आकर्षक भी दिखेगा।

मरीजों का है भारी दबाव

एम्स में मरीजों का भारी दबाव है। हर साल करीब 41 लाख मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। इस वजह से संस्थान में सुविधाएं कम पड़ रही हैं। इसका असर शोध कार्य पर भी पड़ रहा है। यही वजह है कि एम्स को भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किया जाना है।

केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया

राज्य ब्यूरो,नई दिल्ली

राम मंदिर मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की पीठ के पांचों न्यायाधीशों ने एकमत से अपना निर्णय दिया। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। कई दशकों के विवाद पर शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। वर्षों पुराना विवाद आज खत्म हुआ। मेरी सभी लोगों से अपील है कि शांति एवं सौहार्द बनाए रखें।

वहीं, आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि इस फैसले को किसी की जीत-हार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। वर्षों से लंबित एक विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सभी पक्षों को सुनने के बाद सर्वसम्मति से पांच जजों की पीठ ने फैसला दिया है। मैं समझता हूं कि इस देश के लोकतंत्र की मजबूती, गंगा-जमुनी तहजीब, भाईचारे व संस्कृति की मजबूती के लिए सभी पक्षों को इस फैसले का स्वागत करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि हम सभी लोगों व देशवासियों से अपील करते हैं कि भारत एक गंगा-जमुनी तहजीब का मुल्क है। भारत एक अलग पहचान रखने वाला धर्मनिरपेक्षता का मुल्क है। सभी लोग अमन और शांति बहाल रखें। किसी को चिढ़ाने, दबाने या किसी के ऊपर आरोप-प्रत्योप करने की आवश्यकता नहीं है।

कांग्रेस के लिए देश का संविधान सर्वोपरि : सुभाष चोपड़ा

जाब्यू,नई दिल्ली : अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा की अध्यक्षता में बैठक हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए देश का संविधान सर्वोपरि है। पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहा कि समाज में भाईचारे को बनाए रखने के लिए काम करें। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता मुकेश शर्मा ने सदियों पुरानी गंगा-यमुना संस्कृति की रक्षा करने का प्रस्ताव पेश किया, जिसका सभी ने समर्थन किया। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री हारुन युसूफ, डॉ. किरण वालिया, डॉ. नरेंद्र नाथ व अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष पूर्व विधायक नदीम जावेद ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा धर्मनिरपेक्षता की बात की है।

भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया

भगवान राम अयोध्या में खुले आसमान के नीचे विराज रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जमीन राम लला के लिए देने का फैसला दिया है। सबसे खुशी की बात है कि दूसरे पक्ष को भी मस्जिद बनाने के लिए पांच एकड़ जमीन देने का निर्णय हुआ है। यही भारत की न्याय व्यवस्था है।
-मनोज तिवारी, दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष

वर्षों से चले आ रहे श्री राम जन्मभूमि के कानूनी विवाद को इस निर्णय से अंतिम रूप मिला है। मैं भारत की न्याय प्रणाली का अभिनंदन करता हूं।
-श्याम जाजू (दिल्ली प्रदेश भाजपा प्रभारी)

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिस तरह से देशवासियों ने स्वागत किया है, उससे पूरे देश में एकता का संदेश गया है। मैं निर्णय से बहुत खुश हूं। भारत में कई बार विचारों की भिन्नता होती है, परंतु राष्ट्रीय मुद्दों पर हमने हमेशा एकता दिखाई है। **-विजय गोयल (रास सदस्य)**

इस फैसले से हिंदुओं के लिए मंदिर व मुसलमानों के लिए मस्जिद बनाने का रास्ता साफ हो गया है। यह न तो हिंदुओं की जीत है और न ही मुसलमानों की। यह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत की जीत है।
-विजेंद्र गुप्ता (दिल्ली विस में नेता प्रतिपक्ष)

दिल्ली-एनसीआर में खिली धूप, गिरा प्रदूषण का स्तर

राहत ▶ दिल्ली का एयर इंडेक्स 283 पर पहुंचा, अन्य शहरों में भी घाटा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में शनिवार को काफी गिरावट दर्ज हुई। दिनभर धूप खिली रही। तेज गति से हवा भी चली, जिसने प्रदूषक कणों को एक जगह ठहरने नहीं दिया और वह हवा के साथ आगे बढ़ गए।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के प्रदूषण मॉनीटरिंग स्टेशन में दिल्ली का एयर इंडेक्स शुक्रवार की तुलना में शनिवार को 47 अंक नीचे गिरकर 283 पर पहुंच गया, जो खराब श्रेणी में आता है। शुक्रवार को यह 330 दर्ज किया गया था, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी शुक्रवार की तुलना में शनिवार को प्रदूषण का स्तर गिरा है। लेकिन गाजियाबाद और नोएडा में अभी भी खराब श्रेणी में एयर इंडेक्स बना हुआ है। गाजियाबाद में शुक्रवार को एयर इंडेक्स 355 और नोएडा में 366 दर्ज हुआ था। शनिवार को यह गाजियाबाद में 307 और नोएडा में 302 पर पहुंच गया।

मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को दिनभर 20 से 25 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। रविवार को इसी गति से हवा के चलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि सोमवार से हवा की रफ्तार में कमी आएगी। हवा 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ही चलेगी। इसकी वजह से प्रदूषण का स्तर फिर से बहुत खराब श्रेणी में लौट सकता है। लेकिन दिल्ली में अगले तीन दिनों तक खतरनाक स्तर तक प्रदूषण के पहुंचने की संभावना नहीं है। प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी से बहुत खराब श्रेणी के बीच ही रहने की उम्मीद है।

मौसम विभाग के वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तर भारत में हाल ही में पश्चिमी विक्षोभ ने दस्तक दी थी। अब यह निकल गया है। इसके प्रभाव से उत्तर की दिशा से हवा दिल्ली में आ रही है। शनिवार को हवा के साथ ज्यादा मात्रा में नमी नहीं आई। साथ ही बादल भी नहीं छाए। इन सब की वजह से शनिवार को दिन भर धूप खिली रही। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इन्हीं सब कारणों से प्रदूषण के स्तर में गिरावट हुई है।

आज से तीन दिन तक ऑड-इवेन से छूट

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली में आज से तीन दिन तक ऑड-इवेन से छूट रहेगी। रविवार और 11 व 12 नवंबर को सभी तरह की कारें चलेंगी। गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। 11 नवंबर को नगर कीर्तन निकला जाएगा। 12 को गुरु पर्व है। इस दौरान सिख श्रद्धालुओं को परेशानी न हो इसलिए दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। इस योजना के छठे दिन भी कहीं से जाम लगने की सूचना नहीं है। दिल्ली सरकार का दावा है कि राजधानी में आज प्रदूषण कम हुआ है। उसमें ऑड-इवेन का भी महत्वपूर्ण रोल है क्योंकि 15 लाख कारें दिल्ली की सड़कों पर नहीं उतर रही हैं। इस योजना को सफल बनाने के लिए पांच हजार वॉलेंटियर्स और चार सौ टीमें लगाई गई हैं। डीटीसी और क्लस्टर की 5600 बसें सड़कों पर हैं। इसके अलावा 650 अतिरिक्त बसें भी लगाई गई हैं।

दिल्ली-एनसीआर का गिरा एयर इंडेक्स

स्थान	8 नवंबर	9 नवंबर
दिल्ली	330	283
फरीदाबाद	337	270
गाजियाबाद	355	307
गुरुग्राम	306	290
नोएडा	366	302
ग्रेटर नोएडा	367	278

ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन 13 से

जासं, नई दिल्ली : ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ खुदरा व्यापारियों ने आंदोलन की घोषणा की है। 13 नवंबर से शुरू होने वाले इस आंदोलन की तैयारियों को लेकर 10 नवंबर को व्यापारियों की आपात बैठक बुलाई गई है। इसमें आंदोलन को सफल बनाने की रणनीति पर चर्चा होगी। इस विरोध आंदोलन का नेतृत्व कंफेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) कर रहा है। कैट के महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि ई-कॉमर्स कंपनियों को नीति के सख्त पालन के निर्देश देने के बजाय सरकार उन्हें अपने मौजूदा व्यवसाय मॉडल के साथ व्यापार जारी रखने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि इसे देखते हुए कैट ने 10 नवंबर को दिल्ली में देश के सभी राज्यों के प्रमुख व्यापारी नेताओं की आपात राष्ट्रीय बैठक बुलाई है। इसमें 13 नवंबर से देशभर में ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ आंदोलन शुरू करने की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। कैट ने ट्रांसपोर्ट, लघु उद्योग, हॉकर्स किसानों, उपभोक्ताओं, स्व-नियोजित समूहों और महिला उद्यमियों के राष्ट्रीय संगठनों के नेताओं के साथ स्वदेशी जागरण मंच को भी बैठक में आमंत्रित किया है।

खंडेलवाल ने कहा कि ई-कॉमर्स कंपनियों के मनमानी तरीके से एफडीआइ नीति का उल्लंघन करने के कारण दिवाली के त्योहारी सीजन में खुदरा कारोबारियों को करीब 50 फीसद के व्यापार का नुकसान झेलना पड़ा है। इन कंपनियों द्वारा लागत से भी कम मूल्य पर माल बेचना, भारी डिस्काउंट देना, अपने पोर्टल पर कुछ विशेष विक्रेताओं को प्रमुखता देने जैसी व्यापार पद्धति अपनाई जा रही है जो सरकार की एफडीआइ नीति का सरासर उल्लंघन हैं।

सोशल मीडिया पर दिल्ली पुलिस की नजर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

अयोध्या मसले पर शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पूर्व ही दिल्ली को हाई अलर्ट कर दिया गया था। शुक्रवार को जैसे ही पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक व सुरक्षा एजेंसियों को पता चला कि शनिवार को इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा, वैसे ही चंद मिनट के अंदर सभी स्तर पर सुरक्षा तैयारियां शुरू कर दी गईं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर व बाहर पैरा मिलिट्री समेत दिल्ली पुलिस के कमांडो वर्दी व सादे कपड़ों में तैनात कर दिए गए। पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। नई दिल्ली जिले में धारा-144 लगा दी गई। सुबह होने तक राजधानी में दिल्ली पुलिस व पैरा मिलिट्री समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने मोर्चा संभाल लिया।

सोशल मीडिया पर कोई असामाजिक तत्व अफवाह न फैला सके, इसलिए दिल्ली पुलिस की साइबर सेल शुक्रवार से ही इस पर पैनी नजर रख रही थी। शुक्रवार व शनिवार दोनों दिन एडवाइजरी जारी कर लोगों से अपील की गई कि वे अफवाह से दूर रहें। किसी ने अफवाह फैलाई तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता अफवाह को रोकने की है। दिल्ली के सभी धार्मिक स्थलों व हर संवेदनशील जगह पर बड़ी संख्या में वर्दी व सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों, पैरा मिलिट्री के अलावा खुफिया विभाग के कर्मियों की तैनाती की गई है। दिल्ली पुलिस सड़कों पर उतर कर आम लोगों के बीच जाकर उनकी भावनाओं को महसूस कर रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि वे शांति और सौहार्द बनाए रखें। ऐसा कोई भी गैर कानूनी काम न करें, जिससे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल विवेक के साथ करें।

दिल्ली में शुक्रवार रात से ही गश्त बढ़ा दी गई थी। शनिवार सुबह कुछ संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद समेत सभी छोटी-बड़ी मस्जिदों के प्रवेश व निकास द्वारों के अलावा आसपास पुलिस की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। सुरक्षा जांच अच्छी तरह से की जा रही थी। संवेदनशील जगहों पर बैरिकेड लगाकर एहतियात के तौर पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। अवकाश होने के बावजूद दिल्ली पुलिस के सभी आला अधिकारी अपने-अपने इलाके में लगातार गश्त करते रहे। पुलिस हर जगह चुस्ती से मौजूद थी।

पुरानी दिल्ली में शनिवार को सुरक्षा का जायजा लेते पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक। साथ में अन्य वरिष्ठ अधिकारी। सौजन्य : दिल्ली पुलिस

संवेदनशील इलाकों में 26 कंपनी पैरा मिलिट्री तैनात

सभी जिलों के डीसीपी को शुक्रवार रात ही अलर्ट कर दिया गया था। उन्हें सभी क्षेत्रों में पुलिसकर्मियों को तैनात करने के लिए कहा गया। संवेदनशील इलाकों में 26 कंपनी पैरा मिलिट्री तैनात की गईं। सभी पीसीआर वैन, ईआरवी और पीसीआर से जुड़े बाइक सवार पुलिसकर्मियों को अधिक से अधिक गश्त करने के निर्देश दिए गए। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक ने विशेष आयुक्त क्राइम ब्रांच सतीश गोलचा के साथ शाम को पुरानी दिल्ली के कई इलाकों में जाकर सुरक्षा-व्यवस्था का जायजा लिया।

धर्मेंद्र ने संभाला एनडीएमसी चेयरमैन का कार्यभार

धर्मेंद्र ने शनिवार को नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) के चेयरमैन का कार्यभार संभाल लिया। इसके बाद ही उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर परिषद की गतिविधियों की जानकारी ली। उल्लेखनीय है कि जुलाई में नरेश कुमार का तबादला बतौर अरुणाचल के मुख्य सचिव के तौर पर हुआ था। तब से एनडीएसमसी चेयरमैन की अतिरिक्त जिम्मेदारी दिल्ली के मुख्य सचिव विजय कुमार देव संभाल रहे थे। जागरण

पूर्व कैप्टन की तिहाड़ में संदिग्ध हालात में मौत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : तिहाड़ जेल संख्या आठ-नौ में बंद एक विचाराधीन कैदी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। मृतक की पहचान मुकेश अरोड़ा (63) के रूप में हुई है। इस मामले की जांच मजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही है। मुकेश सेना में कैप्टन रह चुके थे और उनके पास अमेरिका व कनाडा की नागरिकता थी। मुकेश दिल्ली कैंट थाना में दर्ज चोरी के एक मामले में आरोपित थे। इस मामले में मुकेश पर जासूसी का आरोप लगा था। इसके बाद खुफिया एजेंसियों व दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूछताछ भी की। बाद में सेना के पुस्तकालय से किताबों की चोरी के आरोप में मुकेश को गिरफ्तार किया गया था। जेल में मौत के मामले को देखते हुए हरिनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

जेल अधिकारियों के मुताबिक मुकेश को जेल में पहली मंजिल पर बने कमरे में ले जाया जा रहा था। पहली मंजिल पर पहुंचते ही वह नीचे गिर गए। अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि मौत की वजह खुदकशी है या कुछ और। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है ताकि सही कारण का पता चल सके।

फरीदाबाद में दंपती सहित चार की गला रेतकर हत्या

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद

सेक्टर-7ए में शुक्रवार रात बुजुर्ग दंपती और उनके बेटी-दामाद की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। मृतकों में 60 वर्षीय प्रवीन मेहंदीरत्ता, उनकी पत्नी 55 वर्षीय भारती, बेटी प्रियंका और दामाद सौरभ कटारिया शामिल हैं। सौरभ कटारिया मूलरूप से मेरठ के रहने वाले थे। इस समय पत्नी के साथ गाजियाबाद वैशाली में रहते थे। बेटी और दामाद शुक्रवार रात में मेहंदीरत्ता दंपती से मिलने आए थे। प्रवीन मेहंदीरत्ता रेडियोलॉजिस्ट थे। घर पर ही सावित्री एक्सरे नाम से रेडियोलॉजी लैब चलाते थे। मेहंदीरत्ता दंपती यहां बेटे दर्पण के साथ रहते थे। बेटा गुरुग्राम स्थित कंपनी में इंजीनियर है। शुक्रवार को उसकी नाइट शिफ्ट थी। रात 9.30 बजे वह ड्यूटी चले गए थे। शनिवार को दोपहर डेढ़ बजे तक जब दंपती का घर नहीं खुला तो पड़ोसियों को संदेह हुआ। वे उनके घर गए तो वारदात का पता चला। हत्या के कारण व हत्यारे का पता नहीं चला है। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिली है, जिसमें एक स्कूटी सवार रात में घर के अंदर जाता व बाहर आता दिख रहा है। पुलिस को संदेह है कि उसी ने हत्या को अंजाम दिया। पुलिस इसे रंजिशन हत्या मान रही है। पुलिस ने बेटे दर्पण की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर, शव पोस्टमॉर्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल में रखवाए हैं।

दर्पण ने पुलिस को बताया है कि वह सुबह छह-सात बजे तक ड्यूटी से लौट आते थे। मगर शनिवार को वह दोस्तों के साथ रुक गए थे। दोपहर में उन्हें पड़ोसी सुनील गर्ग ने फोन पर सूचना दी कि घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कोई फोन भी नहीं उठा रहा। तब वे गुरुग्राम से लौटे। उससे पहले पुलिस उनके घर पहुंच चुकी थी।

बेटी-दामाद की हत्या के लिए 45 मिनट किया था इंतजार

हरेंद्र नागर, फरीदाबाद : सेक्टर-7ए में मेहंदीरत्ता दंपती व उनके बेटी-दामाद की हत्या मामले में क्राइम सीन की गहनता से जांच के बाद पुलिस को कई अहम बिंदू मिले हैं। घर में किसी की जबरन एंट्री या लूटपाट के सबूत न मिलने से पुलिस का निष्कर्ष है कि किसी बेहद नजदीकी व्यक्ति ने रंजिश में हत्या को अंजाम दिया है। पड़ोसी सतीश गर्ग के घर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज व क्राइम सीन के मिलान से पता चलता है कि हमलावर ने पहले मेहंदीरत्ता दंपती की हत्या की। इसके बाद करीब 45 मिनट घर में बैठकर उनके बेटी व दामाद के आने का इंतजार किया। उनकी हत्या के करीब आधे घंटे बाद वह फरार हुआ। सीसीटीवी कैमरे की दूरी व अंधेरे के कारण न स्कूटी सवार का चेहरा दिखा, न स्कूटी का नंबर या रंग।

पुलिस का अनुमान है कि हमलावर को मालूम था कि मेहंदीरत्ता दंपती के बेटी व दामाद आने वाले हैं। सीसीटीवी फुटेज में स्कूटी सवार रात करीब 10.30 बजे मेहंदीरत्ता दंपती के घर के बाहर पहुंचा। स्कूटी बाहर खड़ी कर वह घर के अंदर चला गया। करीब 11.15 बजे मेहंदीरत्ता दंपती के बेटी व दामाद घर के अंदर जाते दिखे। करीब 11.45 बजे स्कूटी सवार घर के बाहर जाता दिखा। पुलिस को प्रवीन मेहंदीरत्ता का शव बेसमेंट में बनी लैब में कुर्सी पर पड़ा मिला। उनकी पत्नी भारती का शव बेडरूम में पड़ा मिला। बेटी व दामाद के शव बिल्कुल घर के दरवाजे पर मिले हैं। सभी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई है। शरीर पर चाकू घोपे जाने के भी निशान हैं। बेसमेंट में एक्सरे मशीन चालू मिली है। यह मशीन तभी चालू की जाती है जब किसी का एक्सरे करना हो। वैसे भी प्रवीन रात के 10.30 बजे किसी जानकार का ही एक्सरे कर सकते हैं, अन्य को वे सुबह आने को बोल देते। पुलिस का निष्कर्ष है कि 10.30 बजे आया हमलावर एक्सरे कराने के बहाने प्रवीन मेहंदीरत्ता को बेसमेंट में लेकर गया। जैसे ही प्रवीन ने मशीन चालू की, उसने उनका गला रेत दिया। इसके बाद ऊपर आकर बेडरूम में भारती की हत्या की। इसके बाद उसने बेटी व दामाद के आने का इंतजार किया। रात 11.15 बजे पहले बेटी प्रियंका अंदर आई और दामाद सौरभ कटारिया कार खड़ी करने लगे। उसने गेट पर ही प्रियंका की हत्या कर दी। इसके बाद जैसे ही सौरभ कटारिया अंदर आए, उसने उनकी भी हत्या कर दी। उसने 11.45 बजे तक उनके दम तोड़ने का इंतजार किया। इसके बाद फरार हो गया।

कामयाबी

वसंत कुंज निवासी राजवीर सिंह के दिल में कैथेटर के जरिये लगाया वाल्व, किसी सरकारी अस्पताल को पहली बार मिली सफलता

सफदरजंग अस्पताल में ओपन सर्जरी के बिना बदला वाल्व

रणविजय सिंह, नई दिल्ली

देश में पहली बार सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने ओपन सर्जरी के बगैर हृदय में वाल्व लगाने में कामयाबी हासिल की है। सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों ने वसंत कुंज निवासी राजवीर सिंह (68) के दिल में कैथेटर के जरिये वाल्व लगाया। पिछले माह डॉक्टरों ने यह प्रक्रिया अपनाई। इसमें कोई सर्जरी नहीं की गई। डॉक्टरों का कहना है कि पहली बार किसी सरकारी अस्पताल ने यह उपलब्धि हासिल की है।

चिकित्सा क्षेत्र में उपलब्धियों की बात आती है तो अक्सर सरकारी क्षेत्र के अस्पतालों में एम्स, पीजीआइ चंडीगढ़ जैसे अस्पतालों का नाम जुड़ा होता है। हृदय की बीमारियों के इलाज के मामले में एम्स के नाम कई उपलब्धियां जुड़ी हैं, लेकिन ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट (टीएवीआर) के मामले में सफदरजंग अस्पताल ने बाजी मार ली है। कार्डियोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. संदीप बंसल के नेतृत्व में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रीति गुप्ता और डॉ. अनुभव गुप्ता ने बुजुर्ग को वाल्व लगाया।

सफदरजंग अस्पताल में मरीज राजवीर सिंह के साथ डॉक्टरों की टीम। सौजन्य : डॉक्टर

डॉ. प्रीति ने बताया कि मरीज के एओर्टिक वाल्व में ब्लॉकेज था। इस वजह से दिन में दो-तीन बार उन्हें बेहोशी हो रही थी। मरीज के जीवित रहने की संभावना एक माह से भी कम थी। दिक्कत यह थी कि उन्हें रीढ़ की हड्डी से जुड़ी कयफोसकोलिओसिस बीमारी है। इसके अलावा वह सांस की पुरानी बीमारी सीओपीडी (क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज) से पीड़ित हैं। इस कारण उन्हें एनेस्थीसिया (बेहोशी की दवा) देने में जोखिम था। कई अस्पतालों ने उनकी सर्जरी करने से इन्कार कर दिया था। उन्हें दोबारा सर्जरी के लिए ऑपरेशन थियेटर (ओटी) में ले जाने के बावजूद सर्जरी के बगैर लाना पड़ा था। इसके बाद सफदरजंग के डॉक्टरों ने सर्जरी के बिना उन्हें वाल्व लगाने का फैसला किया, ताकि बेहोश करने की जरूरत न पड़े। इसके बाद डॉक्टरों ने पेट व जांघ के बीच के हिस्से (ग्रॉइन) की धमनी के जरिये ट्रांसकैथेटर को दिल में ले जाकर वाल्व लगाया।

निजी अस्पताल में आता है इस प्रक्रिया में 20 लाख तक खर्च : निजी क्षेत्र के कई बड़े अस्पतालों में यह सुविधा पहले शुरू हो चुकी है। लेकिन इस प्रक्रिया में मरीज को 20 लाख रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं। सफदरजंग अस्पताल में मरीज को सिर्फ वाल्व की कीमत (12.48 लाख) देनी पड़ी। अब सफदरजंग अस्पताल में मरीजों को कम कीमत में यह सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सुनील गुप्ता ने कहा कि सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक में चार कैथ लैब व अत्याधुनिक आइसीयू की सुविधा विकसित की गई है। इससे डॉक्टर अब इस तरह की सुविधा मरीजों को दे पा रहे हैं।

कम हुए वाहन तो टोल कंपनी ने मांगी 450 करोड़ की छूट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे से दिल्ली में व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश कम होने से टोल वसूलने वाली कंपनी ने 450 करोड़ रुपये की छूट मांगी है। कंपनी ने कहा कि दिल्ली में वाहनों का प्रवेश कम हो गया है। इसका सीधा असर टोल वसूली से होने वाली उनकी आय पर हुआ है। इसलिए निगम द्वारा उन्हें 450 करोड़ रुपये की वार्षिक छूट दी जानी चाहिए। हालांकि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति ने पिछली बैठक में इस प्रस्ताव को भी टाल दिया है, लेकिन निगम इस प्रस्ताव को नहीं मानेगा तो टोल वसूलने वाली कंपनी इस कार्य से हाथ खड़े कर सकती है। इससे निगम को आने वाले वर्षों में आर्थिक नुकसान हो सकता है।

प्रस्ताव में कंपनी ने दावा किया है कि फ्री लेन से दिल्ली में 35 हजार वाहन प्रतिदिन प्रवेश कर रहे हैं। वहीं ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल-वे की वजह से दिल्ली में प्रतिमाह 90 हजार वाहनों का प्रवेश कम हो गया है। निगम ने 1206 करोड़ रुपये के वार्षिक शुल्क पर दिल्ली में टोल वसूली का कार्य एक निजी कंपनी को दे रखा है। कंपनी का कहना है कि कोर्ट का इसमें पहले से ही निर्देश है कि उन्हें फ्री लेन में जाने से रोका नहीं जा सकता। इसलिए ऐसे वाहनों पर लगाम लगाने के लिए कंपनी के पास कोई विकल्प नहीं है। हालांकि निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इतनी छूट नहीं दे सकते हैं। टेंडर की सेवा शर्तों में इसका प्रावधान नहीं है।

दिल्ली में टोल वसूली से निगमों को 1206 करोड़ की आय होती है। टोल वसूलने वाली कंपनी कार्य छोड़ देती है तो निगम को आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसका असर निगमों के बजट पर पड़ सकता है। तीनों निगम इस समय खराब आर्थिक हालातों का सामना कर रहे हैं। अगर टोल वसूली से आय कम होती है तो उनके राजस्व नुकसान का खामियाजा कर्मचारियों को वेतन और अन्य के रूप में उठाना पड़ सकता है।

80 एनआरआइ केंद्र सरकार के न्योते पर आए हैं करतारपुर साहिब के दर्शनों को। आशा जताई है कि कॉरिडोर को खोलने का फैसला दोनों देशों के संबंध सुधारने का सुनहरा मौका हो सकता है।

श्रद्धा में डूबे मोदी, बाबा नानक के दर पर माथा टेक की अरदास

प्रकाशोत्सव ▸ पंजाब के मुख्यमंत्री ने किया प्रधानमंत्री का स्वागत, कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले सुल्तानपुर लोधी में लिया श्री गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद

पीएम ने जप स्थान भौरा साहिब में जाकर की अरदास संगत को दीं बधाइयां

मनोज त्रिपाठी/हरनेक सिंह, सुल्तानपुर लोधी (कपूरथला)

आस्था व श्रद्धा में डूबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले सुल्तानपुर लोधी के ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री बेर साहिब में माथा टेककर आशीर्वाद लिया। करीब 11 मिनट तक मोदी गुरुद्वारा परिसर में रुके। मोदी को गुरुद्वारा साहिब के पीछे बने नए द्वार से कड़ी सुरक्षा के बीच अंदर लाया गया।

नीली जैकेट व पीले रंग का कुर्ता पहने प्रधानमंत्री जैसे ही गुरुद्वारा परिसर पहुंचे तो केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल व पंजाब के गर्वनर वीपी सिंह बदनौर के अलावा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनका स्वागत किया। पास ही खड़ी एसजीपीसी की पूर्व प्रधान बीबी जागीर कौर पर जैसे ही मोदी की नजर पड़ी तो उन्होंने उनके पास जाकर उनसे मुलाकात की और करीब दो मिनट तक गुफ्तगू की। भाजपा की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला व पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया ने भी मोदी का स्वागत किया।

तय कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री के करीब नौ बजे सुल्तानपुर लोधी पहुंचने की सूचना मिलते ही गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने आई संगत में भी उनकी झलक पाने की ललक दिखाई दी। इस दौरान उत्साह से भरे मोदी के चेहरे पर बाबा नानक से आशीर्वाद लेने की खुशी स्पष्ट झलक रही थी। उन्होंने सबसे पहले गुरुद्वारा श्री बेर साहिब में माथा टेका और फिर गुरु नानक देव जी के जप स्थान भौरा साहिब में जाकर अरदास की। बाबा नानक के हाथों से लगे बेरी के पेड़ को भी नमस्कार किया और संगत को प्रकाशोत्सव की बधाई दी। प्रधानमंत्री को बीबी जागीर कौर ने सिरोपा व किरपाण भेंटकर सम्मानित किया। मोदी ने गुरुद्वारा श्री केसगढ़ साहिब के जत्थेदार भाई रघुवीर सिंह से भी मुलाकात की।

गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में गुरदासपुर जिले के भारत-पाक सीमा पर डेरा बाबा नानक में करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले हुई जनसभा में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीरी साहिब देकर सम्मानित किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर, शिअद अध्यक्ष सुखबीर बादल, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्वेत मलिक, केंद्रीय राज्य मंत्री हरदीप सिंह मौजूद रहे। जागरण

सियासत में दिखी भाईचारक सांझ

भूपेंदर सिंह भाटिया, डेरा बाबा नानक (गुरदासपुर)

- पाकिस्तान के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवर रहे नरम
- मोदी ने कैप्टन अमरिंदर की तारीफ की, कैप्टन ने भी उनके कार्य को सराहा
- हरसिमरत कौर व सुखबीर बादल ने भी कैप्टन को दिया पूरा सम्मान

श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर सुल्तानपुर लोधी (कपूरथला) से लेकर डेरा बाबा नानक (गुरदासपुर) तक आयोजित कार्यक्रमों में शनिवार को गुरु नानक की भाईचारक सांझ देखने को मिली। आमतौर पर पाकिस्तान पर आक्रामक रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाज आज बदला-बदला नजर आया। पंजाब के राजनेता भी गुरु नानक देव जी के भाईचारे के संदेश पर अमल करते नजर आए और सियासत की बर्फ पिघलती दिखी।

डेरा बाबा नानक की धरती पर सभी का ध्यान प्रधानमंत्री के भाषण पर केंद्रित था, लेकिन उन्होंने अपने 26 मिनट के भाषण में सिर्फ एक बार पाकिस्तान का जिक्र किया। पाक के प्रधानमंत्री इमरान खान का कॉरिडोर के लिए आभार जताया और उनका धन्यवाद किया। यह अलग बात है कि पाक में इमरान ने ऐसा कोई सद्भाव नहीं दिखाया और वे कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए मोदी पर तल्ख दिखे।

कांग्रेस पर निशाना साधने वाले मोदी ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि कैप्टन के नेतृत्व में राज्य सरकार ने तय समय सीमा में कॉरिडोर के सारे निर्माण कार्य करवाने में मदद कर सराहनीय काम किया है। कैप्टन ने भी कहा कि कॉरिडोर निर्माण में प्रधानमंत्री ने जो योगदान किया है, वह अतुलनीय है। मैंने पंजाब के हर ऐतिहासिक स्थानों में माथा टेका है, लेकिन करतारपुर की इच्छा आज पूरी हो रही है। कैप्टन ने अपने भाषण में बादल साहब कहकर उनकी बातों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मैं बादल साहब की उस बात से सहमत हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि सिख संगत 70 साल से अरदास कर रही थी और अब प्रधानमंत्री ने उसे पूरा कर दिया। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इतना बड़ा काम किया। कैप्टन ने आज बादल साहब कहकर संबोधित किया, जबकि छह नवंबर को पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में कैप्टन ने सदन में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम तो लिया था, लेकिन सबसे बुजुर्ग नेता और पांच बार मुख्यमंत्री रहे बादल का नाम नहीं लिया था। बादल सदन में मौजूद थे, जबकि हुड्डा उस समय सदन में नहीं थे। आज बादल ने भी कैप्टन को मुख्यमंत्री साहब कहकर संबोधित किया।

सुल्तानपुर लोधी में गुरुद्वारा श्री बेर साहिब में प्रधानमंत्री के प्रवेश के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह पीछे रह गए तो हरसिमरत कौर बादल उन्हें सियासी दूरियां मिटाते हुए आगे लेकर आईं। इसी तरह डेरा बाबा नानक में जब प्रधानमंत्री को सम्मानित किया जा रहा था तो कैप्टन अमरिंदर कुछ दूर थे। अकाली दल के अध्यक्ष व सांसद सुखबीर सिंह बादल कैप्टन को आगे लेकर आए और उनके हाथ से प्रधानमंत्री को स्मृति चिह्न भेंट करवाया।

पाकिस्तान में स्वागत से गदगद सिद्धू इमरान से बोले- खोल दो बॉर्डर

इंद्रप्रीत सिंह, करतारपुर साहिब

भारत में राजनीति के हाशिए पर चल रहे नवजोत सिंह सिद्धू का पाकिस्तान में जोरदार स्वागत हुआ। इससे अभिभूत सिद्धू ने पाक के प्रधानमंत्री इमरान खान से भारत-पाक बॉर्डर को खोलने की मांग रख दी।

सिद्धू ने पाक सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा को पिछले साल डाली गई जफ्फी पर भी स्पष्टीकरण दिया। कहा, 'एक जफ्फी से लांघा खुल सकता है तो हमें ऐसी सौ जफ्फियां डालनी चाहिए। यह जफ्फी रंग ले आई है। अगर भारत-पाक बॉर्डर खोलने का एलान कर दें तो मैं मोदी जी को भी जफ्फी डालने को तैयार हूं, जब भी वह बुलाएंगे मैं जफ्फी डालने पहुंच जाऊंगा।' सिद्धू ने इमरान की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि सिकंदर ने जहां डराकर दुनिया जीती थी, वहीं इमरान दिलों को जीत रहे हैं। मेरे यार ने मेरे बाबे के घर को दस महीनों में ही स्वर्ग बना दिया है। सिद्धू ने कॉरिडोर खोलने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी खुलकर तारीफ की और धन्यवाद किया। सिद्धू ने कहा कि कहा कि 1947 के विभाजन का दंश पंजाब ने ही झेला है। 72 सालों से सिखों की इस कॉरिडोर को खोलने की आवाज किसी ने नहीं सुनी।

कैप्टन और मंत्रियों से बनाई दूरी, मनमोहन के छुए पांव : सिद्धू देश-विदश से आई सिख संगत के लिए तो आकर्षण का केंद्र थे, लेकिन अपने मंत्रियों से वे दूर ही रहे। यहां तक पूरे दौरे में उनकी कैप्टन अमरिंदर सिंह से बात तक नहीं हुई। सिद्धू सुबह जल्दी आ गए थे और पैसेंजर टर्मिनल के लाउंज में बैठे रहे। कैप्टन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही आए और पीएम के फ्लैग ऑफ करने के बाद कैप्टन कॉरिडोर की ओर चले गए। पूरे रास्ते दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। सीमा पार करते समय उनकी पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी गुरशरण कौर से मुलाकात हुई। उन्होंने उनके चरण छूकर आशीर्वाद भी लिया।

जब भारत में लोगों ने सिद्धू को घेरा : भारत लौटने पर जब सिद्धू कॉरिडोर से बाहर निकले तो वहां मौजूद लोगों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और समर्थन में जोरदार नारेबाजी की। लोगों ने कॉरिडोर खुलवाने का श्रेय सिद्धू को दिया।

पाकिस्तान के करतारपुर में शनिवार को गुरुद्वारा दरबार साहिब पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू। एएफपी

प्रतिक्रियाएं

72 सालों के बाद यह द्वार खुले हैं। मेरे जैसे किसी भी सिख के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। आज तो ऐसा लग रहा है कि करतारपुर साहिब जाने के लिए जाने वाले पहले जत्थे को खुद परमेश्वर लीड कर रहे हैं। हम तो बस दर्शन के लिए जा रहे हैं।

-ज्ञानी हरप्रीत सिंह, जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब

कॉरिडोर खुलना ऐतिहासिक कदम है। दोनों देशों की ओर से यह अच्छी शुरुआत हुई है। सिख संगत की बरसों पुरानी अरदास पूरी हुई है।

-मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री

मैं सबसे खुशकिस्मत व्यक्ति हूं। 72 साल से लोग अरदास कर रहे हैं। आज उनकी प्रार्थना पूरी हुई है।

-प्रकाश सिंह बादल, पूर्व सीएम

श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के समारोहों के हिस्से के तौर पर करतारपुर कॉरिडोर का खुलना दोनों देशों के बीच शांति और सद्भावना की शुरुआत सिद्ध होगा। गलियारा दोनों देशों के संबंधों को मजबूती प्रदान करने के अलावा श्री गुरु नानक देव जी की तरफ से दिए अमन, शांति और भाईचारे के संदेश का सूचक साबित होगा।

-कैप्टन अमरिंदर सिंह, मुख्यमंत्री पंजाब

सौहार्द, श्रद्धा व सत्कार... उस पार अपार

इंद्रप्रीत सिंह, करतारपुर साहिब (पाकिस्तान): करतारपुर साहिब कॉरिडोर खुला तो जैसे दिल भी खुल गए। जाने वाले जत्थों में शामिल सभी पार्टियों के नुमाइंदे एक दूसरे के साथ गले मिलते, उन्हें बधाइयां देते नहीं थक रहे थे। करतारपुर जाने से पहले तक यह राजनीति चल रही थी कि कौन जत्थे को लीड करेगा लेकिन श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह के लीड करने से यह दुविधा भी दूर हो गई। नवजोत सिंह सिद्धू को इमरान खान की ओर से न्योता मिला था। वह भी जत्थे का हिस्सा बने।

करतारपुर कॉरिडोर के जरिए जब पहला जत्था रवाना हुआ तो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह व उनका परिवार, पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह व उनकी पत्नी गुरशरण कौर, प्रकाश सिंह बादल व उनका परिवार और उनके सहायक ही गए। इसके बाद सभी को एक एक करके भेजा गया।

केंद्र सरकार के न्योते पर आए 80 एनआरआइ : केंद्र सरकार ने आज के दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए कनाडा, अमेरिका, इटली, जर्मनी और यूके आदि से एनआरआइ को भी बुलाया था। इटली के कुलवंत सिंह जो पहली बार करतारपुर जा रहे थे, ने आशा जताई कि कॉरिडोर को खोलने का फैसला दोनों देशों के संबंध सुधारने का सुनहरा मौका हो सकता है।

भारतीय करंसी चढ़ाकर ही माथा टेका : पाकिस्तान की ओर से प्रबंध ज्यादा अच्छे थे। बीस डॉलर की फीस आज के दिन पाकिस्तान ने माफ की थी। गुरुद्वार साहिब में खर्च के लिए सभी श्रद्धालुओं को करंसी बदलने का मौका दिया गया। लेकिन ज्यादातर श्रद्धालुओं ने भारतीय करंसी चढ़ाकर ही माथा टेका।

पाक से ज्यादा लोग थे आए हुए : गुरुद्वारा साहिब में हर तरफ 'जो बोले सो निहाल' के उद्घोष लग रहे थे। गुरुद्वारा साहिब के प्रांगण को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था और बिछाई गई दरियों पर तकिए भी रखे गए थे ताकि बुजुर्गों को बैठने में दिक्कत न आए। गुरुद्वारा साहिब में भारत से केवल 500 लोग गए थे जबकि पाकिस्तान की ओर से आने वाली की गिनती कहीं अधिक थी।

पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब में माथा टेकने की श्रद्धालुओं की अरदास आखिर 72 साल बाद पूरी हुई। इस दौरान श्रद्धालु सेल्फी लेकर इस ऐतिहासिक पल को कैमरे में कैद करते नजर भी आए। उनका कहना था कि दशकों बाद ऐसा सुनहरा पल आया है। उपेंद्र सेन गुप्त

मनोहर और दुष्यंत को भाजपा हाईकमान के बुलावे का इंतजार

विजेंद्र बंसल, नई दिल्ली

अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार संबंधी गतिविधियां और तेज हो गई हैं। शनिवार सायं हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला के साथ बैठकर मंत्रणा भी की।

सूत्र बताते हैं कि भाजपा हाईकमान की तरफ से मनोहर और दुष्यंत को एक साथ या अलग-अलग बुलावा आ सकता है। दोनों नेताओं के साथ विचार विमर्श के बाद अगले सप्ताह में मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय हो सकती है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा भवन में इस बाबत स्पष्ट संकेत दिए। चूंकि राज्यपाल 13 नवंबर तक अपने गृह राज्य में मांगलिक कार्य के लिए गए हैं, इसलिए माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख 13 नवंबर के बाद ही तय होगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान इस बार केंद्र से राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी मौजूद रहने की संभावना है। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य बताते हुए कहा कि यह ऐसा फैसला है जिसका दोनों पक्ष स्वागत कर रहे हैं।

दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भाजपा-जजपा गठबंधन की सरकार के लिए मंत्रिमंडल विस्तार प्राथमिकता का विषय नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार जब होगा तब होगा, फिलहाल सरकार प्रदेशवासियों को बेहतर शासन-प्रशासन देने के क्रम में काम कर रही है। नए चुने हुए विधायक भी बुधवार को खत्म हुए विधानसभा के विशेष सत्र के बाद अब अपने क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में भी प्रदेश से संबंधित कुछ विषय रहे हैं। ऐसे में धान की खरीद और पराली के प्रदूषण से निपटने के लिए भी सरकार ने कारगर कदम उठाए हैं।

भूस्खलन से जम्मू-श्रीनगर हाईवे फिर बंद, लगी वाहनों की कतार

जागरण संवाददाता, जम्मू

भारी बारिश और बर्फबारी के बाद बिगड़े मौसम में शनिवार को सुधार आया। सुबह जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर फंसे अधिकतर वाहनों को निकाला गया, लेकिन देर शाम जम्मू संभाग के रामबन जिले में हुए भूस्खलन के बाद राजमार्ग फिर बंद हो गया। अभी तक हवाई संपर्क भी बहाल नहीं हुआ है। पुंछ से कश्मीर को जोड़ने वाला मुगल रोड चौथे दिन भी बंद रहा। देर शाम रामबन में हुए भूस्खलन के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग फिर बंद हो गया। गत गत गुरुवार को हुई भारी बर्फबारी के कारण कश्मीर के सैड़कों क्षेत्र जिला मुख्यालयों से कटे हैं।

ट्रैफिक कंट्रोल रूम से मिली जानकारी अनुसार रामबन से दो किमी दूर महार के पास राजमार्ग पर पहाड़ों से भारी मात्र में मलबा गिरा जिससे मार्ग बंद हो गया। मलबा काफी होने के कारण हाईवे के रविवार को भी खुलने की संभावना कम है। अधिकारी ने बताया कि शनिवार सुबह वाहनों को दोनों तरफ से जाने की अनुमति दी गई थी। काफी संख्या में वाहनों को कश्मीर की तरफ छोड़ा गया। कश्मीर के निचले इलाकों में तो मौसम शुष्क रहा। उच्च पवर्तीय इलाकों में दिनभर हलकी बारिश होती रही। श्रीनगर व साथ सटे इलाकों में सुबह धुंध छाई रही। उसके बाद दिनभर आसमान घने बादलों से ढका रहा। श्रीनगर में अधिकतम तापमान 7.2, न्यूनतम तापमान 1.0 सेलिसयस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान भी वादी में कई स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। वहीं जम्मू में मौसम साफ रहा।

बर्फ में दबने से युवक की मौत : जम्मू के राजौरी के थन्नामंडी क्षेत्र के राजधानी गांव के रहने वाले युवक की पुंछ के सुरनकोट के बेहराम गाला के पास बर्फ में फंसने से मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि 35 वर्षीय जफर जावेद पोशाना से थानामंडी के रास्ते से जा रहा था। बेहराम गाला के पास एक ढलान से फिसल गया और वह बर्फ में दब गया जिससे उसकी मौत हो गई।

हिमस्खलन का खतरा : वादी में गुरुवार को हुई जबरदस्त बर्फबारी के चलते उच्च पर्वतीय इलाकों में हिस्खलन का खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने कुपवाड़ा, बांडीपुर, बारामूला, बड़गाम, शोपियां, अनंतनाग, कुलगाम व पुलवामा जिलों के उच्च पवर्तीय इलकों में रहने वाले लोगों को चलने फिरने में सावधानी बरतने की सलाह दे रखी है।

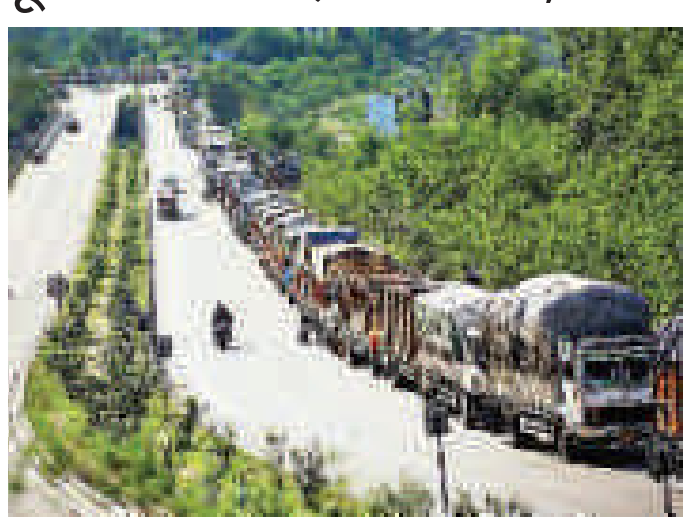

जम्मू संभाग के रामबन जिले में हुए भूस्खलन के बाद राजमार्ग में खड़े वाहन। प्रेट्र

10 बड़े हवाई अड्डों पर डीजीसीए ने एल्कोहल जांच शुरू की

नई दिल्ली, आइएएनएस : सुरक्षा मानक सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए देश के नागरिक उड्डयन नियामक ने देश के 10 हवाई अड्डों पर काम करने वाले कर्मचारियों की एल्कोहल जांच शुरू कर दी है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ब्रेथ एनलाइजर के जरिये एटीसी, विमान मेंटिनेंस और हवाई अड्डा संचालन कर्मचारियों की जांच करता है।

दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, अहमदाबाद, कोचीन, लखनऊ और गुवाहाटी में 10 हवाई अड्डों पर अनियमित रूप से जांच की गई है। शनिवार को जारी एक बयान में डीजीसीए ने कहा है कि हम देश के सभी मान्य हवाई अड्डों पर ब्रेथ एनलाइजर लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह काम 31 दिसंबर तक पूरा किया जाएगा। हर रोज 10 फीसद की अनियमित जांच की जाती है। अक्टूबर महीने में बीए पाजिटिव के 14 मामले मिले थे। नवंबर में अभी तक चार ऐसे मामले मिल चुके हैं।

तैयारी

वादी में ठंड के प्रकोप को देखते हुए किया जा रहा विचार, पीपुल्स कांफ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन को भी लाया जाएगा जम्मू

जम्मू शिफ्ट किए जा सकते हैं फारुक, उमर और महबूबा

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) के अध्यक्ष डॉ. फारुक अब्दुल्ला, उनके पुत्र उमर अब्दुल्ला और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को अगले चंद दिनों में श्रीनगर से शरदकालीन राजधानी जम्मू में स्थानांतरित किया जा सकता है। राज्य प्रशासन ने तीनों नेताओं को वादी में ठंड के प्रकोप को देखते हुए जम्मू में किसी उपयुक्त जगह पर हिरासत में रखने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया है। इनके अलावा पीपुल्स कांफ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन को भी जम्मू लाया जा सकता है, जबकि शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर परिसर में स्थित सेंटूर होटल में रखे गए 34 अन्य नेताओं में से अधिकांश को रिहा करने व एक दर्जन के करीब को एमएलए हॉस्टल श्रीनगर या फिर सोनवार के आसपास एक निजी होटल में रखे जाने की योजना है।

सूत्रों ने बताया कि डॉ. फारुक अब्दुल्ला की किडनी का ऑपरेशन हो चुका है। इसके अलावा वह हृदयरोग और शुगर से भी पीड़ित हैं। महबूबा मुफ्ती का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उनकी बेटी इल्तिजा ने भी कई मंचों पर अपनी मां की बीमारी का हवाला देते हुए उन्हें किसी ऐसी जगह स्थानांतरित करने का आग्रह किया है, जहां ठंड कम हो। सज्जाद गनी लोन का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। प्रशासन नहीं चाहता कि ठंड के मौसम में विशेषकर जब कश्मीर में बर्फ से सब कुछ ठप होता है, इन नेताओं के स्वास्थ्य पर किसी तरह का दुष्प्रभाव हो और जिसके लिए उसकी फजीहत हो। इसलिए वह इन्हें शरदकालीन राजधानी जम्मू में किसी उचित जगह पर हिरासत में रखने पर विचार कर रहा है।

पांच अगस्त को केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को लागू करने का फैसला लिए जाने से पूर्व चार अगस्त की मध्यरात्रि को राज्य सरकार ने एहतियात के तौर पर नेशनल कांफ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) पीपुल्स कांफ्रेंस, अवामी इत्तेहाद पार्टी, माकपा व कांग्रेस समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को हिरासत में लिया या फिर उन्हें नजरबंद बनाया था। हिरासत में लिए गए अधिकांश नेताओं को रिहा कर दिया गया है। डॉ. फारुक अब्दुल्ला को तीन माह के लिए पीएसए के तहत उनके ही घर में बंदी बनाकर रखा गया है। उमर अब्दुल्ला को हरि निवास में और महबूबा मुफ्ती को चश्माशाही के पास एक सरकारी गेस्ट हाउस में एहतियातन हिरासत में रखा गया है। सज्जाद गनी लोन समेत करीब 50 नेताओं को सेंटूर होटल में रखा गया था। इसे सब जेल का दर्जा दिया गया है। सेंटूर में रखे गए करीब 50 में से 16 नेताओं को रिहा किया जा चुका है। इसके अलावा दूसरी जगहों पर रखे गए 35 अन्य नेताओं को भी रिहा किया गया है।

सूत्रों ने बताया कि सेंटूर प्रबंधन द्वारा करीब पौने तीन करोड़ रुपये का बिल थमाए जाने के बाद से ही राज्य प्रशासन अब वहां रखे गए नेताओं के लिए वैकल्पिक स्थान का तलाश रहा है। प्रशासन ऐसी जगह की तलाश में है, जहां उसे इन नेताओं को आम लोगों से दूर रखते हुए सुरक्षा कवच तैयार करने में कोई ज्यादा दिक्कत न हो। उन्होंने बताया कि राज्य प्रशासन की फिलहाल सेंटूर प्रशासन से बातचीत चल रही है, ताकि वहां ठंड से बचाव की पर्याप्त सुविधा का बंदोबस्त करते हुए किराया दर को कम किया जा सके। इसके अलावा सोनवार और बादामी बाग इलाके में स्थित एक निजी होटल प्रबंधन के साथ भी इस सिलसिले में संवाद किया गया है।

उन्होंने बताया कि राज्य गृह विभाग ने राज्य एस्टेट विभाग से भी संपर्क किया है और उसे श्रीनगर में कोई उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराने के लिए कहा है। इसके अलावा एमएलए हॉस्टल श्रीनगर का भी दो दिन पूर्व राज्य पुलिस और गृह विभाग के अधिकारियों ने दौरा कर वहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया है। कहा जा रहा है सेंटूर में रखे गए नेताओं को एमएलए हॉस्टल में भी स्थानांतरित करने का एक विकल्प संबंधित प्रशासन ने अपने पास रखा है। ऐसी स्थिति में सेंटूर में इस समय बंद 34 नेताओं में से करीब 19 को रिहा किया जाएगा और 14 को एमएलए हॉस्टल में रखा जाएगा। इसके अलावा वहां बंद पीपुल्स कांफ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन को जम्मू में स्थानांतरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रिहा किए जाने वाले संभावित नेताओं में अधिकांश बुजुर्ग हैं और वह हालात को सामान्य बनाए रखने में सहयोग के लिए बांड देने को भी तैयार हैं।

कटड़ा-दिल्ली एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर का सर्वे पूरा

राज्य ब्यूरो, जम्मू

- अब दूसरे चरण का काम शुरू होने का रास्ता साफ
- कॉरिडोर के निर्माण पर आएगी 35 हजार करोड़ की लागत

575 किलोमीटर लंबे कटड़ा-दिल्ली एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर के निर्माण के लिए सर्वे का काम पूरा हो गया है। मैसर्स फीडबैक कंसल्टेंट लिमिटेड द्वारा प्रारंभिक चरण का काम पूरा होने के बाद अब दूसरे चरण का काम शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। इस रास्ते के साथ पठानकोट-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को फोरलेन से सिक्सलेन करने का काम भी होगा।

नेशनल हाईवे अथारिटी ऑफ इंडिया से अपडेट हासिल करने के बाद डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि उन्होंने दो साल पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के पास प्रस्ताव रखा था। उन्हें इस बात की खुशी है कि प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि 575 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर पर करीब 35 हजार करोड़ रुपये खर्च आएंगे। यह कटड़ा से दिल्ली को अमृतसर के रास्ते जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर की विशेषता यह है कि यह दिल्ली को दो धार्मिक शहरों कटड़ा और अमृतसर से जोड़ेगा। श्रद्धालु अब इससे अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर और श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। हालांकि इसके निर्माण में अभी कुछ देरी हो सकती है। इसमें अभी वन विभाग से भी स्वीकृति लेनी है, लेकिन एक बार यह सड़क बनने से दिल्ली से कटड़ा आने के समय में कटौती हो जाएगी। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि एक दिन आएगा जब लोग कटड़ा से दिल्ली सड़क के रास्ते जाने को प्राथमिकता देंगे। ट्रेन और हवाई मार्ग की अपेक्षा सड़क मार्ग पर जाना आसान और सस्ता होगा। इसी बीच नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने डॉ. जितेंद्र सिंह को कठुआ और ऊधमपुर में बन रहे देश के पहले दो हाईवे विलेज की स्थिति के बारे में भी जानकारी दी।

89 ब्लॉक प्रमुखों में से आधे से अधिक (53) पर भाजपा ने जीत दर्ज की है उत्तराखंड में। 20 ब्लॉकों में निर्दलीय उम्मीदवारों ने पाई है विजय। 18 ब्लॉक प्रमुखों के साथ कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
रविवार 10 नवंबर 2019

समान नागरिक संहिता का आ गया समय

बोले राजनाथ ▸ राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट, बढ़ेगा सर्व धर्म समभाव

रक्षा मंत्री ने कहा, भारत में एक-दूसरे को जोड़ती है संस्कृति, इस्लाम के भी हैं 72 फिरके

राज्य ब्यूरो, देहरादून

देहरादून में शनिवार को उत्तराखंड राज्य के 20वें स्थापना दिवस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विकास पुस्तिका का विमोचन किया। साथ में हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, सांसद लक्ष्मी शाह और अजय भट्ट। जागरण

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लैंडमार्क जजमेंट करार देते हुए कहा कि फैसले का सुप्रीम सम्मान भी होना चाहिए। समान नागरिक संहिता पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इसका समय आ गया है।

उत्तराखंड राज्य के 20वें स्थापना दिवस समारोह में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री आवास में मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि इससे सर्व धर्म समभाव को मजबूती मिलेगी। आपस में लोगों रिश्ते मजबूत होंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस फैसले को किसी की हार या जीत के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुछ नेताओं के असंतोष जाहिर किए जाने के मामले में उन्होंने टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया। देश में समान नागरिक संहिता पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने जवाब दिया, अब समय आ गया है।

भारत में संस्कृति एक-दूसरे को जोड़ती है : इससे पूर्व परेड मैदान में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत ही ऐसा देश है जहां संस्कृति एक-दूसरे को जोड़ती है। सहिष्णुता, सर्व धर्म समभाव, विविधता में एकता, वीरता और सामर्थ्य की यह अद्भुत संस्कृति और सांस्कृतिक पहचान पूरे देश को राष्ट्र बनाती है। केवल भारत में ही इस्लाम के 72 फिरके मिलते हैं। इस्लाम को मानने वाले किसी देश में इतने फिरके नहीं मिलते। देश की सांस्कृतिक ताकत का हवाला देने के लिए उन्होंने पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू, अल्लामा इकबाल और स्वामी विवेकानंद का जिक्र भी किया।

उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू ने लंबे समय तक विदेशों में शिक्षा प्राप्त की, लेकिन भारत में आने पर उन्होंने भी सांस्कृतिक एकता को अनुभव किया। इकबाल के शेर 'यूनान, मिस्र, रोमां सब मिट गए जहां से, का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि विविधता में एकता पैदा करने का यही काम भारतीय संस्कृति करती है। दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम् का संदेश देने वाला भारत ही है। प्राचीनकाल में भारत समृद्ध राष्ट्र था। हमारे प्राचीन सांस्कृतिक मूल्यों को ताकत देने का काम नौजवान ही कर सकता है। समारोह को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी संबोधित किया।

उप्र के 433 माध्यमिक कॉलेज काली सूची में

राज्य ब्यूरो, प्रयागराज : माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने हाई स्कूल व इंटर परीक्षा 2020 के लिए डिबार सूची जारी कर दी है। प्रदेश भर के 433 माध्यमिक कॉलेज इस वर्ष परीक्षा केंद्र नहीं बन सकेंगे। इस काली सूची में सबसे अधिक माध्यमिक कॉलेज अलीगढ़ जिले के हैं, जबकि दूसरे नंबर पर प्रतापगढ़ है। बोर्ड प्रशासन ने अपनी वेबसाइट पर काली सूची में कॉलेजों को क्यों डाला गया, इसका उल्लेख करते हुए लिस्ट जारी की है।

यूपी बोर्ड की 2020 परीक्षा के लिए शासन पिछले माह निर्देश जारी कर चुका है। उसी के अनुरूप सभी कॉलेजों से आधारभूत सुविधाओं का ब्योरा लिया गया। इसी माह परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी करनी है लेकिन, यह कार्य बिना डिबार लिस्ट फाइनल किए संभव नहीं था। इसलिए बोर्ड ने पिछले वर्ष की परीक्षा और पिछले वर्षों की परीक्षा में डिबार सूची पर मंथन किया उसे अनुमोदन के लिए शासन को भेजा। उस पर मुहर लगते ही शनिवार शाम को वेबसाइट पर डिबार सूची जारी कर दी गई है। सूची में लगभग सभी जिलों का जिक्र है, क्योंकि हर जिले में ऐसे कॉलेज रहे हैं, जो परीक्षा के दौरान गड़बड़ी होने पर डिबार किए गए।

433 की काली सूची में सबसे अधिक अलीगढ़ में 72, प्रतापगढ़ में 41, आजमगढ़ में 25, प्रयागराज में 24, आगरा में 22, बलिया में 21, मथुरा में 20, गाजीपुर में 14, मऊ व हाथरस में 10-10 और कौशांबी में तीन कॉलेजों को डिबार किया गया है। पहले पूरब के जिलों में ही यह संख्या बहुतायत में होती थी अब पश्चिम में भी ऐसे जिलों की संख्या बढ़ी है। यूपी बोर्ड अब जल्द ही परीक्षा केंद्रों की सूची जारी करके आपत्तियां मांगेगा।

ब्रोकर फर्मों का जाल बुनकर किया गया करोड़ों का खेल

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

पीएफ घोटाला

- 14 ब्रोकर फर्मों के जरिये हुआ था डीएचएफएल में निवेश

बिजली विभाग के कर्मियों की भविष्य निधि (पीएफ) की रकम लूटने के लिए ब्रोकर फर्मों का गहरा जाल बुना गया था। 14 ब्रोकर फर्मों के जरिये ही निजी कंपनी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) में निवेश किया गया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश व पड़ोसी राज्यों के कुछ जिलों के पतों पर रजिस्टर्ड इन फर्मों की विश्वसनीयता भी सवालों के घेरे में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक जिले के पते पर रजिस्टर्ड ब्रोकर फर्म का पता फर्जी निकलने के बाद ईओडब्ल्यू ने पूरे खेल की जांच और गहनता से शुरू कर दी है। ब्रोकर फर्मों के जरिये निवेश में कमीशन के बिंदु पर भी पड़ताल की जा रही है।

पीएफ घोटाले में आरोपित उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के पूर्व निदेशक एपी मिश्र, पूर्व निदेशक (वित्त) सुधांशु द्विवेदी व तत्कालीन सचिव ट्रस्ट पीके गुप्ता से पूछताछ में ब्रोकर फर्मों से जुड़े तथ्य सामने आए हैं। डीजी ईओडब्ल्यू डॉ. आरपी सिंह ने बताया कि 14 ब्रोकर फर्मों की पूरी पड़ताल कराई जा रही है। अब तक की जांच में यह भी सामने आया है कि दो फर्मों ने डीएचएफएल के अलावा अन्य कंपनियों के लिए भी काम किया है, जबकि 12 फर्में तो ऐसी हैं जो केवल यूपीपीसीएल के काम कर रही थीं। इन 12 फर्मों पर जांच एजेंसी का संदेह और गहरा गया है। पता लगाया जा रहा है कि कहीं इन फर्मों से आरोपित अधिकारियों या यूपीपीसीएल के अन्य बड़ों का कोई सीधा लिंक तो नहीं है। ब्रोकर फर्मों से जुड़े दो नाम ऐसे भी हैं, जो दो-तीन फर्मों के संचालक मंडल में शामिल हैं। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से सभी फर्मों का पूरा ब्योरा भी निकलवाया जा रहा है।

ईओडब्ल्यू ने आरोपित सुधांशु द्विवेदी व पीके गुप्ता की तीन दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड पूरी होने पर शनिवार को उन्हें लखनऊ जेल में दाखिल करा दिया। नोएडा में रियल एस्टेट का काम करने वाले पीके गुप्ता के बेटे के बारे में भी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। वह अब तक ईओडब्ल्यू के सामने नहीं आया है। ध्यान रहे, 4122.70 करोड़ के पीएफ घोटाले में हजरतगंज कोतवाली में एफआइआर दर्ज कराई गई है। सरकार के निर्देश पर इस मुकदमे की विवेचना ईओडब्ल्यू कर रही है। शासन ने पूरे प्रकरण की सीबीआइ जांच कराने की सिफारिश भी है।

एपी मिश्र से और पूछताछ की भी तैयारी : पूर्व निदेशक एपी मिश्र की पुलिस कस्टडी रिमांड की अवधि रविवार को पूरी हो जाएगी। इससे पूर्व ईओडब्ल्यू उनसे सिलसिलेवार पूछताछ कर रहा है। बताया गया कि ईओडब्ल्यू एपी मिश्रा की पुलिस कस्टडी रिमांड अवधि बढ़ाए जाने की मांग भी कर सकता है। अगली कड़ी में ईओडब्ल्यू तत्कालीन अध्यक्ष व अन्य अधिकारियों के बयान दर्ज करने की कार्रवाई करेगा।

मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की चाह पदोन्नत होकर हों सेवानिवृत्त

नईदुनिया, भोपाल

- कर्मचारियों ने अलग-अलग स्तर से शुरू किए पदोन्नति के प्रयास

सेवानिवृत्ति से पहले कर्मचारियों को पदोन्नति देना बेहद जरूरी है। वे पूरा जीवन सेवा में लगा चुके हैं और उन्हें अपना हक भी न मिले तो गलत है। सरकार को इस बारे में सोचकर रास्ता निकालना चाहिए।
-रमेश राठौर, अध्यक्ष, मप्र संविदा कर्मचारी महासंघ

प्रदेश में अधिकारियों-कर्मचारियों के पदोन्नति के रास्ते खुलने चाहिए। इसे लेकर समय-समय पर हम सरकार से गुहार लगाते रहे हैं। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा दो साल बढ़ाए जाने के बाद से सेवानिवृत्ति पर डेढ़ साल से रोक लगी हुई थी। अप्रैल 2020 के बाद से स्थिति फिर बिगड़ेगी। उससे पहले सरकार को कोर्ट से मंजूरी लेकर पदोन्नति शुरू करना चाहिए।
-लक्ष्मी नारायण शर्मा, महामंत्री, मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ

मध्य प्रदेश में दो साल के लिए सेवानिवृत्ति पर लगी रोक हटने का समय नजदीक आते ही कर्मचारियों को पदोन्नति की चाह सताने लगी है। अतिरिक्त दो साल सेवा का मौका मिलने के बाद भी कर्मचारी चाहते हैं कि वे पदोन्नत होकर ही सेवानिवृत्त हों, इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों और सरकार से गुहार लगाई जा रही है। शिवराज सरकार ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा दो साल बढ़ाई थी। यह अवधि मार्च 2020 में पूरी हो रही है। अप्रैल से सेवानिवृत्ति का सिलसिला शुरू हो जाएगा।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 को मप्र लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 खारिज कर दिया है। इसके बाद से प्रदेश में पदोन्नति पर रोक लगी हुई है। इस अवधि में करीब 55 हजार कर्मचारी बगैर पदोन्नति सेवानिवृत्त हो गए हैं। यदि सरकार सेवानिवृत्ति आयु सीमा नहीं बढ़ाती तो अब तक 25 से 30 हजार और कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाते। शिवराज सरकार के इस फैसले से कर्मचारी संतुष्ट दिखाई दे रहे थे, लेकिन सेवानिवृत्ति की घड़ी नजदीक आते ही कर्मचारियों की बेचैनी सामने आने लगी है। वे फिर से पदोन्नति की बात करने लगे हैं। इसे लेकर उनका ज्ञापन सौंपना, मंत्रियों और अधिकारियों से मिलना शुरू हो गया है।

वरिष्ठ पदों का ज्ञान रखने वाले नहीं बचेंगे : कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अप्रैल 2020 से अधिकारी और कर्मचारी तेजी से सेवानिवृत्त होंगे। ऐसे में वरिष्ठ पदों का ज्ञान रखने वाले नहीं बचेंगे। तब सरकार चलाने में दिक्कत होगी, क्योंकि लिपिकों का काम बढ़ गया है और उस अनुपात में कर्मचारियों की भर्ती हो नहीं रही। यदि सरकार नए कर्मचारी भर्ती करती भी है तो वे वरिष्ठ पदों का काम नहीं कर पाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट में है सरकार की अर्जी : कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों की स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश के कर्मचारियों को सशर्त पदोन्नति देने की अर्जी लगाई है, लेकिन कोर्ट ने अब तक अर्जी स्वीकार नहीं की है, जिसे देखते हुए इस संबंध में जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद कम ही लगती है। सरकार ने लोकसभा चुनाव के बाद कोर्ट में यह अर्जी दाखिल की है।

चिन्मयानंद प्रकरण में जेल में बंद छात्रा को माता-पिता का इंतजार

जासं, शाहजहांपुर : पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करने के आरोप में जेल में बंद छात्रा को माता-पिता के प्रयागराज से वापस आने का इंतजार है। दरअसल, इसी महीने के अंतिम सप्ताह से उसकी एलएलएम की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। इसलिए परीक्षा देने जाने के लिए उसे कोर्ट की अनुमति चाहिए होगी। छात्रा को एसआइटी ने 25 सितंबर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जिला जज की ओर से छात्रा की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। छह नवंबर को छात्रा की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी इसलिए उसके माता-पिता दो नवंबर की रात प्रयागराज रवाना हो गए थे। अब जमानत अर्जी पर सुनवाई 29 नवंबर को होनी है। लेकिन अब तक उसके माता-पिता वहां से लौटे नहीं हैं। शनिवार को उनके आने की संभावना थी, पर दोनों नहीं आए। छात्रा उनका इंतजार कर रही है क्योंकि उसकी एलएलएम की परीक्षाएं 26 नवंबर से शुरू हो रही हैं। छात्रा को परीक्षा देने के लिए कोर्ट से अनुमति लेनी होगी, पर इस पर निर्णय उसके माता-पिता ही आकर लेंगे। माना जा रहा है कि रविवार को वे लोग वापस आकर कोर्ट में अनुमति के लिए अर्जी दाखिल करने पर कोई निर्णय ले सकते हैं।

'बुलबुल' के चलते 23 उड़ानें रद, 12 घंटे बंद रहा कोलकाता एयरपोर्ट

जागरण संवाददाता, कोलकाता

बंगाल के दक्षिण 24 परगना में शनिवार को काकद्वीप में चक्रवात 'बुलबुल' के चलते गंगा सागर के लिए फेरी सेवा रोके जाने के बाद डॉक से लौटते श्रद्धालु। एएफपी

बंगाल की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे चक्रवात 'बुलबुल' ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। शुक्रवार की शाम से ही शुरू हुई बारिश शनिवार को भी जारी रही। इसका असर विमान सेवा पर भी पड़ा। ऐसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय (एनएससीबीआइ) हवाई अड्डा प्रबंधन की मानें तो शनिवार शाम छह बजे से अगले दिन यानी रविवार छह बजे तक हवाई अड्डा बंद रहेगा। इस दौरान यहां से कोई विमान उड़ान नहीं भरेगा।

उधर, खराब मौसम और कम रोशनी के चलते एनएससीबीआइ हवाई अड्डे से इंडिगो एयरलाइंस ने शनिवार की सुबह 11 बजे के बाद से उड़ान भरने वाली अपनी 23 उड़ानों को रद कर दिया। इसमें कोलकाता से रांची, पटना, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और पुणे आदि को जाने वाली विमान शामिल है। वहीं, अन्य विमानों ने विलंब से उड़ान भरी।

चक्रवात बुलबुल से निपटने को नौसेना तैयार : प्रचंड चक्रवात बुलबुल के प्रभाव से होने वाले किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए भारतीय नौसेना पूरी तरह तैयार है। नौसेना ने अपने विमानों और राहत सामग्री भरे तीन जहाजों को तैयार रखा है। रक्षा मंत्रालय की ओर से एक बयान में बताया गया कि पूर्वी नौसेना कमान बंगाल की ओर तेज गति से बढ़ रहे बुलबुल तूफान पर करीब से नजर बनाए हुए है। नौसेना की ओर से चक्रवाती तूफान को देखते मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी के साथ उन्हें करीबी बंदरगाहों व अन्य जगहों पर आश्रय लेने की भी सलाह दी गई है।

म्यांमार में बंधक बनाए गए उत्तराखंड के पूर्व सीएस व अन्य लोग लौटे

जागरण संवाददाता, देहरादून : भारत और म्यांमार को जोड़ने के लिए सड़क निर्माण की संभावना तलाशने गए उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव राकेश शर्मा और केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य में अहम भूमिका निभाने वाले अजय कोठियाल समेत चार भारतीय सकुशल वापस घर लौट आए हैं। इन सभी को म्यांमार की विद्रोही सेना अरक्कन ने बंधक बना लिया था। हालांकि, इस दौरान दिल्ली निवासी और दल के पांचवें सदस्य की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी।

भारत-म्यांमार को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए भारत सरकार 109 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना पर काम कर रही है। यह काम पिछले करीब पांच साल से अधर में लटका था। ऐसे में केदारनाथ पुनर्निर्माण के सफल कार्य को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव राकेश शर्मा को परियोजना को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। केदारनाथ में कार्य के अनुभव को देखते हुए पूर्व मुख्य सचिव ने उत्तराखंड के अजय कोठियाल समेत तीन और लोगों को म्यांमार सीमा पर रेकी कार्य के लिए अपने साथ शामिल कर लिया था। यह पांच सदस्यीय दल तीन नवंबर को म्यांमार पहुंचा था। इस दौरान म्यांमार का एक सांसद भी उसी क्षेत्र में था, जहां भारतीय दल पहुंचा था। इसे लेकर विद्रोही सेना अरक्कन ने म्यांमार सांसद समेत भारतीय दल के सभी पांच सदस्यों को भी बंधक बना लिया।

हालांकि, जब अरक्कन सेना को पता चला कि सांसद के अलावा अन्य लोग भारतीय नागरिक हैं तो उन्होंने इसकी पुख्ता तस्दीक के बाद सभी को रिहा करने का निर्णय लिया। दुर्भाग्यवश उसी दौरान दहशत के चलते भारतीय दल में शामिल दिल्ली निवासी वेणु गोपाल नाम के व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो गई। रिहा होने के बाद भारतीय दल वेणु गोपाल के शव को भारत लेकर वापस लौट आया है। दल सभी सदस्य अपने-अपने घर पहुंच चुके हैं। घटना को लेकर किसी भी व्यक्ति ने कुछ भी बोलने से इन्कार कर दिया है। भारतीय दल ने सिर्फ घटना की पुष्टि भर की है।

मेरठ में सड़क हादसा, नोएडा के पांच इंजीनियरों की मौत

मेरठ के कांवड़ मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त कार देखते परिजन। जागरण

जागरण संवाददाता, मेरठ

दोस्त की शादी में शामिल होने शुक्रवार रात नोएडा से मुजफ्फरनगर के मीरापुर जा रहे पांच युवकों की सड़क हादसे में मौत हो गई। कांवड़ मार्ग पर नानू पुल के पास उनकी कार की ट्रक से जबरदस्त टक्कर हुई। पांचों युवक नोएडा की ल्यूमैक्स कंपनी में इंजीनियर थे।

सोनीपत के थाना गोहाना के बली ब्राह्मण गांव निवासी तरुण ने बताया कि उनका भतीजा अंकित उनकी कार लेकर गया था। नोएडा से शुक्रवार रात उसके साथ दोस्त कैलाश चंद निवासी नागल सिरोही महेंद्रगढ़ नारनौल हरियाणा, ओम प्रकाश निवासी कजीवरा रेवाड़ी हरियाणा, मोहित निवासी ग्राम छारदहा थाना पानीवाला जयपुर और सचिन निवासी ग्राम झबरेड़ा भूडपुर चौहान हरिद्वार भी थे। ये अपने दोस्त निशांत निवासी सिलारपुर जानसठ की शादी में शामिल होने के लिए मीरापुर जा रहे थे। रात करीब 12 बजे चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग पर नानू पुल से कुछ दूरी पर मुजफ्फरनगर की ओर से आ रहे ट्रक और कार की आमने-सामने की टक्कर हो गई। हादसे के बाद पांचों युवक कार में बुरी तरह फंस गए। पुलिस ने गैस कटर से कार को काटकर किसी तरह से युवकों को निकाला, लेकिन तब तक सभी दम तोड़ चुके थे। पुलिस ने कार में मिले कागजों के आधार पर परिवारीजनों को सूचना दी। अंकित के चाचा तरुण और उनका भाई यहां पहुंचे। मृतक कैलाश के भाई की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ खड़ी कार में टक्कर मारने की रिपोर्ट दर्ज की है।

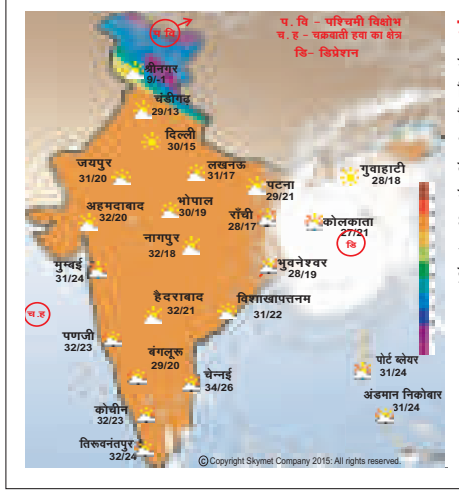

मौसम विशेष

राजस्थान, हरियाणा, पंजाब व दिल्ली में न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी रहेगी। चमकीली धूप के साथ दिन हल्का गर्म रहेगा। कश्मीर घाटी में दिन ठंडा रहेगा। रात में कंपकंपाती ठंड रहेगी। जम्मू क्षेत्र में शुष्क मौसम के साथ दिन आरामदायक रहेगा। लद्दाख क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होगी।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	33/23/स	अहमदाबाद	32/19/स
कोलकाता	29/20/आंबा	बड़ौदा	32/18/आंबा
चेन्नई	32/25/स	नागपुर	33/18/स
हैदराबाद	32/22/आंबा	इन्दौर	28/19/आंबा
बंगलूरू	30/20/आंबा	राँची	29/19/आंबा
त्रिवेन्द्रम	32/24/सा	पटना	30/19/आंबा
गुवाहाटी	28/21/आंबा	जमशेदपुर	28/18/स
गंगटोक	13/03/आंबा	पुणे	30/20/स

कल सूर्य के सामने से सफर तय करेगा बुध

रमेश चंद्रा, नैनीताल

सोमवार को दुर्लभ खगोलीय घटना में बुध ग्रह सूर्य के मध्य क्षेत्र से होकर गुजरेगा। बुध के अच्छादन यानी मरकरी ट्रांजिट की यह घटना भारत से लगे महासागरों से देखी जा सकेगी। सोमवार की शाम 6.04 बजे से यह शुरू होगी।

आर्यभटट् प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (एरीज) के खगोल वैज्ञानिक डॉ. शशि भूषण पांडे ने बताया कि इस खगोलीय घटना में बुध ग्रह सूर्य के सामने से होकर गुजरेगा। जिसमें वह काली बिंदी की तरह अपने पथ पर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस घटना को विशेष चश्मे के सहारे देखा जा सकेगा। ट्रांजिट का समय सूर्यास्त के बाद होने के कारण यह घटना भारत के धरातलीय क्षेत्र से नहीं देखी जा सकेगी। परंतु प्रशांत, अटलांटिक व हिंद महासागर से देख सकेंगे। इसके अलावा अफ्रीका, यूरोप व दक्षिणी अमेरिका से देखी जा सकेगी। ट्रांजिट का समय लगभग साढ़े पांच घंटे का रहेगा। इस बीच बुध ग्रह सूर्य के एक छोर से दूसरे किनारे तक यात्रा करेगा। भारतीय समय के अनुसार रात करीब 11.30 बजे ट्रांजिट समाप्त हो जाएगा। इसके बाद यह घटना 13 वर्ष बाद 2032 में होगी। एक सदी में 13 बार यह घटना होती है। ट्रांजिट ग्रहण जैसी ही घटना है। वैज्ञानिक नजरिये से यह सामान्य खगोलीय घटना है। परंतु समयकाल की गणना के साथ बुध व पृथ्वी के बीच की दूरी की गणना का सटीक पता चलने के साथ पिछली गणनाओं की पुष्टि हो सकेगी। जिस कारण वैज्ञानिक इस घटना का अध्ययन करते हैं। सौर मंडल में सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह बुध है।

बांग्लादेश की सीमा से गिरफ्तार किए गए 117 घुसपैठिए

जागरण संवाददाता, कोलकाता

बड़ी कार्रवाई

- बीएसएफ ने उत्तर 24 परगना जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ को किया नाकाम
- बंगाल के सीमावर्ती जिलों से इस साल 1828 घुसपैठियों की हो चुकी है गिरफ्तारी

बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा से अवैध घुसपैठियों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के जवानों ने शुक्रवार मध्यरात्रि में विशेष अभियान चलाकर अवैध रूप से अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर प्रवेश करने की कोशिश के आरोप में सीमावर्ती उत्तर 24 परगना जिले के विभिन्न स्थानों से 117 घुसपैठियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। इनमें 113 बांग्लादेशी जबकि चार भारतीय मूल के नागरिक हैं। हाल के समय में बांग्लादेश सीमा से एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठियों की गिरफ्तारी का यह पहला मामला है।

इससे पहले बुधवार व गुरुवार को दो दिनों में 42 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया था। दरअसल, पिछले कुछ महीनों से ऐसा कोई दिन नहीं बीता है जब घुसपैठियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बीएसएफ की ओर से शनिवार को जारी एक बयान में बताया गया कि शुक्रवार मध्यरात्रि में चलाए गए अभियान के दौरान जवानों ने उत्तर 24 परगना के बनगांव थाना क्षेत्र से 108 बांग्लादेशी और चार भारतीय मूल के नागरिकों को गिरफ्तार किया, जब वे अवैध रूप से अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा स्वरूपनगर थाना क्षेत्र से पांच बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में सभी घुसपैठियों ने बताया है कि वे दलालों की मदद से भारत में आए थे।

साप्ताहिक राशिफल

रविवार 10 नवंबर, 2019 से शनिवार 16 नवंबर, 2019 तक

पं. बी. बी. शास्त्री 'देवेश'

मेष (चू,चे,चो,ला,ली,लू,ले,लो,आ)
व्यापारिक, नौकरी, उद्योग के कार्य में प्रयास से सफलता, धनागम अच्छा, आत्मविश्वास की कमी, धन आवागमन में सावधानी, स्वास्थ्य में सुधार, भौतिक साधनों की वृद्धि, संतान से अनबन, चयन में सफलता, खानपान का ध्यान रखें, यात्रा में सावधानी, वाहन में सावधानी, शुभ अंक 8।

वृष (इ,ऊ,ए,ओ,पा,वी,वू,वे,वो)
नौकरी, व्यापार, उद्योग के कार्य में सहयोग से सफलता, अर्थ साधन में सुधार, निर्णय सलाह से करें, विदेश कार्य में प्रयास सफल, भूमि योग, संतान के प्रति कार्य, शिक्षा में रुचि, वाद विवाद से बचें, दांपत्य में सुख, संपूर्ति का अनुबंध, वाहन में सावधानी, व्यय अधिक, शुभ अंक 7।

मिथुन (का,की,कू,घ,ड,छ,के,को,हा)
व्यापार, नौकरी, उद्योग के कार्य में सफलता, धनागम अच्छा, आत्मविश्वास की वृद्धि, महिला से लाभ, जीवन में शांति, भवन भूमि सजावट योग, संतान से सहयोग, शिक्षा में एकाग्रता, मित्रों से सावधान, दांपत्य में अनबन, यात्रा में लाभ, यंत्र स्थापन योग, वाहन में सावधानी, शुभ अंक 6।

कर्क (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डू,डे,डो)
व्यापार, नौकरी, उद्योग के कार्य में श्रम से सफलता, अर्थ साधन में प्रगति, आत्मविश्वास की कमी, भौतिक साधनों की वृद्धि, सन्तान से चिन्तित, चयन में अवरोध, वाद में विजय, दांपत्य में सुख, यात्रा से बचें, राज्यपक्ष से सावधान, स्थान परिवर्तन, व्यय अधिक, शुभ अंक 5।

सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे)
व्यापार, नौकरी, उद्योग के कार्य में प्रयास से सफलता, अर्थ साधन अच्छा, साहस की वृद्धि, कार्य करने वालों से सावधान, विदेश कार्य में प्रयास करें, जीवन में चिंता, संतान से सहयोग, शिक्षा में रुचि, चयन में सफलता, नेत्र एवं त्वचा विकार, यात्रा में सावधानी, वाहन में सावधानी, व्यय अधिक, शुभ अंक 4।

कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो)
व्यापार, नौकरी, उद्योग के कार्य में प्रगति, धनागम में प्रगति, विदेश कार्य में प्रयास सफल, साधन वृद्धि, वाहन योग, संतान की सफलता, तकनीकी विषय में रुचि, चयन में देरी, वाद में विजय, सलाह से किए गए कार्य में प्रगति, जीवनसाथी का मिलन, यात्रा से लाभ, बैंक कार्य में प्रगति, शुभ अंक 3।

तुला (रा,री,रू,रे,रो,ता,ती,तू,ते)
व्यापारिक, नौकरी, उद्योग के कार्य में सफलता, धनागम में सुधार, पूंजी निवेश में सावधानी, जीवन शांतिमय, साधनों की वृद्धि, संतान से अनबन, शिक्षा में रुचि, चयन में सफलता, विवादित कार्य से बचें, क्रोध पर नियंत्रण करें, दांपत्य में अनबन, यात्रा में सावधानी, संपूर्ति का अनुबंध, शुभ अंक 2।

वश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू)
नौकरी, उद्योग, व्यापार के कार्य में सहयोग से सफलता, अर्थ साधन अच्छा, सहयोगी जनों से सतर्क, जीवन में खिन्नता, भौतिक साधन वृद्धि, चयन में देरी, आलस्य से बचें, दांपत्य में अनबन, यात्रा से लाभ, अधिकारी जन से सहयोग, लोकप्रियता में कमी, स्थान परिवर्तन, शुभ अंक 1।

धनु (ये,यो,भा,भी,भू,धा,फा,ढा,भे)
व्यापारिक, उद्योग, नौकरी के कार्य में प्रयास में सफलता, अर्थ साधन में प्रयास करें, पूंजी निवेश में सावधानी, पारिवारिक चिन्ता, साधन वृद्धि, संतान से अनबन, शिक्षा में व्यवधान, विवादित कार्य से बचें, शत्रु पक्ष प्रभावी, प्रणय में मधुरता, यात्रा से बचें, कार्यों के प्रति सावधानी, शुभ अंक 11।

मकर (भो,जा,ज,खी,खू,खे,खो,गा,गी)
व्यापारिक, नौकरी, उद्योग के कार्य में सफलता, अर्थ साधन में देरी, नए स्थानों पर संपर्क, सुख शांति, साधनों की वृद्धि, संतान से चिंतित, शिक्षा में एकाग्रता, विवादित कार्य से बचें, तीर्थयात्रा योग, जीवनसाथी का मिलन, लोकप्रियता में कमी, राजनैतिक अपयश, स्थान परिवर्तन, शुभ अंक 11।

कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सा,दा)
व्यापारिक, उद्योग, नौकरी के कार्य में सहयोग से सफलता, अर्थ साधन में प्रयास करें, कार्य करने वालों से सावधान, पारिवारिक अनबन, सजावट भूमि कार्य में सफलता, चयन में सफलता, यात्रा में सावधानी, राजनैतिक में अपयश, निर्माण की योजना, व्यय अधिक, शुभ अंक 10।

मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची)
व्यापारिक नौकरी उद्योग के कार्य में प्रगति, अर्थ साधन, नए स्थानों में व्यापार योग, पारिवारिक सुख शांति, भौतिक साधनों की पूर्ति, संतान के प्रति चिंतित, अध्ययन में एकाग्रता, चयन में सफलता, मित्रों से सावधान, नए जीवनसाथी का मिलन, यात्रा में सावधानी, अधिकारी से अनबन, शुभ अंक 9।

तैयारी ▸ भारत और बांग्लादेश के बीच सीरीज का तीसरा व अंतिम टी-20 मैच आज

सीरीज जीतने का आखिरी मौका

अभी 1-1 से बराबर पर है सीरीज, कप्तान रोहित से फिर अच्छे प्रदर्शन की आस

नागपुर, प्रेट्र : बांग्लादेश के खिलाफ रविवार को विदर्भ क्रिकेट संघ स्टेडियम (वीसीए) में खेले जाने वाले सीरीज के तीसरे और आखिरी टी-20 मैच में भारतीय टीम की नजरें इस साल घरेलू सरजमीं पर सबसे छोटे प्रारूप की पहली सीरीज जीतने पर होंगी। इसके साथ ही दोनों टीमों के पास सीरीज जीतने का यह आखिरी मौका भी है, क्योंकि यह सीरीज अभी 1-1 से बराबरी पर है।

कप्तान विराट कोहली सहित कुछ अन्य सीनियर खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में भारतीय टीम सीरीज अपने नाम करने के साथ अगले साल खेले जाने वाले टी-20 विश्व कप के लिए कोर खिलाड़ियों की पहचान करना चाहेगी। सीरीज के पहले दो मैचों में हालांकि इस मामले में लेग स्पिनर युजवेंद्रा सिंह चहल की टीम में सफल वापसी के अलावा ज्यादा फायदा नहीं हुआ। चहल ने एक बार फिर साबित किया कि बीच के ओवरों में उनके पास विकेट निकालने की क्षमता है। राजकोट में खेले गए दूसरे टी-20 में चहल की अगुआई में भारतीय गेंदबाजों ने बांग्लादेश को छह विकेट पर 153 रन पर रोक दिया। फिर रही सही कसर कप्तान रोहित शर्मा में 85 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर पूरी कर दी।

ठाकुर को मौका : चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव की जगह टीम में चुने गए वाशिंगटन सुंदर काफी किफायती रहे, लेकिन विकेट चटकाने के मामले में चहल से पीछे छूट गए। तेज गेंदबाज खलील अहमद ने दोनों मैचों में रन लुटाए, जिससे इस मैच में शार्दुल ठाकुर को अंतिम एकादश में जगह मिल सकती है, जो दीपक चाहर के साथ नई गेंद साझा कर सकते हैं।

पांडे, संजू और चाहर का इंतजार : रोहित ने पहले दोनों टी-20 मैचों की टीम में कोई बदलाव नहीं किया, जिससे मनीष पांडे, संजू सैमसन और राहुल चाहर जैसे खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में ही बैठे रहे। नागपुर में अगर उन्हें मौका नहीं मिला तो उन्हें खुद को साबित करने के लिए वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी टी-20 सीरीज का इंतजार करना होगा। टीम में जब सीनियर खिलाड़ियों की वापसी होगी तब भी भारत को टीम संयोजन बनाने के लिए काफी मशक्कत करनी होगी, खासकर बल्लेबाजी विभाग में, जहां टीम के पास ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की तरह बड़े शॉट खेलने वाली खिलाड़ियों की कमी है।

पंत ने बढ़ाई परेशानी : श्रेयस अय्यर ने कम समय में खुद को साबित किया है, जबकि लोकेश राहुल अभी तक प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे है। नए ऑलराउंडर शिवम दुबे को भी अपनी प्रतिभा से न्याय करना होगा। भारतीय टीम में नए खिलाड़ियों के साथ अनुभवी शिखर धवन और युवा विकेटकीपर रिभष पंत भी टीम में जगह बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे है। धवन बल्ले से, जबकि पंत बल्ले के साथ विकेट के पीछे भी अपने खराब प्रदर्शन के कारण आलोचना झेल रहे हैं। रविवार को दोनों खिलाड़ियों के पास आलोचकों को चुप करने का एक मौका होगा। पंत ने भी कप्तान रोहित को परेशान ही किया है। वह पहले टी-20 मैच में रिव्यू मामले में पिछड़ गए थे, फिर दूसरे टी-20 में विकेट के आगे से गेंद पकड़कर बचकाना हरकत भी की थी।

मैच पर नहीं बारिश का साया

इस मैच में बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। रविवार को मैच के दौरान नागपुर का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस, जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। दिन में धूप खिली रहेगी।

तिकड़ी ने की गहन चर्चा

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, मुख्य कोच रवि शास्त्री और गेंदबाजी कोच भरत अरुण की तिकड़ी ने शनिवार को वीसीए में अभ्यास के दौरान गहन चर्चा की। पहले कप्तान रोहित पिच देखने पहुंचे और उनके पीछे-पीछे दोनों कोच भी पिच पर आ गए। यह तिकड़ी पिच देखने के बाद किसी अहम मुद्दों पर चर्चा कर रही थी।

दोनों टीमें

भारत : रोहित शर्मा (कप्तान), शिखर धवन, लोकेश राहुल, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, रिषभ पंत (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, क्रुणाल पांड्या, युजवेंद्रा सिंह चहल, राहुल चाहर, दीपक चाहर, खलील अहमद, शिवम दुबे, शार्दुल ठाकुर।

बांग्लादेश : महमुदुल्लाह (कप्तान), मुहम्मद नईम, अफिफ हुसैन, मुसद्दक हुसैन, अनिमुल इस्लाम, लिटन दास, मुश्फिकुर रहीम, अराफत सनी, अल अमिन हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान, शैफुल इस्लाम, अबु हैदर, मुहम्मद मिथुन, तैजुल इस्लाम।

बांग्लादेश से रहें सतर्क

भारतीय टीम जीत की दावेदार होगी, लेकिन तमीम इकबाल और शाकिब अल हसन जैसे सीनियर खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में बांग्लादेश एक बार फिर दिल्ली की तरह चौका सकती है। राजकोट में दूसरे टी-20 में भी टीम को अच्छी शुरुआत मिली, लेकिन वे इसका फायदा नहीं उठा सके और टीम 20 ओवर में सिर्फ 153 रन बना सकी। बांग्लादेश के लिए 20 साल के लेग स्पिनर अनिमुल इस्लाम ने अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया। उन्होंने किफायती रहते हुए चार विकेट चटकाए। बांग्लादेश को हालांकि तेज गेंदबाजी में सुधार करना होगा, खासकर टीम के मुख्य गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करने में नाकाम रहे हैं।

वीसीए की पिच को देखकर बातचीत करते भारत के गेंदबाजी कोच भरत अरुण, रोहित, शास्त्री। प्रेट्र

400 छक्के अंतरराष्ट्रीय करियर में पूरे करने से दो छक्के दूर हैं भारत के कप्तान रोहित शर्मा। वनडे में रोहित ने 232, टेस्ट में 51 और टी-20 में 115 छक्के जड़े हैं। अभी तक सिर्फ दो खिलाड़ी ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 400 छक्के लगा पाए हैं जिसमें पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी और वेस्टइंडीज के क्रिस गेल शामिल हैं

01 विकेट लेते ही भारत के कलाई के स्पिनर युजवेंद्रा सिंह चहल अंतरराष्ट्रीय टी-20 में 50 विकेट पूरे कर लेंगे। अभी उन्होंने 33 टी-20 मैच खेले हैं जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 25 रन देकर छह विकेट है

2017 में भारत ने नागपुर में अपना पिछला टी-20 मैच खेला था। भारतीय टीम ने इस मैच में इंग्लैंड को पांच रन से हराया था

03 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच भारतीय टीम ने नागपुर के विदर्भ क्रिकेट संघ स्टेडियम में खेले हैं। भारत को इस मैदान पर तीन में से दो मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है

15 टी-20 द्विपक्षीय अवे सीरीज खेली हैं बांग्लादेश ने, इनमें से उसे सिर्फ दो में जीत मिली है

पंत को छोड़ दें : रोहित

नागपुर डायरी

नागपुर, प्रेट्र : भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने शनिवार को आलोचनाओं से घिरे रिषभ पंत का समर्थन करते हुए आलोचकों से कहा कि उन्हें छोड़ दें, क्योंकि वह सिर्फ टीम प्रबधंन की रणनीति पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। कई मौकों पर पंत के शॉट चयन की काफी आलोचना हुई है और राजकोट में बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टी-20 में उनकी खराब विकेटकीपिंग की भी आलोचना हुई।

रोहित ने कहा, 'हर दिन, हर मिनट पंत के बारे में काफी चर्चा चल रही है। मुझे यही लगता है कि उन्हें वही करने देना चाहिए जो वह मैदान पर करना चाहते हैं। मैं हर किसी से अनुरोध करूंगा कि कुछ समय के लिए पंत से निगाहें हटा लीजिए। वह निर्भीक क्रिकेटर हैं और हम (टीम प्रबंधन) उन्हें वही आजादी देना चाहते हैं और अगर आप कुछ समय के लिए अपनी निगाहें उनसे दूर रखोगे तो इससे वह बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे।'

रोहित दिल्ली के इस युवा खिलाड़ी की लगातार आलोचना से खुश नहीं हैं। उन्होंने इस पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा, 'वह 22 साल के युवा हैं, जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खुद का मुकाम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वह मैदान पर कुछ भी करते हैं तो लोग उनके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। यह ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि हमें उन्हें उनका क्रिकेट खेलने देना चाहिए, जो वास्तव में वह करना चाहते हैं।'

> यह सभी जानते हैं कि भारत का गेंदबाजी आक्रमण कम अनुभवी है। अगर हम अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और अपनी रणनीति पर कायम रहते हैं तो हम उनके गेंदबाजी आक्रमण को दबाव में ला सकते हैं। ओस मैचों को प्रभावित कर रही है। टॉस की भूमिका अहम होगी, दूसरी पारी में बल्लेबाजी कर रही दोनों टीमों ने जीत हासिल की।
>
> **-रसेल डोमिंगो, कोच, बांग्लादेश**

चहल ने उपयोगिता साबित की : युजवेंद्रा सिंह चहल टीम में वापसी में एक बार फिर से बीच के ओवरों में अपनी उपयोगिता साबित करने में सफल रहे, जिसने कप्तान रोहित शर्मा को भी प्रभावित किया। वनडे विश्व कप के बाद चहल और कुलदीप यादव को वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी-20 सीरीज की टीम में जगह नहीं दी गई थी। चयनकर्ता अगले साल खेले जाने वाले टी-20 विश्व कप के लिए नए खिलाड़ियों को आजमाना चाहते थे। रोहित ने कहा, 'यह काफी नई टीम है, लेकिन पिछले दो वर्षों से सीमित ओवरों के प्रारूप में चहल का प्रदर्शन कमाल का रहा है। उन्होंने वनडे में भी शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने आइपीएल में अच्छे प्रदर्शन के दम पर भारत की वनडे टीम में जगह बनाई। उसके बाद से ही वह टीम के अहम सदस्य हैं और उन्होंने इस सीरीज में भी साबित किया कि बीच के ओवरों में वह टीम के लिए कितने उपयोगी हैं। चहल जानते हैं कि वह क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और वह यह भी जानते हैं कि बल्लेबाज क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। वह खेल में हमेशा बल्लेबाज से आगे रहना चाहते हैं। इस कारण से किसी भी बल्लेबाज के लिए उनका सामना करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। वह इसे अच्छी तरह समझ चुके हैं। उनके पास विविधता और कौशल की कमी नहीं है।'

भारतीय खिलाड़ी वायुसेना के पायलटों से मिले

नागपुर, प्रेट्र : बांग्लादेश के खिलाफ रविवार को निर्णायक टी-20 मुकाबले से पहले भारतीय क्रिकेटरों ने शनिवार को यहां वायुसेना की सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम से मुलाकात की। वायुसेना के ये पायलट नारंगी रंग की वर्दी में थे। धवन, पंत और मनीष पांडे के साथ मुख्य कोच रवि शास्त्री ने वायुसेना के जवानों के साथ लगभग एक घंटे तक समय बिताया। इस मौके पर एरोबैटिक दल ने मुख्य शास्त्री को स्मारिका भेंट की। वायुसेना के ये पायलट यहां 'एयर फेस्ट 2019' के लिए मौजूद थे।

वायुसेना की सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम के साथ भारतीय बल्लेबाज शिखर धवन। ट्विटर

रोहित के शॉटों ने जीता दिल

मोहिंदर अमरनाथ
रिवर्स स्वीप

पिछले कुछ सत्रों में भारत ने उलटफेर होने के बाद मजबूती से वापसी की है और राजकोट में यह अलग नहीं था। भारत ने सीरीज में 1-1 से बराबरी पा ली है, जिसमें एक शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन के साथ रोहित शर्मा की मास्टर क्लास बल्लेबाजी भी शामिल है। कप्तान रोहित अभी शानदार फॉर्म में हैं। मुझे लगता है कि उनके तीनों प्रारूपों में मौजूदगी ने उनके प्रदर्शन में स्थिरता और निरंतरता को जोड़ा है। मुझे पहले आश्चर्य होता था जब रोहित टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं होते थे, लेकिन टेस्ट में एक सलामी बल्लेबाज के तौर पर उन्हें शामिल करके उनके खेल में एक नया आयाम आया है। मुझे उम्मीद है कि वह टेस्ट में अपने अच्छे फॉर्म को जारी रखेंगे और रोहित जानते हैं कि समय आने पर वह वीरेंद्र सहवाग की तरह ओपनर बन सकते हैं। बांग्लादेश की टीम के पास पिछले मैच में अच्छी शुरुआत करने के बाद एक बड़ा स्कोर खड़ा करने का शानदार मौका था, लेकिन वह इसका फायदा नहीं उठा पाए और टीम को हार के साथ इसकी कीमत चुकानी पड़ी। राजकोट का विकेट बल्लेबाजों के लिए मददगार था और मेजबानों को रोकने के लिए 170 का स्कोर अच्छा होता और कम स्कोर को भारतीय टीम ने लगभग 16 ओवर में ही हासिल कर लिया। रोहित शतक से चूकने से निराश दिखे, लेकिन उनके दमदार शॉटों ने सभी का दिल जीत लिया। सीरीज के आखिरी मैच के लिए भारत नागपुर में खेलेगा। वे एक संतुलित टीम की तरफ देख रहे हैं। शिखर धवन और रोहित शर्मा की सलामी जोड़ी से नागपुर में अच्छे प्रदर्शन की आस है। वे किसी भी समय मैच का नतीजा बदल सकते हैं।

#WhatDrivesYou
EXIDE

टी-20 विश्व कप को देखते हुए कुलदीप को मौका देने की जरूरत

के श्रीकांत
कलम से

भारत का बल्लेबाजी विभाग बेहतरीन नजर आ रहा है, हालांकि टीम प्रबंधन को सीनियर गेंदबाजों को आराम देते वक्त गेंदबाजी विभाग पर ध्यान देने की जरूरत है। निश्चित रूप से सबसे बड़ा पुरस्कार विश्व कप है और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सारी योजना उसी के इर्द-गिर्द बुनी जा रही है।

मुझे लगता है कि विश्व कप अभियान में कलाई के स्पिनर अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। ऐसे में कुलदीप यादव को टीम में शामिल करने का यह सही वक्त है। ऑस्ट्रेलिया में बड़े मैदानों और विकेट पर उछाल को देखते हुए कुलदीप और चहल की जोड़ी घातक साबित हो सकती है। मौजूदा सीरीज कुलदीप को मौका देने के लिए आदर्श मौका है। हालांकि राहुल चाहर भी खराब विकल्प नहीं हैं, लेकिन कुलदीप का अनुभव उनके पक्ष में है।

विश्व कप के लिए मेरी टीम में एक ऑफ स्पिनर भी शामिल होता है। वॉशिंगटन सुंदर ऐसी खोज हैं, जो न केवल कसी हुई गेंदबाजी कर सकते हैं बल्कि बल्ले से भी प्रभावी हैं। इसके अलावा उनकी फील्डिंग भी शानदार है जिस तरह रोहित शर्मा ने वॉशिंगटन सुंदर का इस्तेमाल किया वह बेहतरीन था। उन्होंने सुंदर के दो ओवर पावरप्ले में कराए और दो रन रोकने के लिए मध्य ओवरों में।

रोहित ने स्पिनरों का बेहतरीन इस्तेमाल किया जिसका फायदा उन्हें नियमित विकेट के तौर पर मिला। ऐसे में जबकि तीन स्पिनर पर बात हो चुकी है और हार्दिक पांड्या के तौर पर ऑलराउंडर भी मौजूद है तो तेज गेंदबाजी विभाग पर बात करते हैं। जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार को जगह मिलनी ही चाहिए। चिंता की बात उनके सहयोगी गेंदबाज को लेकर है। खलील अहमद इस स्तर पर सही विकल्प नजर नहीं आ रहे हैं। बेशक सुधार की गुंजाइश कहती है, लेकिन उन्हें तेजी से सीखना होगा। हालात अनुकूल हों तो दीपक चाहर अलग ही गेंदबाज नजर आते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में उन्हें मुश्किल आ सकती है, अगर वह अपनी गेंदबाजी में कुछ और हथियार शामिल कर लेते हैं, तो तीसरे तेज गेंदबाज की जगह भर सकते हैं। बांग्लादेश और भारत के बीच रविवार को होने वाले मुकाबले में मेजबान टीम दावेदार के तौर पर मैदान में कदम रखेगी। (टीसीएम)

सर्वश्रेष्ठ खेल से बार्टी ने दिलाई ऑस्ट्रेलिया को बराबरी

टेनिस डायरी

▸ फेड कप फाइनल में फ्रांस की ग्रासिया को 6-0, 6-0 से हराया

▸ पहले सिंगल्स मैच में मलादेनोविक ने ऑस्ट्रेलिया की टॉमजानोविक दी मात

पर्थ, एएफपी : विश्व की नंबर एक महिला टेनिस खिलाड़ी एश्ले बार्टी ने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए फ्रांस की कैरोलिना ग्रासिया को 6-0, 6-0 से हराकर फेड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 1-1 की बराबरी दिलाई। इससे पहले क्रिस्टिना मलादेनोविक ने ऑस्ट्रेलिया की एल्जा टॉमजानोविक को हराकर फ्रांस को शुरुआती बढ़त दिलाई थी। चीन में डब्ल्यूटीए फाइनल्स का खिताब जीतकर लौटीं बार्टी उस समय कोर्ट पर उतरीं जब उनकी टीम 0-1 से पिछड़ रही थी, लेकिन 38 डिग्री सेल्सियस की गर्मी होने के बावजूद ग्रासिया को एकतरफा सिंगल्स मुकाबले में मात दी। जीत के बाद बार्टी ने कहा कि यह एक यादगार जीत है। मुझसे इससे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे लगता है कि यह मेरे जीवन के अब तक का सर्वश्रेष्ठ मैच है। उधर, पहले सिंगल्स मुकाबले में मलादेनोविक ने टॉमजानोविक को 6-1, 6-1 से हराया। सात बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलियाई टीम 45 वर्षों बाद फेड कप में खिताबी जीत की उम्मीद से खेल रही है, जबकि फ्रांस की टीम 2003 के बाद पहले और कुल तीसरे खिताब की कोशिश में खेल रही है।

नडाल और जोकोविक में बादशाहत की जंग : सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक रविवार से शुरू हो रहे एटीपी फाइनल्स में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड छह खिताब की बराबरी करके और राफेल नडाल को नंबर एक रैंकिंग से हटाकर इस सत्र का शानदार अंत कर सकते हैं। जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव ने पिछले साल एटीपी फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जोकोविक को हरा दिया था, लेकिन इस साल जोकोविक खिताब के प्रबल दावेदार के रूप में शुरुआत करेंगे। जोकोविक और स्पेनिश स्टार नडाल ने मिलकर इस साल के सभी चारों ग्रैंडस्लैम खिताब जीते और अगली पीढ़ी को अपनी बादशाहत नहीं जमाने दी। हालांकि, टूर्नामेंट से पहले नडाल की चोट परेशानी का सबब बनी हुई है। स्विस स्टार फेडरर, नडाल और जोकोविक को शीर्ष वरीयता दी गई है और वह 2007 के बाद पहली बार एक साथ एटीपी फाइनल्स में खेलेंगे। एटीपी फाइनल्स में शीर्ष आठ खिलाड़ी भाग लेते हैं। इन तीनों के अलावा फॉर्म में चल रहे रूस के डेनिल मेदवेदेव, ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम, यूनान के स्टीफानोस सितसिपास, जर्मनी के ज्वेरेव और इटली के मातियो बेरेटिनी टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे।

मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया की टेनिस खिलाड़ी एश्ले बार्टी। एएफपी

फुटबॉल डायरी

लिवरपूल की टीम के पास बढ़त बढ़ाने का मौका

इंग्लिश प्रीमियर लीग में आज मैनचेस्टर सिटी से एनफील्ड में होगी भिड़ंत, शीर्ष पर काबिज लिवरपूल के पास छह अंकों की बढ़त

लिवरपूल, एएफपी : 29 साल पहले पिछली बार इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) की खिताबी जीत के बाद से इंग्लिश फुटबॉल क्लब लिवरपूल ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। हालांकि, 2019-20 के सत्र में फॉर्म में चल रहा लिवरपूल रविवार को एनफील्ड में मौजूदा चैंपियन मैनचेस्टर सिटी से भिड़ेगा तो उसके पास अपनी बढ़त को बढ़ाने का मौका होगा।

पिछले सत्र में रिकॉर्ड 97 अंक हासिल करने के बावजूद लिवरपूल को सिटी से खिताबी दौड़ में एक अंक से पिछड़ना पड़ा था। हालांकि, मौजूदा सत्र में पेप गॉर्डियोला की टीम चोट की वजह से परेशान है। वहीं, मैनेजर जुर्जेन क्लोप की लिवरपूल टीम रविवार को होने वाली भिड़ंत से पहले अंक तालिका में छह अंकों की बढ़त हासिल कर चुकी है। शुक्रवार को सिटी के मैनेजर गॉर्डियोला ने कहा था कि पिछले सत्र में ईपीएल खिताब जीतने के दौरान लिवरपूल के रूप में मुझे मेरे करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी से भिड़ना पड़ा था। इस समय लिवरपूल दुनिया की सबसे ताकतवर टीम है। मालूम हो कि अप्रैल 2017 के बाद से क्लोप के मार्गदर्शन में लिवरपूल की टीम ईपीएल में कोई भी घरेलू मुकाबला नहीं हारी है।

लिवरपूल के मैनेजर जुर्जेन क्लोप (बायें) और मैनचेस्टर सिटी के मैनेजर पेप गॉर्डियोला। फाइल फोटो, रायटर

आर्सेनल के खिलाड़ियों पर हमला करने वाले शख्स को 10 साल की जेल : लीड्स, एएनआइ : इंग्लिश क्लब आर्सेनल के खिलाड़ी मेसुत ओजिल और सीड कोलासिनाक पर हमला करने वाले शख्स एश्ले स्मिथ को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। स्मिथ पर हमला और चोरी के आरोप साबित हुए। स्मिथ के साथी जॉर्डन नॉर्थओवर को भी चोरी की कोशिश के आरोप में बुधवार को दोषी करार दिया गया था, जिनकी सजा बाद में सुनाई जाएगी। इस साल जुलाई में ओजिल और कोलासिनाक की जीप पर नॉर्थ लंदन के गोल्डर्स ग्रीन में हमला किया गया था, जिसके बाद ओजिल अपनी जीप से उतरकर हमलावरों से भिड़ते नजर आए थे।

सऊदी अरब से हारा भारत

अल खोबार (सऊदी अरब), एएफपी : 2020 एएफसी अंडर-19 एशियन चैंपियनशिप के क्वालीफायर में भारतीय फुटबॉल टीम को सऊदी अरब के हाथों 0-4 से शिकस्त झेलनी पड़ी। घरेलू टीम के मुहम्मद खलील मारन ने खेल के दूसरे ही मिनट में गोल दागकर भारतीय टीम पर दबाव बना दिया। इसके बाद 10वें मिनट में अहमद अल्बसास ने गोल करके अपनी टीम को दोहरी बढ़त दिलाई। अल्बसास ने 18वें मिनट में अपना दूसरा और सऊदी अरब के लिए तीसरा गोल दागा। इसके बाद 28वें मिनट में उन्होंने फिर से गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाकर अपनी हैट्रिक मुकम्मल की। भारत अपने आखिरी ग्रुप मुकाबले में रविवार को अफगानिस्तान से भिड़ेगा।

निशानेबाज तेजस्विनी ने भी हासिल किया ओलंपिक कोटा

एशियन चैंपियनशिप

▸ टोक्यो के लिए निशानेबाजी में भारत का 12वां स्थान पक्का हुआ

▸ चौथे स्थान पर रहते हुए पदक से चूकीं अनुभवी सावंत

दोहा, प्रेट्र : अनुभवी तेजस्विनी सावंत शनिवार को यहां 14वीं एशियन चैंपियनशिप की महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में पदक से चूक गईं, लेकिन उन्होंने निशानेबाजी में भारत के लिए 12 ओलंपिक कोटा सुनिश्चित किया।

पूर्व विश्व चैंपियन तेजस्विनी ने चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाकर अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए कोटा हासिल किया। फाइनल में पहुंचे आठ प्रतिद्वंद्वियों में से पांच पहले ही टोक्यो के लिए जगह पक्की कर चुके थे, इसलिए भारत को तीन उपलब्ध कोटा में से एक मिल गया। 39 साल की तेजस्विनी क्वालीफिकेशन में 1171 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर रहते हुए फाइनल में पहुंची थीं। हालांकि, फाइनल में तेजस्विनी ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उन्हें चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा। फाइनल में उन्होंने 435.8 अंक हासिल किए। तेजस्विनी 2008, 2012 और 2016 में ओलंपिक टीम में जगह बनाने से चूक गई थीं।

चीन की मेंगयाओ शी ने 457.9 अंकों के साथ स्वर्ण जीता, जबकि मंगोलिया की येसुगेन ओयुनबाट ने 457 अंकों के साथ रजत मिला। कांस्य पदक जापान की शिओरी हिराता (445.9) ने हासिल किया। अन्य भारतीयों में काजल सैनी (1167) और गायत्री नित्यानंदम (1165) क्वालीफिकेशन में क्रमशः 13वें और 16वें स्थान पर रहीं। 50 मीटर राइफल प्रोन में भी प्रतिस्पर्धा करने वालीं तेजस्विनी कई पदक जीत चुकी हैं, जिनमें विश्व कप और कॉमनवेल्थ के पदकों के साथ विश्व चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक भी शामिल है।

23 अक्टूबर को ब्रिटेन के एसेक्स में रेफ्रिजरेटिड लॉरी में मृत पाए गए वियतनाम के 39 लोगों के नाम पुलिस ने जारी कर दिए हैं। मृतकों की पहचान फिंगर प्रिंट, डीएनए, शरीर पर मौजूद चिह्न और दांतों के जरिये की गई है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
रविवार 10 नवंबर 2019

न्यूज गैलरी

ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति लुला डिसिल्वा जेल से रिहा

ब्राजीलिया : ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति लुला डिसिल्वा को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जेल से रिहा कर दिया गया। पूर्व राष्ट्रपति अप्रैल, 2018 से भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद थे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने फैसले में दोषियों के जेल जाने की अनिवार्यता से जुड़े आदेश को पलट दिया था। इसी के बाद डिसिल्वा की रिहाई का रास्ता साफ हुआ। (एएनआइ)

दुबई व्हीलचेयर दौड़ में बुजुर्ग भारतीय महिलाओं का जलवा

दुबई : संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के दुबई में भारत की दो बुजुर्ग महिलाओं 86 साल की कुसुम भार्गव और 74 वर्षीय ईश्वरी अम्मा ने पांच किलोमीटर की व्हीलचेयर दौड़ सफलतापूर्वक पूरी की। कुसुम संभवत: प्रतियोगिता की सबसे बुजुर्ग प्रतिभागी थीं। उन्होंने इसे अपने लिए अलग अनुभव बताया। ईश्वरी अम्मा ने बेटे-बहू और पोते-पोतियों के साथ प्रतियोगिता में भाग लिया। (प्रेट्र)

अमेरिका के भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध : ट्रंप

वाशिंगटन : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका के भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता में बहुत सारे मुद्दों पर प्रगति हुई है। भारत की यात्रा के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का निमंत्रण स्वीकार करने वाले ट्रंप ने कहा कि वह आने वाले समय में वहां जा सकते हैं। भारत के साथ व्यापार समझौतों पर प्रगति के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में एकत्र मीडिया से कहा कि भारत के साथ अमेरिका के बहुत अच्छे संबंध हैं और दोनों ही देश इस मामले में काफी आगे बढ़े हैं। (प्रेट्र)

अमेरिकी संसदीय समितियों ने दो गवाहों के बयान जारी किए

वाशिंगटन : राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की जांच कर रही अमेरिकी संसदीय समितियों ने दो गवाहों के बंद कमरे में दर्ज किए गए बयान सार्वजनिक किए हैं। जिनके बयान जारी किए गए हैं उनमें व्हाइट हाउस के पूर्व सलाहकार फिओना हिल और व्हाइट हाउस के वर्तमान सलाहकार अलेक्जेंडर विंडमैन शामिल हैं। शुक्रवार को एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ माइक मुलवानेय और व्हाइट हाउस के एक अन्य अधिकारी मार्क सैंडी गवाही दर्ज कराने के लिए हाजिर नहीं हुए। (रायटर)

हांगकांग में तनाव के बाद तीन सांसद गिरफ्तार

बढ़ा बवाल ▶ स्वायत्त प्रांत में थम नहीं रहा प्रदर्शनों का सिलसिला

चार अन्य सांसदों की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस

हांगकांग, एएफपी : हांगकांग पुलिस ने शनिवार को लोकतंत्र समर्थक तीन सांसदों को संसद में उपद्रव के आरोप में गिरफ्तार किया है। इससे एक दिन पहले ही शहर में छात्र की मौत के बाद तनाव चरम पर पहुंच गया। दुनिया के वित्तीय केंद्र के रूप में उभरे हांगकांग में पिछले पांच महीनों के दौरान लोकतंत्र के समर्थक में कई हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। हालांकि बीजिंग ने प्रदर्शनकारियों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। हांगकांग में लगातार 24वां सप्ताह रैलियों के नाम रहा।

तीन प्रमुख लोकतंत्र समर्थक सांसदों की गिरफ्तारी के बाद चार अन्य सांसदों को पुलिस स्टेशन पहुंचने का आदेश दिया गया है। यदि वे दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें एक साल की जेल हो सकती है। सांसदों ने अपने संयुक्त बयान में कहा कि विरोध प्रदर्शन पांच महीनों से जारी हैं, ये खत्म हो सकता था लेकिन सरकार लोकतंत्र समर्थक सांसदों को पुलिस के जरिए गिरफ्तार करने में जुटी है। सांसद लैम च्युंग टिंग ने कहा कि यदि उन्हें लगता है कि मैंने कानून का उल्लंघन किया है तो वे आएं और मुझे गिरफ्तार कर लें। मैं उनका इंतजार कर रहा हूं।

हांगकांग की लेजिसलेटिव काउंसिल अर्द्ध लोकतांत्रिक है। इसमें से आधे सदस्यों का चुनाव किया जाता है, वहीं आधे सदस्यों का चुनाव बीजिंग समर्थक समितियां करती हैं। चुनाव के वक्त चीनी सरकार के प्रति सदस्यों की प्रतिबद्धता देखी जाती है।ताजा हालात उस वक्त पैदा हुए जब शुक्रवार को एक 22 वर्षीय छात्र एलेक्स चौ की पुलिस के साथ झड़प में मौत हो गई। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शुक्रवार शाम को कैंडल मार्च निकाला और उस दौरान प्रदर्शनकारियों ने रोड जाम कर दी और बेरिकेटिंग जला दी।

ये था मामला

इस मामले की शुरुआत मई में एक प्रत्यर्पण कानून प्रस्तावित होने के बाद हुई। इस कानून में अपराधियों को मुकदमे के लिए चीन में प्रत्यर्पित किए जाने का प्रावधान था। हांगकांग के लोग इस प्रस्तावित कानून के विरोध में सड़कों पर उतर आए थे। कई हफ्तों के विरोध प्रदर्शनों के बाद हांगकांग की नेता कैरी लैम ने पहले इस बिल को निलंबित किया और फिर निरस्त कर दिया। बावजूद इसके विरोध नहीं थमा और अब भी जारी है।

बर्लिन की दीवार गिराने का जश्न

जर्मनी के ब्रांडेनबर्ग में बर्लिन की दीवार गिराए जाने की 30 वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह का भव्य नजारा। समारोह स्थल को प्रकाश से जगमगाया गया। देश को दो हिस्सों में बांटने वाली यह दीवार 13 अगस्त 1961 को खड़ी की गई थी और करीब 28 साल बाद 9 नवंबर 1989 को गिरा दी गई। रायटर

नेतन्याहू ने बेनेट को इजरायल का रक्षा मंत्री नियुक्त किया

▶ नियुक्ति पर कैबिनेट की अगली बैठक में होगा मतदान

यरुशलम, आइएएनएस : इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने न्यू राइट पार्टी के नेता नफ्तली बेनेट को देश का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के मुताबिक प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को बेनेट से मुलाकात के बाद यह फैसला किया। बेनेट की नियुक्ति पर कैबिनेट की अगली बैठक में मतदान होगा।

न्यू राइट पार्टी की नेता आयलेट शेक्ड ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कृषि के साथ प्रवासी मामले और कल्याण या रक्षा मंत्रालय में से एक को चुनने का प्रस्ताव दिया था। गठबंधन सरकार में शामिल रहे बेनेट और शेक्ड ने 2018 में न्यू राइट पार्टी के नेता को रक्षा मंत्री बनाने का अल्टीमेटम दिया था। मांग नहीं मानने पर उन्होंने सरकार से हाथ खींच लेने की धमकी दी थी लेकिन बाद में वे पीछे हट गए थे। नेतन्याहू फिलहाल कार्यकारी सरकार के नेता के तौर पर काम कर रहे हैं।

बता दें कि गत नौ अप्रैल और 17 सितंबर को हुए चुनावों के बाद वे दो बार गठबंधन सरकार बनाने में असफल रहे हैं। पिछले दो चुनावों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। पिछले चुनाव में बेंजामिन के नेतृत्व वाली दक्षिणपंथी पार्टियों के समूह को 120 में से 55 सीटें मिली थीं, जबकि विपक्षी पार्टियों ने 57सीटों पर विजय पाई थी।

बेंजामिन नेतन्याहू (फाइल फोटो)। एपी

इलाज के लिए लंदन जाएंगे नवाज, छोटे भाई शाहबाज भी होंगे साथ

लाहौर, आइएएनएस : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इलाज के लिए रविवार को लंदन जाएंगे। शरीफ के भाई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के अध्यक्ष शाहबाज शरीफ भी उनके साथ होंगे। पाकिस्तानी मीडिया में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि लंदन की हर्ले स्ट्रीट क्लीनिक में नवाज के इलाज की व्यवस्था की गई है।

नवाज और शाहबाज पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट से लंदन पहुंचेंगे। सूत्रों का दावा है कि शरीफ परिवार ने न्यूयॉर्क में एक डॉक्टर से बातचीत की है। नवाज ने अपने निजी चिकित्सक की सलाह और परिवार के जोर देने के बाद विदेश में इलाज कराना स्वीकार किया। जेल में सजा काट रहे नवाज को गत 22 अक्टूबर को तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया भ्रष्टाचार मामले में उन्हें मिली सात साल की सजा को आठ सप्ताह के लिए निलंबित करते हुए 29 अक्टूबर को चिकित्सकीय आधार पर उन्हें जमानत दे दी थी।

बलूचिस्तान से लापता 30 लोगों में से 25 के शव मिले

▶ बलोच नेशनल मूवमेंट की अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार

▶ सरकार समर्थित एक दस्ता भी इन मौतों के लिए है जिम्मेदार

इस्लामाबाद, एएनआइ : पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हाल के दिनों में पाकिस्तानी सेना ने 28 कार्रवाई कीं जिनमें 30 लोग लापता हो गए। लापता लोगों में से 25 के शव बरामद हो गए हैं जबकि पांच का अभी पता नहीं है। बलोच नेशनल मूवमेंट के प्रचार मंत्री दिल मुराद बलोच ने यह जानकारी दी है।

अक्टूबर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के उत्पीड़न की कार्रवाइयों का लेखा-जोखा पेश करते हुए दिल मुराद ने कहा है कि सरकार समर्थित मारक दस्ता इनमें से कई मौतों के लिए जिम्मेदार है। इस दस्ते को पाकिस्तानी सेना का समर्थन प्राप्त है। इसी की सूचना पर सेना इलाके में कार्रवाई करती है। कार्रवाई में यह दस्ता भी साथ होता है। हाल में हुई कार्रवाई के दौरान आमजनों के सौ से ज्यादा घर लूट लिए गए। प्रचार मंत्री ने कहा है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना का अत्याचार दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान मामले में हस्तक्षेप की मांग की है।

प्रचार मंत्री ने बताया है कि बलूचिस्तान विश्वविद्यालय भी उत्पीड़न से अछूता नहीं है। वहां पर लगे खुफिया कैमरों से लड़कियों के फोटो और वीडियो बना लिए जाते हैं, बाद में शोषण के लिए उनका इस्तेमाल होता है। यह सब सरकार की निगाह में होता है। इस सबका उद्देश्य बलोच लोगों को सिर न उठाने देना है। बलोच नेशनल मूवमेंट के चेयरमैन खलील बलोच ने कहा है कि इस तरह मामलों से वह चिंतित हैं। यह बलोचों की पहचान, सम्मान और आत्मा को घायल करने वाला कृत्य है। बता दें कि बलूचिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ता पाकिस्तान की सेना पर भी आरोप लगाते हैं कि वे प्रांत के लोगों पर जुल्म ढहाते हैं।

ऑस्ट्रेलिया में भीषण हुई जंगल की आग तीन की मौत

मेलबर्न, रायटर : पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग ने भीषण रूप ले लिया है। इसकी चपेट में आकर तीन लोगों की मौत हो गई। करीब 150 घर जलकर खाक हो गए। कुछ लोग लापता हैं। आग के कारण हजारों लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी यह सबसे भयावह आग है। देश पहले ही गंभीर सूखे से जूझ रहा है।

न्यू साउथ वेल्स की पुलिस के मुताबिक सिडनी से करीब 300 किलोमीटर उत्तर में स्थित टेरी कस्बे के जले हुए मकान से एक शव बरामद हुआ है। मकान में 63 वर्षीय महिला रहती थी। एक अन्य महिला का शव वाहन में मिला। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मौरिसन ने कहा है कि सेना को मदद के लिए उतारा जा सकता है। मौरिसन ने शनिवार को कहा, हम ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण खबरें फिर सुन सकते हैं। सेना के रिजर्व जवानों को आपातकालीन सेवाओं के सहयोग और आग से सीधे प्रभावित लोगों की मदद के लिए लगाया जा सकता है।

आजकल

गणित के गूढ़ सूत्रों को समझने में लड़कों से पीछे नहीं लड़कियां

वाशिंगटन, प्रेट्र : गणित के मामले में महिलाओं के मुकाबले पुरुषों को अव्वल माना जाता है। लेकिन एक नए अध्ययन में कहा गया है कि लड़के और लड़कियों के मस्तिष्क का विकास समान रूप से होता है। इसमें गणित की समझ को लेकर कोई लिंगभेद नहीं होता है।

इस अध्ययन के लिए अमेरिका की कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पहली बार बच्चों के मस्तिष्क का न्यूरोइमेजिंग के जरिये अध्ययन किया। ताकि यह पता लगाया जा सके कि बायोलॉजिकल (जैविक) लैंगिक भेद का गणित की समझ में क्या प्रभाव पड़ता है। जर्नल 'साइंस ऑफ लर्निंग' में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया है कि लड़के और लड़कियों के मस्तिष्क के विकास में कोई अंतर नहीं होता है। गणित के गूढ़ सूत्रों को समझने में लड़कियां लड़कों से कहीं पीछे नहीं हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि बच्चों में गणित का कौशल कैसे प्रभावित होता है।

अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता और इस अध्ययन के सह-लेखक एलिसा केर्सी ने कहा, 'यह महत्वपूर्ण बात है कि शारीरिक स्तर पर भले ही हम एक-दूसरे से काफी भिन्न दिखते हों लेकिन हममें कई समानताएं भी हैं।' अध्ययन में यह भी कहा गया है कि शैक्षिक वीडियो देखते समय लड़के और लड़कियां दोनों समान रूप से व्यस्त थे। केर्सी ने कहा, 'सिर्फ इतना ही नहीं कि लड़के और लड़कियां गणित की समस्याओं को हल करने के लिए एक जैसे तरीके अपनाते हैं, बल्कि इन समस्याओं को हल करने के लिए उनके मस्तिष्क में एक जैसी प्रक्रियाएं भी चलती हैं।'

इस शोध के लिए शोधकर्ताओं ने तीन से 10 साल तक की उम्र के 104 बच्चों (55 लड़कियां और 49 लड़कों) के मस्तिष्क की गतिविधियों को मापने के लिए शैक्षणिक वीडियो देखने के दौरान फंग्शनल एमआरआइ का अध्ययन किया और दोनों के मस्तिष्क की समानताओं का पता लगाया। शोधकर्ताओं की टीम ने बच्चों के मस्तिष्क की परिपक्वता का पता लगाने के लिए एमआरआइ के स्कैन की तुलना 63 वयस्कों के मस्तिष्क की गतिविधियों के स्कैन से की। इसके लिए उन्हें भी बच्चों की तरह शैक्षणिक वीडियो दिखाए गए। शोधकर्ताओं ने कहा, अध्ययन से पता चलता है कि गणित के मामले में बच्चों में समझ एक-सी ही रहती है और इसमें भिन्न आयुवर्ग और लैंगिक भेद कहीं नहीं देखने को मिलता।

समाज की वजह से पीछे हैं महिलाएं : कार्नेगी मेलन यूनिवसिर्टी की मुख्य शोधकर्ता जेसिका कैंटन ने कहा, 'समाज और संस्कृति की वजह से लड़कियां और महिलाएं विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्रों से दूर हैं।' उन्होंने कहा कि इसके अलावा पुरुषों की गणित बेहतर होने का कारण परिजनों का लड़कों के साथ खेलने में ज्यादा समय व्यतीत करना और स्कूलों में शिक्षकों द्वारा गणित की कक्षा के दौरान लड़कियों के मुकाबले लड़कों पर ज्यादा ध्यान देना हो सकता है। कैंटन ने कहा कि हो सकता है सभी जगह ऐसी परिस्थितियां न हों, पर यह लड़कियों के पिछड़ने का एक मुख्य कारण है। उन्होंने कहा कि यदि गणित के मामले में लड़कियों को भी आगे बढ़ना है तो हमें समाज और संस्कृति से परे सोचना और समझना होगा।

यह अध्ययन जर्नल 'साइंस ऑफ लर्निंग' में प्रकाशित हुआ है। प्रतीकात्मक

अध्ययन

▶ अमेरिका की कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किया दावा

▶ कहा- समान रूप से होता है दोनों के मस्तिष्क का विकास

नासा का पहला इलेक्ट्रिक विमान

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के आर्मस्ट्रांग फ्लाइंग रिसर्च सेंटर में नासा के पहले इलेक्ट्रिक विमान एक्स-57 मैक्सवेल का तकनीकी परीक्षण करते वैज्ञानिक। इस विमान से कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा, इसलिए इसे पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर विकल्प माना जा रहा है। रायटर

खास बातें

- इस प्लेन के निर्माण में 20 वर्ष का समय लगा
- इस विमान में चार लोग उड़ान भर सकते हैं
- इसमें 14 इलेक्ट्रिक क्रूजर मोटर्स का उपयोग किया है।
- भविष्य में इसका उपयोग अर्बन टैक्सी के रूप में किया जाएगा
- मार्केट में लाने से पहले सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड का पालन जरूरी
- पर्यावरण स्वच्छ रखने में मिलेगी मदद

क्यों खास है यह विमान

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का एक्स-57 विमान कई मायनों में खास हैं। इसमें रिचार्ज हो सकने वाली लिथियम-आयन बैट्री का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा वायु प्रवाह बढ़ाने के लिए विमान के पंखों के आसपास दर्जनों मोटर भी लगाएं गए हैं।

वाशिंगटन, आइएएनएस : अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने पूरी तरह बिजली से संचालित होने वाले अपने पहले विमान एक्स-57 मैक्सवेल का शुक्रवार को अनावरण किया। बीते दो दशकों में यह नासा का पहला ऐसा एक्स-विमान है, जिस पर लोग सवार हो सकेंगे। इस विमान का परीक्षण करीब एक साल बाद किया जाएगा।

इस विमान को इटली के टेकनाम पी2006टी विमान के अनुरूप बनाया गया है। कैलिफोर्निया स्थित इंपीरिकल सिस्टम एरोस्पेस (एसएरो) ने दो अक्टूबर को नासा को पूरी तरह बिजली से संचालित पहला प्रायोगिक एक्स-57 सौंपा था। आर्मस्ट्रांग फ्लाइट रिसर्च सेंटर में एसएरो ने विमान के कुल तीन कंफिग्रेशन के साथ डिलीवरी दी थी। नासा के अनुसार, एक्स-57 प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य तेजी से उभर रहे इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट बाजारों के प्रमाणन के लिए मानक तय करना है। इसके लिए नासा नियामक एजेंसियों को विमान का इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन केंद्रित डिजाइन भी साझा करेगी। नासा ने कहा कि ये विमान भविष्य में आम लोगों के लिए यातायात को और सुगम बनाएंगे।

चिंताजनक

अमेरिका के वुड्स होल ओशियनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन के शोधकर्ताओं ने किया अध्ययन, कहा- इस सदी के अंत तक 86 फीसद पक्षी हो सकते हैं विलुप्त

अंटार्कटिका से विलुप्त हो सकते हैं 'एम्परर पेंगुइन'

बोस्टन, प्रेट्र : लगातार बढ़ती गर्मी इस सदी के अंत तक 'एम्परर पेंगुइन' के विलुप्त होने का कारण बन सकती है। एक नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने चिंता जताते हुए कहा कि अंटार्कटिका में पाई जाने वाली पक्षियों की इस प्रजाति के लिए जलवायु परिवर्तन बेहद खतरनाक सिद्ध हो सकता है।

अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं की एक टीम ने कहा, एम्परर पेंगुइन पेंगुइन की सभी प्रजातियों में सबसे लंबा और भारी पक्षी होता है। जीवनयापन के लिए ये समुद्र पर निर्भर रहते हैं। आराम करने के लिए ये पक्षी समुद्री बर्फ के टुकड़ों का उपयोग करते हैं। शोधकर्ताओं की इस टीम में अमेरिका के वुड्स होल ओशियनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन (डब्ल्यूएचओआइ) के शोधार्थी भी शामिल थे।

करंट बायोलॉजी नामक जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया है कि यदि गर्मी लगातार बढ़ती रही और वर्तमान दर से अंटार्कटिका की बर्फ पिघलती रही तो एम्परर प्रजाति के पेंगुइन वर्ष 2100 तक 86 फीसद विलुप्त हो सकते हैं। इस स्थिति में पहुंचने के बाद इसकी आबादी बढ़ने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने दो कंप्यूटर मॉडलों का प्रयोग किया। जिसमें पहला- ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल अमेरिका के नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फियरिक रिसर्च (एनसीएआर) ने बनाया है, जो यह अनुमान लगाता है कि अलग-अलग जलवायु परिदृश्यों पर कहां और कब बर्फ पिघलेगी। जबकि दूसरा, पेंगुइन पॉपुलेशन मॉडल था, जो यह बताता है कि बर्फ के पिघलने पर इसकी कॉलोनी और रहने के तरीकों में क्या-क्या बदलाव आ सकते हैं। अध्ययन के मुताबिक, पेंगुइन विशिष्ट परिस्थितियों में विशेष तरीके से बर्फ पर अपनी कॉलोनियों का निर्माण करते हैं। इसके लिए जरूरी है कि बर्फ के टुकड़े समुद्र के नजदीक ही हों ताकि वे अपने बच्चों के लिए समय पर भोजन उपलब्ध करा सकें। अध्ययन में कहा गया है कि गर्मी बढ़ने से इनके बर्फ पिघल जाएगी और इनकी आवास नष्ट हो जाएंगे।

यह अध्ययन करंट बायोलॉजी नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ है। प्रतीकात्मक

प्रभावित होता है जीवनचक्र

डब्ल्यूएचओआइ के एक पारिस्थितिकीविज्ञानी और इस अध्ययन के सह-लेखक स्टेफनी जेनॉरियर ने कहा, 'पेंगुइन मॉडल के आंकड़े बताते हैं कि समुद्री बर्फ के पिघलने से एम्परर पेंगुइन का जीवन चक्र और मृत्यु दर प्रभावित होती है।' उन्होंने कहा, यदि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए समय रहते प्रयास नहीं किए गए तो आने वाले समय में अन्य जीवों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा।

सिकुड़ रही है पेंगुइन की कॉलोनी

इससे पहले हुए एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने दावा किया था बीते लगभग 37 वर्षों में एम्परर पेंगुइन की दुनिया की सबसे बड़ी कॉलोनी का आकार 88 फीसद तक सिकुड़ गया है। बता दें कि दक्षिणी महासागर द्वीप 'आल ऑक्स कोचंस' वर्ष 1960 से एम्परर पेंगुइन की दुनिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है। यहां पेंगुइन की इस प्रजाति की संख्या दुनिया में सबसे अधिक पाई जाती है।

मनुष्य की तरह अब एआइ भी ले सकेंगे रचनात्मक निर्णय

▶ अमेरिकी शोधकर्ताओं ने तैयार किया नया 'एजेंट', दावा-डिजाइन के क्षेत्र में लगाएगा बड़ा बदलाव

वाशिंगटन, एएनआइ : शोधकर्ताओं ने एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ) एजेंट विकसित किया है, जो मनुष्य की तरह कई प्रकार के डिजाइन गढ़ सकता है। शोधकर्ताओं का दावा है कि यह एआइ एजेंट डिजाइन के मामले में मनुष्यों की तरह रचनात्मक है और स्वयं निर्णय लेने में सक्षम है। इसका उपयोग बड़ी डिजाइन की समस्याओं को दूर करने के लिए किया जा सकता है।

आमतौर पर इंजीनियरों को जब किसी समस्या का समाधान करना होता है तो वे आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ) का उपयोग तो करते हैं, लेकिन इसमें एआइ के काम करने की सीमाएं निर्धारित होती। एक खास सेट के जरिये ही इंजीनियर समस्याओं का समाधान खोजते हैं, क्योंकि अब तक एआइ में ऐसी क्षमता नहीं होती थी कि वह मनुष्यों की तरह जरूरत के मुताबिक नई रणनीतियां तय कर सके। शोधकर्ताओं ने कहा, 'एआइ के नए एजेंट में अब ऐसी क्षमताएं हैं कि वह बड़ी से बड़ी डिजाइन की समस्याओं को भी आसानी से दूर कर सकता है और कई मामलों में मनुष्यों से भी बेहतर डिजाइन तैयार कर सकता है।'

यह अध्ययन 'एसएमई जर्नल ऑफ मैकेनिकल डिजाइन' में प्रकाशित हुआ है। इस अध्ययन में एक ऐसे एआइ फ्रेमवर्क के बारे में बताया गया है जो बिना किसी स्पष्ट जानकारी, पूर्वाग्रह और मार्गदर्शन के नए डिजाइन बनाने के लिए मानव डाटा का अवलोकन कर नई डिजाइन बनाने की रणनीतियों को सीखता है। इस अध्ययन का सह-लेखन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर और कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के अंतरिम डीन जोनाथन कॉगन, पीएचडी के शोधकर्ता आयुष रैना और पेंसिलवेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग डिजाइन के असिस्टेंट प्रोफेसर क्रिस मैककोम ने किया है।